चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 16 जनवरी–22 जनवरी 2012 | मूल्य 5 रुपये

अखिलेश-शिवपाल में ठनी रार

पेज-3

मायावती को सत्ता विरोधी लहर का ख़ौफ़

पेज-4

भाजपा और कांग्रेस में बगावत के आसार

पेज-5

जान देंगे ज़मीन नहीं

पेज-6

यह सेना की इज़्ज़त का सवाल है

सभी फोटो–**प्रभात पाण्डेय**

मनीष कुमार

देश के सर्वोच्च न्यायालय में सेना और सरकार आमने-सामने हैं. आज़ादी के बाद भारतीय सेना की यह सबसे शर्मनाक परीक्षा है, जिसमें थल सेनाध्यक्ष की संस्था को सरकार दाग़दार कर रही है. पहली बार सेनाध्यक्ष और सरकार के बीच विवाद का फ़ैसला अदालत में होगा. विवाद भी ऐसा, जिसे सुनकर दुनिया भर में भारत की हंसी उड़ रही है. यह मामला थल सेनाध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह की जन्मतिथि का है. इस मामले में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के सामने है. वहां क्या होगा, यह पता नहीं, लेकिन इस विवाद को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे समझना ज़रूरी है. चौथी दुनिया ने इस विवाद पर तहक़ीक़ात की. क़रीब छह महीने पहले हमने इस विवाद से जुड़े सारे तथ्यों को सामने रखा, सारे दस्तावेज़ पेश किए. सारे तथ्य और सबूत इस बात को साबित करते हैं कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है, लेकिन सरकार ने इस तथ्य को ठुकरा दिया और उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1950 मान ली. सरकार की इस ज़िद का राज़ क्या है. सरकार क्यों देश के सर्वोच्च सेनाधिकारी को बेइज़्ज़त करने पर तुली है, जबकि यह बात दिन के उजाले की तरह साफ़ है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है. साक्ष्य इतने पक्के हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तीन-तीन भूतपूर्व चीफ जस्टिस ने अपनी राय जनरल वी के सिंह के पक्ष में दी है. इसके बावजूद अगर विवाद जारी है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है.

एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनरल वी के सिंह ने ही अपनी जन्मतिथि का विवाद उठाया है. मीडिया झूठी ख़बर दिखा रहा है कि जनरल वी के सिंह अपनी जन्मतिथि को बदलना चाहते थे. यह विवाद जनरल वी के सिंह ने नहीं उठाया. हक़ीक़त यह है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि को लेकर कभी कोई विवाद ही नहीं था. जबसे वह सेना में आए, तबसे 36 साल तक सेना के आधिकारिक दस्तावेज़ों, प्रोमोशन और हर जगह उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1951 ही है. जब जनरल वी के सिंह थल सेनाध्यक्ष बने, उस समय ऐसी ख़बरें आम थीं कि देश भर में सेना की ज़मीन की लूट हो रही है. देश के अलग-अलग इलाक़ों से सेना की ज़मीनों पर अवैध निर्माण या उनके बिक जाने की ख़बरें टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया में लगातार आती थीं. सेना के अधिकारी और भू-माफ़िया मिलजुल कर इस काम को अंजाम दे रहे थे. सुकना ज़मीन घोटाला सामने आया. इस घोटाले में पूर्व मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश का नाम आया. उस वक़्त वह तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर के प्रमुख सलाहकारों में थे. सुकना ज़मीन घोटाले पर जनरल वी के सिंह ने अपनी रिपोर्ट दी. लगा कि सेना की ज़मीन का सौदा करने वाले अधिकारियों को सज़ा मिलेगी, लेकिन जनरल कपूर ने ख़ुद से कोई एक्शन नहीं लिया. हक़ीक़त यह है कि चंद सैन्य अधिकारी भू-माफ़ियाओं के साथ मिलकर सेना की ज़मीनों का बंदरबांट कर रहे थे. वी के सिंह के आते ही यह गोरखधंधा बंद हो गया. जनरल वी के सिंह ने सेना की प्रतिष्ठा वापस दिलाई और भ्रष्टाचार को रोका. ऐसी क्या बात है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि का विवाद तब उठाया गया, जब अवधेश प्रकाश का नाम सुकना ज़मीन घोटाले में उजागर हुआ.

यह विवाद जनरल वी के सिंह ने नहीं, बल्कि मिलिट्री के सेक्रेटरी ब्रांच ने शुरू किया है. वह भी तब, जबकि जनरल वी के सिंह 36 सालों तक सेना को अपनी सेवाएं दे चुके थे. पूरे 36 सालों तक उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1951 ही रही. सवाल यह उठता है कि किसी भी सैनिक की जन्मतिथि के रिकॉर्ड को रखने की ज़िम्मेदारी किसकी है और कौन सा रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से मान्य है. क़ानून के मुताबिक़, यह काम मिलिट्री की एडजूटैंट ब्रांच का है. सरकार को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि उसने एडजूटैंट ब्रांच के रिकॉर्ड को तरजीह क्यों नहीं दी, जबकि यही आधिकारिक रूप से मान्य है. सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इस विवाद में सेक्रेटरी ब्रांच की बात को सच मान रही है, जिसका काम अधिकारियों का रिकॉर्ड रखना नहीं है.

कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि उन्होंने एनडीए के फॉर्म में अपनी जन्मतिथि 10 मई, 1950 दर्ज कराई थी, इसीलिए उनकी जन्मतिथि यह बताई जा रही है. हक़ीक़त यह है कि जब वह एनडीए में शामिल हुए, तब उनकी उम्र 15 साल थी. मतलब यह कि वह नाबालिग थे. किसी नाबालिग द्वारा भरे गए फॉर्म का क़ानून में कोई स्थान नहीं है. क़ानून के मुताबिक़, जब कोई नाबालिग किसी दस्तावेज़ को पेश करता है तो उसे पर्याप्त सबूत पेश करना पड़ता है. क़ानून की नज़र में जन्मतिथि का सबसे बड़ा सबूत दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट माना जाता है. जनरल वी के सिंह के हाईस्कूल सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1951 दर्ज है. जनरल वी के सिंह का सर्टिफिकेट दो-तीन सालों के बाद एनडीए में जमा किया गया, क्योंकि उस ज़माने में स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट बनने में इतना समय लग जाता था. इसके बाद से उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1951 हो गई. 1997 में एडजूटैंट जनरल ब्रांच ने लिखकर दिया कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है. 2007 में भी एडजूटैंट जनरल ब्रांच ने फिर यह बताया कि उनकी सही जन्मतिथि 10 मई, 1951 है.

मीडिया में एक ख़बर फैलाई जा रही है कि जनरल वी के सिंह ने 24 जनवरी, 2008 को यह मान लिया था कि उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1950 है. जबकि यह मामला कुछ और ही है. चौथी दुनिया इस विवाद के पहले ही यह जानकारी दे चुका है कि तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष दीपक कपूर ने वी के सिंह पर यह दबाव डाला था कि वह एक सहमति पत्र लिखकर दें, नहीं तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है और जनरल वी के सिंह ने यह लिखकर दे दिया था कि ऐज डायरेक्टेड बाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आई एक्सेप्ट. जनरल वी के सिंह का अंबाला से कलकत्ता ट्रांसफर हो गया. उन्होंने फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पत्र लिखा कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझसे कहा कि आप मेरे मामले को क़ानून मंत्रालय भेज रहे हैं. आप पर चीफ के नाते मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन आपने वायदे के हिसाब से जो कहा था, वह नहीं किया. एथिकली और लॉजिकली यह सही नहीं है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वह पत्र रख लिया, जवाब नहीं दिया. जब जनरल वी के सिंह मिलने गए तो जनरल दीपक कपूर ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम चीफ बनना तो ख़ुद ठीक करा लेना अपनी जन्मतिथि. जनरल वी के सिंह चुपचाप वापस चले आए. अब सरकार उसी पत्र को एक सबूत के रूप में पेश कर रही है.

सरकार की नाराज़गी की कई वजहें हैं. भारतीय सेना एक ट्रक का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम है टेट्रा ट्रक. भारतीय थलसेना टेट्रा ट्रक का इस्तेमाल मिसाइल लांचर की तैनाती और भारी-भरकम चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करती है. इन ट्रकों का पिछला ऑर्डर फरवरी, 2010 में दिया गया था, लेकिन ख़रीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं तो आर्मी चीफ वी के सिंह ने इस सौदे पर मुहर लगाने से इंकार कर दिया. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल लिमिटेड को जिस वक़्त इन ट्रकों की आपूर्ति का ठेका मिला, तब भारतीय सेना की कमान जनरल दीपक कपूर के हाथ में थी. नियमों के मुताबिक़, हर साल आर्मी चीफ को इस डील पर साइन करने होते हैं, लेकिन रिश्वतखोरी से लेकर मानकों के उल्लंघन तक की शिकायतों की वजह से जनरल वी के सिंह ने साइन नहीं किए. क़ानून के मुताबिक़, टेट्रा ट्रकों की ख़रीददारी सीधे कंपनी से होनी चाहिए, लेकिन बीईएमएल ने यह ख़रीददारी टेट्रा सिपॉक्स (यूके) लिमिटेड से की, जो न

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनरल वी के सिंह ने ही अपनी जन्मतिथि का विवाद उठाया है. मीडिया झूठी ख़बर दिखा रहा है कि जनरल वी के सिंह अपनी जन्मतिथि को बदलना चाहते थे. यह विवाद जनरल वी के सिंह ने नहीं उठाया. हक़ीक़त यह है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि को लेकर कभी कोई विवाद ही नहीं था.

जनरल वी के सिंह ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पत्र लिखा कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझसे कहा कि आप मेरे मामले को क़ानून मंत्रालय भेज रहे हैं. आप पर चीफ के नाते मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन आपने वायदे के हिसाब से जो कहा था, वह नहीं किया. एथिकली और लॉजिकली यह सही नहीं है.

सरकार की नाराज़गी की कई वजहें हैं. भारतीय सेना एक ट्रक का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम है टेट्रा ट्रक. भारतीय थलसेना टेट्रा ट्रक का इस्तेमाल मिसाइल लांचर की तैनाती और भारी-भरकम चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करती है. इन ट्रकों का पिछला ऑर्डर फरवरी, 2010 में दिया गया था, लेकिन ख़रीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं तो आर्मी चीफ वी के सिंह ने इस सौदे पर मुहर लगाने से इंकार कर दिया.

मुख्यमंत्री मायावती का बाबुओं के साथ पहले जैसा ही रिश्ता है. ख़ासकर उन बाबुओं के साथ, जिन्हें मायावती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

उड़ीसा सरकार की विभेदकारी नीति

हाल में हुए हाउसिंग घोटाले में नेताओं और बाबुओं का नाम आना उड़ीसा सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, लेकिन यह तो मात्र एक उदाहरण है, क्योंकि ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है. इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसी अन्य कारण से परेशानी में हैं. उड़ीसा सरकार विकलांगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है. उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने विकलांगों के नौकरी के अधिकार को अस्वीकार करके उनके साथ अन्याय किया है. सूत्रों के अनुसार, उड़ीसा के विकलांगों राज्य सिविल सेवा में अपने लिए आरक्षण की मांग की है. वे सिविल सेवा में तीन फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जैसा कि केंद्र में दिया जाता है, लेकिन उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने तीन फीसदी की मांग नकार दी है. उसका कहना है कि ओपीएससी एक्ट में विकलांगों के लिए तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान नहीं है. ओपीएससी (उड़ीसा लोक सेवा आयोग) के विशेष सचिव एल एन मिश्रा का कहना है कि आयोग इस मांग पर विचार कर रहा है, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं राजस्थान जैसे राज्यों में विकलांगों के लिए इतना आरक्षण है. अब देखना यह है कि ओपीएससी कब तक इस पर विचार कर पाता है.

लोकायुक्त की पारदर्शिता

लोकायुक्त आजकल काफी चर्चा में हैं. बंगलुरू में जब लोकायुक्त ने एक ही दिन तीन आईएएस अधिकारियों सिदैयाह, एम वी वीरभद्रैया एवं मोहम्मद ए सादिक के घरों पर छापा मारा तो वहां काम कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता चकित हो गए. सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक की भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं भी दूसरे राज्यों से अलग नहीं हैं. उन्हें भी पूरी तरह पाक-साफ नहीं कहा जा सकता है. पिछले दस सालों में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने करीब 2400 बाबुओं को पकड़ा है, जिसमें केवल पांच आईएएस एवं छह आईपीएस अधिकारी थे. इसीलिए यह कहा जा सकता है कि आखिर इस बार पड़े छापों से कई लोगों को आश्चर्य क्यों हुआ. सूत्रों का कहना है कि लोकायुक्त के अंदर भी पारदर्शिता नहीं है. हालांकि सरकार के सभी अधिकारियों को अपनी संपत्तियों की घोषणा करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी लोकायुक्त पुलिस प्रमुख सत्य नारायण राव एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक अरुण चक्रवर्ती ने इस आदेश का पालन अभी तक नहीं किया है, लेकिन हाल की यह घटना परिवर्तन की ओर इशारा करती है.

मायावती और बाबू

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक गतिविधियों के चलते वहां अन्य कामों पर ग्रहण लग गया है, लेकिन चुनावी कोलाहल में भी बाबुओं का काम उसी तरह चल रहा है, जैसे पहले चलता था. मुख्यमंत्री मायावती का बाबुओं के साथ पहले जैसा ही रिश्ता है. ख़ासकर उन बाबुओं के साथ, जिन्हें मायावती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है. गत सितंबर में प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रोमिला शंकर, जो एनसीआर क्षेत्र में आयुक्त के पद पर काम कर रही थीं, को बहन जी की बात न मानने की वजह से निलंबित होना पड़ा था. सूत्रों का कहना है कि प्रोमिला शंकर ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके अनुसार उनका निलंबन बढ़ाया गया है. प्रोमिला का कहना है कि किसी भी अधिकारी को 45 दिनों से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है, अगर इस दौरान उसके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है. अब देखना यह है कि मायावती क्या जवाब देती हैं.

dilipcherian@gmail..com

यह सेना की इज़्ज़त का सवाल है

पृष्ठ एक का शेष

तो स्वयं उपकरण बनाती है और न उपकरण बनाने वाली कंपनी की सब्सिडियरी है. उपकरण बनाने वाली मूल कंपनी का नाम है टेट्रा सिपॉक्स एएस, जो स्लोवाकिया की कंपनी है.

दरअसल, बीईएमएल द्वारा टेट्रा ट्रकों की ख़रीद का पूरा मामला संदेह के घेरे में है. एक अंग्रेजी अख़बार डीएनए के मुताबिक़, रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक दिए गए कुल ठेकों में भारी धनराशि बतौर रिश्वत दी गई है. डीएनए के मुताबिक़, यह पूरा रैकेट 1997 से चल रहा है. बीईएमएल में उच्च पद पर रह चुके एक पूर्व अधिकारी के हवाले से यह भी ख़बर आई कि अभी तक कंपनी टेट्रा ट्रकों की डील से जुड़ा कुल 5,000 करोड़ रुपये तक का कारोबार कर चुकी है. यह कारोबार टेट्रा सिपॉक्स (यूके) लिमिटेड के साथ किया गया है. इसे स्लोवाकिया की टेट्रा सिपॉक्स एएस की सब्सिडियरी बताया जाता रहा है. बीईएमएल के इस पूर्व अधिकारी के मुताबिक़, 5,000 करोड़ रुपये के इस कारोबार में 750 करोड़ रुपये बीईएमएल एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बतौर रिश्वत दिए गए. बात यहीं ख़त्म नहीं होती है. बीईएमएल के एक शेयरधारक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के एस पेरियास्वामी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप और सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं. वह कहते हैं, ख़रीद के लिए जितनी रकम की मंजूरी दी जाती है, उसका कम से कम 15 फ़ीसदी हिस्सा कमीशन में चला जाता है. ऊपर से नीचे तक सबको हिस्सा मिलता है. मैंने 2002 में कंपनी की एजीएम में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की गई. एक प्रतिष्ठित बिजनेस अख़बार ने यहां तक लिखा कि बीईएमएल की टेट्रा ट्रकों की डील को कारगर बनाने में जुटी हथियार विक्रेताओं की लॉबी ने आर्मी चीफ को आठ करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश भी की थी, जिसे जनरल वी के सिंह ने ठुकरा दिया.

ट्रकों की संदेहास्पद डील को लेकर 8 मई, 2005 को मीडिया में ख़बर आई थी. डीएनए अख़बार ने एक और ख़ुलासा किया कि टेट्रा सिपॉक्स (यूके) लिमिटेड की स्थापना 1994 में ब्रिटेन में हुई थी. जोजफ मजिस्की और वीनस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसके शेयर होल्डर थे. स्लोवाकिया के न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक़, टेट्रा सिपॉक्स एएस 1998 में अस्तित्व में आई. इसका मतलब यह हुआ कि 1997 में बीईएमएल ने ऐसी कंपनी की सब्सिडियरी के साथ समझौता किया, जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी. टेट्रा सिपॉक्स (यूके) की शेयर होल्डिंग में कई बार बदलाव हुआ, लेकिन स्लोवाक कंपनी के पास कभी इसका एक शेयर भी नहीं रहा. बीईएमएल के चेयरमैन वी आर एस नटराजन के मुताबिक़, इंग्लैंड के वेक्ट्रा ग्रुप के पास टेट्रा कंपनियों का स्वामित्व है. वेक्ट्रा ग्रुप के चेयरमैन रविंदर ऋषि हैं. वेक्ट्रा ग्रुप के पास ही टेट्रा सिपॉक्स (यूके) का भी मालिकाना हक़ है. टेट्रा चेक कंपनी के भी बहुमत शेयर वेक्ट्रा ग्रुप के पास हैं. अब सवाल यह उठता है कि क्या आर्मी चीफ पर इसलिए पद छोड़ने का दबाव है, क्योंकि उन्होंने टेट्रा डील पर दस्तख़त नहीं किए थे? क्या बीईएमएल सेकेंड हैंड ट्रकों का आयात कर रही है और क्या स्लोवाकिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गया है? क्या पुराने ट्रकों की मरम्मत को घरेलू उत्पादन के तौर पर दिखाया जा रहा है? रविंदर ऋषि कौन है, उसे इतने रक्षा सौदों का ठेका क्यों दिया जा रहा है? इस लॉबी के लिए सरकार में काम करने वाले लोग कौन हैं? अगर सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती है तो इसका मतलब यही है

कि आर्मी चीफ को ठिकाने लगाने के लिए माफ़िया और अधिकारियों ने मिलजुल कर जन्मतिथि का बहाना बनाया है.

इसके अलावा जनरल वी के सिंह ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक प्लान तैयार किया, यह प्लान डिफेंस मिनिस्ट्री में लटका हुआ है. उन्होंने इस बीच कई ऐसे काम किए, जिनसे आर्म्स डीलरों और बिचौलियों की नींद उड़ गई. सिंगापुर टेक्नोलॉजी से एक डील हुई थी. इस कंपनी की राइफल को टेस्ट किया गया, उसके बाद जनरल वी के सिंह ने रिपोर्ट दी कि यह राइफल भारत के लिए उपयुक्त नहीं है. भारतीय सेना को नए और आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है. इस ज़रूरत को देखते हुए वह अगले एक-दो सालों में भारी मात्रा में सैन्य शस्त्र और नए उपकरण ख़रीदने वाली है. ख़ासकर, भारत इस साल भारी मात्रा में मॉडर्न असॉल्ट राइफलें ख़रीदने वाला है. भारत का सैन्य इतिहास यही बताता है कि आर्म्स डील के दौरान जमकर घूसखोरी और घपलेबाज़ी होती है. जनरल वी के सिंह सेना के अस्त्र-शस्त्रों की ख़रीददारी में पारदर्शिता लाना चाहते हैं. वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसमें सैनिकों को दुनिया के सबसे आधुनिकतम हथियार मिलें, लेकिन कोई बिचौलिया न हो और न कहीं किसी को दलाली खाने का अवसर मिले. जबसे वह सेनाध्यक्ष बने हैं, तबसे भारतीय सेना पर कोई घोटाले या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा. भ्रष्टाचार के जो पुराने मामले थे, उन्हें न सिर्फ़ निपटाया गया, बल्कि उन्होंने आदर्श जैसे घोटाले की जांच में एजेंसियों की मदद की. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के ज़मीन घोटाले में जनरल वी के सिंह ने मुस्तैदी दिखाई. सेना की कोर्ट ऑफ इनक्वायरी का गठन किया, जिसमें दो पूर्व सेनाध्यक्षों-जनरल दीपक कपूर और जनरल एन सी विज सहित कई टॉप अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया गया. इन सबका नतीजा यह हुआ कि आर्म्स डीलरों की लॉबी, अधिकारी, ज़मीन माफ़िया और ऐसे कई सारे लोग जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ लामबंद हो गए और उनकी जन्मतिथि के विवाद को हवा दी.

जनरल वी के सिंह ने एक और काम किया, जिसकी वजह से अधिकारियों को परेशानी हुई. यह मामला जवानों की यूनिफॉर्म यानी कपड़ों से जुड़ा है. पहले जो यूनिफॉर्म सप्लाई होती थी, वह आधे से ज़्यादा लोगों को फिट नहीं होती थी. जवानों को उनकी माप के मुताबिक़ कपड़े नहीं मिलते थे. उन कपड़ों को फिर से सिलवाने की ज़रूरत पड़ती थी. जनरल वी के सिंह ने इसे रोका. उन्होंने फ़ैसला लिया कि जवानों को मिलने वाले कपड़े अच्छी कंपनी के हों और हर सैनिक की माप लेकर सिलाई हो. जनरल वी के सिंह ने एक और फ़ैसला लिया, जो अधिकारियों को चुभ गया. उन्होंने सेना में मीट की सप्लाई करने वाले मीट कारटेल का सफ़ाया कर दिया, वे लोग जो मीट सप्लाई करते थे, वह ठीक नहीं था. जनरल वी के सिंह ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर की शुरुआत की, ताकि दुनिया का सबसे बेहतर मीट सेना के जवानों को मिले. जब जनरल वी के सिंह ने थल सेनाध्यक्ष का पद संभाला, उस वक़्त भारतीय सेना की साख दांव पर लगी थी. सेना के कई घोटाले उजागर हो चुके थे. अब तक ईमानदार समझे जाने वाले इस महकमे को लोग शक की निगाह से देखने लगे थे. सेना के लोग भी दबी ज़ुबान में कहने लगे थे कि कुव्यवस्था की वजह से उनकी स्थिति ख़राब होती जा रही है. ऊपर से पाकिस्तान की तरफ़ से घुसपैठियों का भारत में आना निरंतर जारी था. देश में नक्सली हमले हो रहे थे. सरकार नक्सलियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का मन बना रही थी. मतलब यह कि जनरल वी के सिंह के सामने कई चुनौतियां थीं. सेनाध्यक्ष बनते ही उन्होंने सेना में मौजूद भ्रष्टाचार और माफ़िया तंत्र को ख़त्म करना शुरू कर दिया. लगता है, यह बात नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठे अधिकारियों को ख़राब लगी. देश में सरकारी तंत्र कैसे चल रहा है, यह एक स्कूली बच्चे को भी पता है. लगता है, देश में जो ईमानदार और आदर्शवादी लोग हैं, उनके लिए सरकारी तंत्र में कोई जगह नहीं रह गई है. उन्हें ईनाम मिलने की जगह सज़ा दी जाती है और जलील किया जाता है.

क्या इस देश में अलग-अलग नागरिकों के लिए अलग-अलग क़ानून हैं या फिर यह मान लिया जाए कि इस देश को माफ़िया सरगना और सरकार में बैठे उनके दलाल चला रहे हैं. पूरे देश की जनता एक ऐसे घिनौने वाक्ये से रूबरू हो रही है, जिसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पिछले सात सालों में जिस तरह देश में संवैधानिक और राजनीतिक संस्थानों की बर्बादी हुई है, वैसी पहले कभी नहीं हुई. हैरानी की बात यह है कि सरकार एक तरफ़ यह कह रही है कि थल सेनाध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ़ वह उनसे डील भी करती है कि उन्हें किसी देश का राजदूत या किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा. यही नहीं, यह धमकी भी दी जा रही है कि अगर वह कोर्ट गए तो उन्हें सेनाध्यक्ष के पद से बर्ख़ास्त कर दिया जाएगा. जनरल वी के सिंह को कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि यह मामला सिर्फ़ जनरल वी के सिंह का नहीं है, यह उनकी जन्मतिथि के विवाद का मामला नहीं है, यह मामला देश के सर्वोच्च थलसेना अधिकारी नामक संस्था से जुड़ा है. सरकार जिस तरह इस संस्था पर कीचड़ उछाल रही है, वह इस देश के नागरिक-सैन्य रिश्ते, प्रजातंत्र और भविष्य के लिए घातक है. एक सच्चे सैनिक को हर हाल में लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए. इसलिए जनरल वी के सिंह को ख़ुद के लिए नहीं, बल्कि इस संस्था की गरिमा बचाने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए. अगर वह नहीं गए तो इसका मतलब यही है कि देश के माफ़िया, अधिकारी और नेता जब चाहें, गिरोह बनाकर भविष्य के सेनाध्यक्षों को नीचा दिखा सकते हैं, उन्हें मनचाहा काम कराने के लिए मजबूर कर सकते हैं. जनरल वी के सिंह लड़ रहे हैं, यह अच्छी बात है. हो सकता है, भविष्य में किसी दूसरे ईमानदार सेनाध्यक्ष के साथ फिर ऐसा हो, लेकिन वह जनरल वी के सिंह की तरह लड़ भी न सके.

manish@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

राजीव कपूर की डीओपीटी से विदाई

1983 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कपूर को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है. वह डीओपीटी में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे. डीओपीटी में संयुक्त सचिव बनाए जाने के लिए पैनल बनाए जा रहे हैं.

अनिल बने संयुक्त महानिदेशक

1985 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल श्रीवास्तव को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त महानिदेशक बनाया गया है. यह पद नवसृजित है.

संडन गृह मंत्रालय में रहेंगे

1982 बैच के आईएएस अधिकारी के संडन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. वह अभी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं और कश्मीर संबंधी मामले देख रहे हैं. इस विभाग में उनका कार्यकाल जनवरी 2012 में खत्म होने वाला था.

यशपाल अल्पसंख्यक मंत्रालय में

1984 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. यशपाल सिंह को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह भानु प्रताप शर्मा की जगह लेंगे.

गिरिधर संयुक्त सचिव बने

1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरमान गिरिधर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह अपूर्व चंद्र की जगह लेंगे, जिन्हें मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

शैलेष कोयला मंत्रालय पहुंचे

1991 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेष कुमार सिंह को कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह रजनीश कुमार महाजन की जगह लेंगे.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 45
दिल्ली, 16 जनवरी–22 जनवरी 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

धर्मेंद्र भी सांसद हैं और उनकी अति महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है. यह और बात है कि धर्मेंद्र और अखिलेश ऊपरी तौर पर काफ़ी क़रीबी नज़र आते हैं.

मुलायम सिंह का परिवार

अखिलेश-शिवपाल में ठनी रार

रूबी अरुण

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का यह नया चेहरा है, जहां नीतियों पर अलगाव है, टकराहट है, सत्ता हथियाने की लालसा है और पार्टी में वर्चस्व को लेकर अंदर ही अंदर सुलग रहा गुस्सा है. यह अखिलेश यादव का समाजवाद है, जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव के समाजवाद से बिल्कुल उलट है. मुलायम सिंह यादव ने किसी भी उतार-चढ़ाव में अपने जिस कुनबे को एक डोर में बांधे रखा था, उनका वही कुनबा अब बिखरने की कगार पर है. भाई शिवपाल सिंह यादव, बेटे अखिलेश यादव और पत्नी साधना गुप्ता की ख्वाहिशों के दरम्यान समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव की बोलती बंद हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में जीत का सेहरा किस पार्टी के सिर बंधेगा, इस पर फ़िलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह के घर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर रार ठन चुकी है. इसी बीच मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता अपने बेटे प्रतीक यादव और बहू को भी चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति बनाने में जुट गई हैं. उधर मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव भी चाचा मुलायम से बेहद नाराज़ हैं, हालांकि धर्मेंद्र ने अपने गुस्से के गुबार को दबा रखा है, पर वह अक्सर इस बात की झल्लाहट अपने क़रीबियों के बीच निकलते देखे-सुने जाते हैं कि मुलायम सिंह पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं और उन्होंने अपनी पूरी ताक़त अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने में झोंक दी है.

धर्मेंद्र भी सांसद हैं और उनकी अति महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है. यह और बात है कि धर्मेंद्र और अखिलेश ऊपरी तौर पर काफ़ी क़रीबी नज़र आते हैं. फिर भी धर्मेंद्र मौन हैं तो इसकी बड़ी वजह है, उन्हें मौके का इंतज़ार है. वैसे प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तब धर्मेंद्र की सरकार में ख़ूब धमक रहती थी. अखिलेश को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे मुलायम सिंह से उनका दूसरा बेटा प्रतीक भी नाराज़ है. वैसे प्रतीक ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन उसकी मां साधना उसे उसका हक़ दिलाने के लिए काफ़ी उत्सुक और लालायित हैं. प्रतीक फ़िलहाल तक राजनीति से दूर थे, लेकिन उनकी शादी के बाद मां साधना ने उनकी ख्वाहिशों को परवान चढ़ाया. साधना गुप्ता चाहती हैं कि जिस तरीके से नेता जी ने अखिलेश को राजनीति में आगे बढ़ाया, उसी तरह वह प्रतीक का भी करियर संवारें. हालत यह है कि मुलायम सिंह के परिवार के सभी सदस्य यह आस लगाए बैठे हैं कि परिवार सत्ता में आए और वही मुख्यमंत्री बन जाएं.

इन सब सुगबुगाहटों को दरकिनार कर अखिलेश यादव अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पार्टी और विचारधारा को धार देने में लगे हैं. अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह अपने त्वरित और कठोर फ़ैसलों के ज़रिए सबको यह समझाने में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में वही होगा, जो यहां का अध्यक्ष चाहेगा. अखिलेश यादव के इस रवैये से घर ही नहीं, पार्टी के अंदर भी कई गुट बन चुके हैं, जो अखिलेश से होने वाली किसी बड़ी चूक का इंतज़ार कर रहे हैं. पिछले दिनों तक जिन लोगों को मुलायम सिंह मान-सम्मान देते थे, उन्हें आज अखिलेश समाजवाद का नया फलसफ़ा समझाने में लगे हैं. जो इस रास्ते में अखिलेश के सामने रोड़ा बन रहा है, उसे मुंह की खानी पड़ रही है. अब वह चाहे चाचा शिवपाल सिंह यादव हों या कभी पार्टी की बेहद अहम शख्सियत रहे आज़म खान हों या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद गंवा चुके मोहन सिंह हों. सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़म ठोके बैठा है, तो वह हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव. जब मुलायम सिंह ने अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब शिवपाल को यह खराब तो बहुत लगा, पर हालात देखते हुए वह ख़ामोश रहे. इसके बाद समाजवादी पार्टी की कमान संभालते ही अखिलेश यादव ने युवाओं को जोड़ने की मुहिम शुरू की. लोग अखिलेश की तुलना कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से करने लगे. अखिलेश यादव ने अपने क्रांति रथ के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा ही इसलिए किया, ताकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का प्रभाव कुछ कम हो सके. बावजूद इसके, मतदान से पहले ही पार्टी का एक धड़ा शिवपाल सिंह यादव की वकालत कर रहा है, वहीं दूसरा खेमा अखिलेश यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाने पर तुला हुआ है.

अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह अपने त्वरित और कठोर फ़ैसलों के ज़रिए सबको यह समझाने में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में वही होगा, जो यहां का अध्यक्ष चाहेगा. अखिलेश यादव के इस रवैये से घर ही नहीं, पार्टी के अंदर भी कई गुट बन चुके हैं, जो अखिलेश से होने वाली किसी बड़ी चूक का इंतज़ार कर रहे हैं.

मुलायम सिंह यादव की दखलंदाज़ी के बाद भी यह खेमेबाज़ी बढ़ती ही जा रही है. दरअसल, शिवपाल सिंह से त्रस्त कुछ पार्टीजनों ने अखिलेश को यह समझा दिया है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, इसमें तो केवल सत्ता हासिल करना ही मक़सद और मूल मंत्र होता है. बस यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ. अखिलेश यादव को लगा कि अब उन्हें अपनी महत्ता और शक्ति दोनों ही साबित करनी होगी. अखिलेश ने शिवपाल सिंह यादव के फ़ैसलों को खुलेआम नकारना शुरू कर दिया. कानपुर में शिवपाल सिंह यादव ने मायावती के सबसे क़रीबी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के भाई हसीउद्दीन सिद्दीक़ी को अपने सामने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई. इस बात से बसपा खेमे में हड़कंप मच गया. शिवपाल सिंह यादव के इस क़दम की सराहना होने लगी. तब अखिलेश यादव के क़रीबी लोगों ने उन्हें समझाया कि इससे तो शिवपाल सिंह यादव के क़द और प्रतिष्ठा दोनों में ही बढ़ोत्तरी हो जाएगी. बस फिर क्या था, मारे उत्साह के, बग़ैर कुछ सोचे-समझे अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि हसीउद्दीन सिद्दीक़ी समाजवादी पार्टी में नहीं हैं. अखिलेश के इस क़दम से शिवपाल सिंह तिलमिला गए और उन्होंने इस बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया. शिवपाल सिंह ने तुरंत पलट वार करते हुए घोषणा की कि हसीउद्दीन को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है और वह पार्टी में ही हैं.

बात बढ़ती, उसके पहले ही मुलायम सिंह ने भाई-भाई का हवाला देकर मामला रफ़ा-दफ़ा करा दिया. ज़ाहिर है, मुलायम सिंह की इस कोशिश ने अखिलेश को और भी बेबाक़ कर दिया. अखिलेश इतने मुखर हो चुके हैं कि वह पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को उनकी हैसियत बताने में एक पल नहीं लगाते. आज़म खां जैसे दबंग और कद्दावर नेता को भी उनकी जगह बताने में अखिलेश को गुरेज़ नहीं. आजम खां ने अपने घर में डी पी यादव को बुलाकर घोषणा की कि डीपी यादव उनके साथ हैं. डी पी यादव ने भी कहा कि उन्होंने नेता जी से अपने मतभेद दूर कर लिए हैं और अब वह समाजवादी पार्टी के सैनिक बनकर उसके लिए काम करेंगे. पर अखिलेश यादव को यह बात बेहद नागवार गुज़री कि उनसे पूछे बिना आज़म खां ने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया. लिहाज़ा अखिलेश ने चाचा शिवपाल सिंह की तरह आजम खां को भी पलट वार करते हुए निपटा दिया. उन्होंने कहा कि डी पी यादव सहित किसी भी अपराधी के लिए समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है. आज़म खां पहले तो उनके इस बयान पर हक्के-बक्के रह गए. उनकी समझ में नहीं आया कि जब मुलायम सिंह उनकी बात नहीं काट सकते, तो भला अखिलेश यादव उनकी मर्ज़ी को कैसे धत्ता बता सकते हैं. एकबारगी आज़म खां ने मुख़ालफ़त भी करनी चाही, पर पार्टी प्रवक्ता मोहन सिंह का हश्र देखकर वह चुप्पी साध गए. हालांकि डी पी यादव के ख़िलाफ़ मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र भी थे, क्योंकि डी पी यादव की नज़र उनके क्षेत्र बदायूं पर थी. वज़ह जो भी हो, पर आज़म खां के बारे में एक बात सबको मालूम है कि वह अपना अपमान जल्दी नहीं भूलते. वक़्त की नजाकत समझते हुए खुले तौर पर आज़म खां भले ही कुछ न कहें, पर मौका मिलते ही वह बल खाने से नहीं चूकते. आज़म खां के हिमायती भी अखिलेश के रवैये से नाराज़ होकर अलग घात लगाए बैठे हैं. ऐसे में प्रदेश की सत्ता पर क़ब्ज़ा करने का सपना लिए सियासी जंग लड़ रहे अखिलेश की राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि जो उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं, उनमें से ज़्यादातर उनके अपने हैं और इतिहास गवाह है कि ग़ैरों से तो आप निपट लेते हैं, पर अपनों की मुख़ालफ़त भारी पड़ जाती है.

ruby@chauthiduniya.com

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मायावती के खास बाबू सिंह कुशवाहा एवं अवध पाल जैसे नेताओं ने खूब किरकिरी कराई. दागी सांसद धनंजय सिंह के सितारे गर्दिश में रहे.

उत्तर प्रदेश

मायावती को सत्ता विरोधी लहर का ख़ौफ़

अजय कुमार

चुनाव आचार संहिता लागू होते ही मायावती राज और 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की मियाद ख़त्म हो गई. अब मायावती सिर्फ़ केयर टेकर (सीमित अधिकार) मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाएंगी. इस दौरान सरकार न कोई नीतिगत फ़ैसला ले पाएगी और न अधिकारियों–कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा. मायावती सरकार के कार्यकाल को कोई गोल्डन पीरियड बता रहा है तो कोई इसे भ्रष्ट और तानाशाह सरकार. पांच साल तक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोपों–प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा. मायावती अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं, लेकिन सत्ता विरोधी रुझान उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. अगर एक–दो प्रतिशत वोट भी बसपा के पाले से खिसक गया तो दोबारा सरकार बनाने का मायावती का सपना चकनाचूर होने में देर नहीं लगेगी. उन्हें इस बात का ख़तरा सता रहा है कि कहीं मुस्लिम मतदाता उनसे दूर न हो जाए. अपने पिछले तीन कार्यकालों के मुक़ाबले इस बार वह कुछ बदली–बदली ज़रूर नज़र आईं, लेकिन उनके इरादों में कोई बदलाव या भटकाव नहीं दिखा. सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वह सत्ता में आईं तो उन्होंने सबको गले लगाया, लेकिन दलितों के हित सर्वोपरि रहे. निकाय चुनाव के लिए विपक्ष से लेकर विभिन्न अदालतों तक ने कोशिश कर ली, लेकिन मायावती ने ठान लिया था, चुनाव नहीं हो पाए. केंद्र सरकार के साथ टकराव के चलते मायावती सरकार को दुधारी तलवार पर चलना पड़ा. उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी तक को सलाखों के पीछे भेजने में गुरेज नहीं किया. रीता के लखनऊ स्थित आवास पर आगजनी करने के आरोपी विधायक को उन्होंने सज़ा की जगह लालबत्ती थमा दी. पूरे कार्यकाल के दौरान विपक्ष मुख्यमंत्री एवं उनके सहयोगी मंत्रियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए लगातार हमलावर रहा, वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए विपक्षी दलों के सियासी समीकरण बिगाड़ने के लिए हरसंभव कोशिश की. सरकार की तरफ़ से सर्वजन हिताय–सर्वजन सुखाय की बात तो की गई, लेकिन बसपा जातीय राजनीति से ऊपर नहीं उठ नहीं पाई. वह दलितों को अपने पाले में बनाए रखने और मुसलमानों को ख़ुश करने के लिए लगातार कोशिशें करती रही. राहुल जब भी दलितों के घर जाते, मायावती उन्हें ख़ूब खरी–खोटी सुनातीं. कांग्रेस के पास जब सेनानी कम पड़े तो उसने दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को मैदान में उतार दिया. मध्य प्रदेश से दूर किए गए दिग्गी को जनता उनके विवादित बयानों से जानने लगी. मायावती ने चार साल तक अपने हिसाब से काम किया, लेकिन अंतिम साल में वह पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गईं. सूबे को चार हिस्सों में बांटने जैसे अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आनन–फानन में पारित कराकर मायावती ने एक नई जंग छेड़ दी. मायावती के लिए यह कार्यकाल मुश्किलों भरा रहा, कई मंत्रियों को लोकायुक्त की जांच के बाद पद गंवाना पड़ा. लोकायुक्त द्वारा साल के अंत तक दो दर्जन से अधिक मंत्रियों एवं क़रीब ढाई दर्जन विधायकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जारी रहने से भी सरकार की जान सांसत में रही. पांच साल विधायकों एवं मंत्रियों पर बलात्कार, हत्या और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देते–देते बीत गए.

कार्यकाल के अंतिम दौर में राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं. इस दौरान अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का आंदोलन भी छाया रहा, जिसका रुख़ मायावती ने कांग्रेस की तरफ़ मुड़ा रहने दिया. दो–ढाई साल से राहुल गांधी ने प्रदेश में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराई. वह पुलिस–किसान संघर्ष के गवाह बने ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल जा पहुंचे, जहां निषेधाज्ञा के उल्लंघन में गिरफ्तार कर लिए गए. मिशन–2012 के मद्देनज़र राहुल ने किसान जागरण यात्रा की और किसान महापंचायत के लिए समर्थन जुटाया. राहुल ने अपनी रैलियों में जनता के बीच मायावती सरकार की छवि नोट खाने वाले हाथी के रूप में बनाने की कोशिश की. विकास कार्यों के लिए ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किसानों के आंदोलन के चलते राज्य सरकार ने अधिग्रहण संबंधी नई नीति बनाई. नोएडा में अदालत ने अनेक ज़मीनों का अधिग्रहण रद्द कर दिया, जिससे वहां निवेश करने वालों को झटका लगा. बसपा सरकार की चौथी पारी घोटालों के नाम रही. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) और जननी सुरक्षा योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं में कथित अनियमितताएं चर्चा का विषय रहीं. स्वास्थ्य महानिदेशक बच्ची सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया. इसके बाद मुख्य चिकित्साधिकारी (परिवार कल्याण) डॉ. बी पी सिंह की हत्या और एनआरएचएम घोटाले के अभियुक्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाई एस सचान की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु जैसी सनसनीखेज घटनाएं हुईं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में माफ़िया तत्वों की पैठ का एहसास कराया. एनआरएचएम और स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं के आरोपों के चलते सरकार के दो काबीना मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा और अनंत मिश्र को पद छोड़ना पड़ा. मायावती की पत्र राजनीति भी चर्चा का विषय रही. कभी बुंदेलखंड, कभी पैकेज तो कभी आरक्षण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे. इतने पत्र आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिखे. चुनाव नज़दीक आते देख उन्होंने विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए केंद्र को कई पत्र लिखे. चुनाव से पहले विरोधियों के सियासी समीकरण बिगाड़ने के लिए सरकार ने राज्य विधान मंडल में उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने संबंधी प्रस्ताव मात्र 16 मिनट में पारित करा दिया. राज्य विधान मंडल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मायावती सरकार को पत्र लिखकर कुछ बुनियादी सवाल पूछे. इस पर मायावती ने उसे संविधान का उल्लंघन बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सूबे के विभाजन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है. बसपा को अपने कई विधायकों की हरकतों की वजह से शर्मसार होना पड़ा. बसपा नेता उमाकांत यादव को जेल भेजकर मायावती ने जो वाहवाही लूटी, उसे विधायक आनंद सेन यादव, शेखर तिवारी, गुड्डू पंडित एवं पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी ने अपने कारनामों से खो दिया.

मायावती के खास बाबू सिंह कुशवाहा एवं अवध पाल जैसे नेताओं ने ख़ूब किरकिरी कराई. दागी सांसद धनंजय सिंह के सितारे गर्दिश में रहे. एनआरएचएम घोटाला उजागर होने के बाद इस्तीफ़ा देने वाले कुशवाहा को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं कुछ ताक़तवर नौकरशाहों पर आरोप लगाने की वजह से बसपा से निकाल दिया गया. मायावती के परिवारीजन पहली बार विपक्ष के निशाने पर आए. भाजपा ने उनके भाई आनंद कुमार के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम छेड़ते हुए उन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनेक फ़र्ज़ी कंपनियां बनाकर घोटाले के 10 हज़ार करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप लगाया. मायावती के वफादार नौकरशाह इस बार भी चर्चा में रहे. शशांक शेखर की कैबिनेट सचिव पद पर तैनाती का विवाद अदालत तक पहुंचा, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा. फतेह बहादुर, डीजीपी बृजलाल एवं कैबिनेट सचिव शशांक शेखर पूरे कार्यकाल के दौरान मायावती की गुडबुक में रहे. इसी प्रकार सतीश मिश्र को लेकर कई अफवाहों ने जन्म लिया. कभी कहा गया कि उन्हें मायावती ने किनारे कर दिया है तो कभी कहा गया कि वह अपने परिवार को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आई. 2007 में चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली मायावती का आगाज़ जितना अच्छा था, अंजाम उतना ही ख़राब लग रहा है. मायावती के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, जिसके बल पर वह जनता से वोट की अपील करेंगी.

feedback@chauthiduniya.com

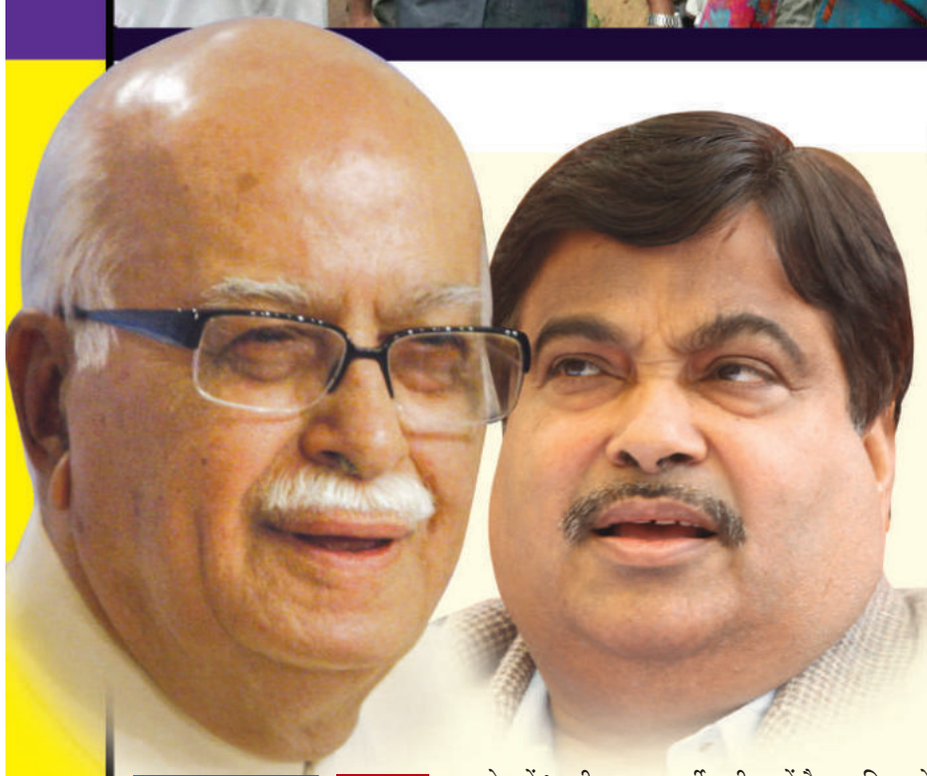

भाजपा मुसीबत में

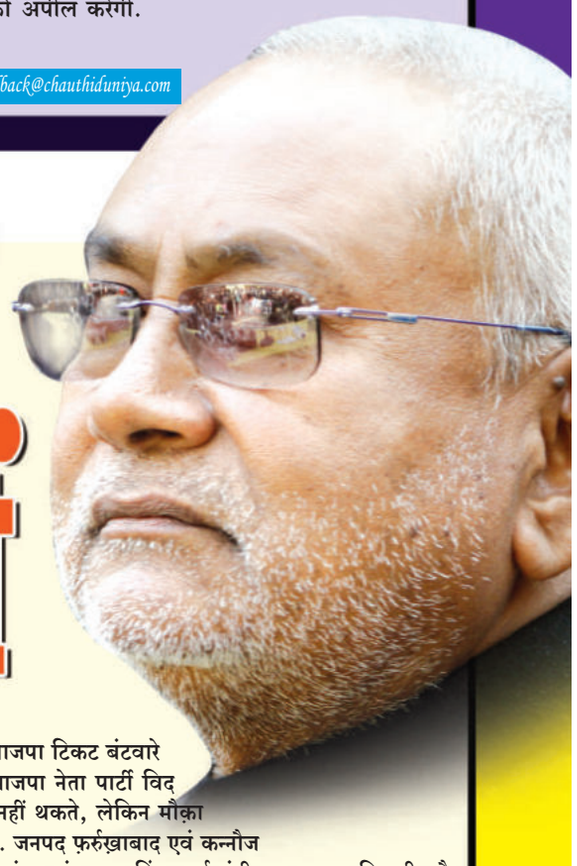

उम्मीदवारों को तलाश कर चुनावी समर जीतने की क़वायद में जुटी हैं, वहीं भाजपा टिकट बंटवारे में भेदभाव की नीति अपना कर ख़ुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है. भाजपा नेता पार्टी विद डिफरेंस का दंभ भरते हुए वंशवाद एवं परिवारवाद की आलोचना करते नहीं थकते, लेकिन मौक़ा मिलते ही वे इस बहती गंगा में हाथ धोने से ख़ुद को रोक नहीं पाते. जनपद फ़र्रुख़ाबाद एवं कन्नौज की सात विधानसभा सीटों पर पूर्व सांसद दयाराम शाक्य, पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह, पूर्व मंत्री राम प्रकाश त्रिपाठी और ब्रह्मदत्त दुबे के पुत्र–पुत्रियों को टिकट थमाए गए हैं.

फ़िरदौस ख़ान

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में है. इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के नेता हैं. एक तरफ़ जहां भाजपा बसपा सरकार से बर्ख़ास्त मंत्रियों को गले लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ़ जुझारू कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके वह एक बड़े तबक़े को नाराज़ कर रही है. भाजपा वैश्यों की पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन इस बार वैश्य समाज उससे नाराज़ है. नाराज़गी पार्टी के नेतृत्व को लेकर है, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में है. वैश्य समाज को मलाल है कि भाजपा वोट तो उससे लेती है, लेकिन संगठन या सत्ता में उसकी भागीदारी को कोई तरजीह नहीं देती. उसकी यह भी शिकायत है कि वैश्य नेताओं को पार्टी में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता. उन्हें लगता है कि पार्टी के सारे फ़ैसले ब्राह्मण नेता लेते हैं, जबकि ब्राह्मणों के वोट मायावती की बहुजन समाज पार्टी की झोली में जाते हैं. वैश्य समाज की यह नाराज़गी ग़लत नहीं है, क्योंकि उसकी दलीलों में सच्चाई दिखती है. अनुपमा जायसवाल बहराइच से भाजपा का टिकट चाहती थीं. वह पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं और उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत भी की, लेकिन पार्टी संगठन में मंत्री पद पर रही इस वैश्य महिला नेता का टिकट काटकर दद्दन मिश्रा को दे दिया गया, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री थे.

वैश्य समाज का आक्रोश कोई नया नहीं है. पिछले चुनाव में भाजपा ने जालौन के सर्वमान्य वैश्य नेता बाबूराम का टिकट काट दिया था, जिससे वैश्य समाज को काफ़ी झटका लगा था. बाद में उन्हें मनाने के लिए पार्टी के टिकट पर विधान परिषद भेजा गया, लेकिन वैश्य समाज की नाराज़गी दूर नहीं हो पाई. इस चुनाव में वैश्य समाज के साथ हो रहे भेदभाव का ख़ामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है. समाजवादी पार्टी वैश्य समाज की नाराज़गी से वाक़िफ़ है. इसलिए मुलायम सिंह यादव वैश्य समाज को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. वैश्य नेता नरेश अग्रवाल ने जब समाजवादी पार्टी का दामन थामा तो मुलायम सिंह ने तड़ से ऐलान कर दिया कि वह समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री होंगे. साथ ही उन्होंने वैश्य समाज के चार एमएलसी बनाने का वायदा भी कर दिया. नरेश अग्रवाल के शामिल होने पर पार्टी में जश्न का माहौल था. वैश्य समाज में भी ख़ुशी देखने को मिली. लखनऊ में ऐसा नज़ारा दिखा, जैसा आज़म ख़ां की वापसी के दौरान नहीं देखा गया. वैश्य समाज को लगता है कि मुलायम सिंह की पार्टी में उसकी ज़्यादा पूछ है. भाजपा का सामाजिक आधार पिछड़े, ब्राह्मण और वैश्य रहे हैं. इनमें से जब भी कोई एक तबक़ा दूर हो जाता है तो पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है.

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार वापस पाने के लिए उमा भारती को यहां की बागडोर सौंपी थी. अति महत्वाकांक्षी संन्यासिन उमा भारती तेज़तर्रार वक्ता हैं और भाजपा ने अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उनका ख़ूब इस्तेमाल किया था. इस बार भी भाजपा एक तीर से दो निशाने साधना चाहती थी. एक तरफ़ जहां वह उमा भारती के ज़रिए दलितों एवं पिछड़ों का चेहरा बनकर मायावती को चुनौती देना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह को कड़ा जवाब देना चाहती थी, लेकिन मज़बूत अगड़ी और पिछड़ी जातियों के नेताओं ने उमा भारती के मंसूबों पर पानी फेर दिया. हालत यह हो गई कि उमा भारती ने बुंदेलखंड की बबीना विधानसभा सीट से अपना नाम कटवा दिया. इतना ही नहीं, एक तरफ़ जहां मायावती जिताऊ

बसपा सरकार के दाग़ी मंत्रियों को पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने से भी भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठने लगे हैं. पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी की जनचेतना यात्रा के महज़ डेढ़ माह के भीतर ही भाजपा ने मायावती सरकार के चार दाग़ी मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा, अवधेश वर्मा, दद्दन मिश्रा और बादशाह सिंह को पार्टी में शामिल करके ख़ुद अपने ही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की हवा निकाल दी है.

बसपा सरकार के दाग़ी मंत्रियों को पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने से भी भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठने लगे हैं. पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी की जनचेतना यात्रा के महज़ डेढ़ माह के भीतर ही भाजपा ने मायावती सरकार के चार दाग़ी मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा, अवधेश वर्मा, दद्दन मिश्रा और बादशाह सिंह को पार्टी में शामिल करके ख़ुद अपने ही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की हवा निकाल दी है. इतना ही नहीं, पार्टी नेता जेल में बंद जौनपुर से बसपा सांसद धनंजय सिंह से भी संपर्क बनाए हुए हैं. बाबू सिंह कुशवाहा को शामिल किए जाने से पार्टी की आंतरिक कलह भी सामने आ रही है. पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के साथ ही किरीट सोमैया को भी उनकी हैसियत बता दी गई है. हाल में पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री एवं भ्रष्टाचार उजागर समिति के अध्यक्ष किरीट सोमैया ने बाबू सिंह कुशवाहा पर सचान हत्याकांड और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कई फ़र्ज़ी कंपनियों के ज़रिए एक हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था. अब वही कुशवाहा भाजपा में शामिल हो गए हैं. ऐसे में कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के सवालों का किस तरह सामना करेंगे. कुशवाहा के मामले में पार्टी दो ख़ेमों में बंट गई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, प्रदेशाध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही और विनय कटियार कुशवाहा के पक्ष में हैं तो सुषमा स्वराज, मुख्तार अब्बास नक़वी और एस एस अहलूवालिया उनके ख़िलाफ़ है. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा को भ्रष्टाचारियों की धर्मशाला क़रार देते हुए कहा कि इस चुनाव में भाजपा का सफ़ाया होने वाला है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कटाक्ष किया कि भाजपा के पास विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए वह बसपा से निकाले गए नेताओं को अपना बना रही है. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीएसपी के कलंक, बीजेपी के तिलक. इस सबके बावजूद भाजपा दाग़ियों को पार्टी में बनाए रखने के मूड में है. पार्टी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नक़वी भी कुशवाहा मामले में सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री एवं जदयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा ने कुशवाहा को पार्टी में शामिल करके ग़लत परंपरा की शुरुआत की है. कुशवाहा मुद्दे पर पत्रकारों ने टीम अन्ना से भी पूछा कि अब भाजपा के बारे में उनका क्या कहना है? इस पर टीम अन्ना के अहम सदस्य संजय सिंह ने कहा कि कुशवाहा को भाजपा में शामिल किया जाना यह साबित करता है कि वह भी भ्रष्टाचारियों से रिश्ते जोड़ने में पीछे नहीं है. उन्होंने भाजपा के उस बयान की निंदा की, जिसमें कहा गया था कि गंगा में नाले पवित्र हो जाते हैं. कुशवाहा पार्टी के गले की ऐसी हड्डी बन चुके हैं, जिसे वह न निग़ल सकती है और न उगल सकती है. भाजपा को लगता है कि कुशवाहा को निकालने से ज़्यादा फ़ज़ीहत होगी, इसलिए अब वह उन्हें केंद्र की यूपीए और प्रदेश की बसपा सरकार के पीड़ित के रूप में पेश कर रही है. पिछड़ों की उपेक्षा, दाग़ियों को पार्टी में शामिल करने, नेताओं की संतानों को टिकट देने आदि के चलते भाजपा में कलह पैदा हो गई है. वर्चस्व की लड़ाई में शामिल नेताओं की ख़ेमेबाज़ी से कार्यकर्ता कशमकश में हैं.

firdus@chauthiduniya.com

तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं. उनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह पार्टी में उन्हें कम अहमियत दिया जाना बताया जा रहा है.

उत्तराखंड

भाजपा और कांग्रेस में बग़ावत के आसार

अभिषेक रंजन सिंह

देवभूमि के रूप में प्रख्यात उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को इस भीषण सर्दी के मौसम में पसीने से तर-बतर कर दिया है. राज्य में आगामी 30 जनवरी को मतदान होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दोनों ही पार्टियों में आंतरिक कलह सतह पर आ गई है. भाजपा और कांग्रेस के भीतर मचे घमासान का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की घोषणा और अधिसूचना जारी होने के बाद भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर नहीं लगा पाई. हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कांग्रेस की तुलना में थोड़ी बेहतर रही. भाजपा ने नया साल शुरू होते ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, लेकिन टिकट वितरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक खासे आहत हैं. उनकी पीड़ा की पहली वजह है, चुनाव के कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाना और दूसरी वजह यह कि उनके क़रीब दर्जन भर चहेतों का टिकट काट दिया जाना. निशंक पार्टी के इन फ़ैसलों से न सिर्फ़ ख़ुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, बल्कि वह पार्टी को चुनाव में सबक सिखाने का भी मूड बना चुके हैं. दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे. ख़ासकर कुंभ मेले के सिलसिले में कैग की रिपोर्ट आने के बाद न सिर्फ़ विपक्षी पार्टी कांग्रेस, बल्कि भाजपा के कई शीर्ष नेता भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, ताकि विधानसभा चुनाव में यह मामला पार्टी का खेल न बिगाड़ दे. इसीलिए पिछले साल सितंबर महीने में निशंक की जगह भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया. इन चुनाव में खंडूरी को अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों पर यक़ीन है. उल्लेखनीय है कि बतौर मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेहतर शासन की वजह से वर्ष 2007 में हुए एक सर्वेक्षण में उत्तराखंड को देश के दस प्रमुख राज्यों में पहला स्थान हासिल हुआ था. इसी तरह 2008 के सर्वेक्षण में भी उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा था, लेकिन मौजूदा समय में उत्तराखंड की छवि लगातार दाग़दार होती जा रही है. उत्तराखंड में बड़ी पार्टियों के बीच जारी घमासान के बीच जनता ख़ामोश है. प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के भीतर जारी उठापटक को बख़ूबी समझ रही है. ऐसे में जनता का वोट किसे मिलेगा इसका अंदाज़ा सूबे की पार्टियों को भी नहीं है.

अमूमन शांत समझे जाने वाले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों में जिस तरह घमासान मचा हुआ है, उससे दोनों पार्टियों के नेता बेहद परेशान हैं. एक तरफ़ भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक पार्टी की राह में कांटे बिछा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी भी पार्टी को मटियामेट करने पर तुले हैं.

अमूमन शांत समझे जाने वाले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों में जिस तरह घमासान मचा हुआ है, उससे दोनों पार्टियों के नेता बेहद परेशान हैं. एक तरफ़ भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक पार्टी की राह में कांटे बिछा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी भी पार्टी को मटियामेट करने पर तुले हैं. यही वजह थी कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में काफी देर बाद अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया. इसकी सबसे बड़ी वजह नारायण दत्त तिवारी बताए जा रहे हैं. तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं. उनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह पार्टी में उन्हें कम अहमियत दिया जाना बताया जा रहा है. नारायण दत्त तिवारी पिछले दिनों खुल्लमखुल्ला कह चुके हैं कि वह उन लोगों को टिकट देंगे, जो कांग्रेस और भाजपा से टिकट न मिलने की वजह से बग़ावत कर चुके हैं. उनके इस ऐलान से न सिर्फ़ कांग्रेस, बल्कि भाजपा में भी खलबली मची हुई है. वैसे भाजपा की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होतीं, कभी उसके साथ रहा उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बार उसे सबक सिखाने के मूड में है. वहीं पिछले चुनाव में आठ सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार पूरे दम-खम के साथ चुनावी समर में उतर चुकी है. बहुजन समाज पार्टी में भाजपा और कांग्रेस की तरह न तो टिकट के बटवारे को लेकर कोई ख़ास विरोध था और न ही प्रदेश में पार्टी नेताओं के बीच कोई आपसी विवाद.

बहरहाल, उत्तराखंड में सियासी हालात इस क़दर बिगड़ चुके हैं कि भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अभी तक अपनी घरेलू मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाई हैं. इससे जहां भाजपा का राज्य में दूसरी बार हुकूमत करने का मंसूबा नाकाम होता दिख रहा है, वहीं सत्ता पर काबिज़ होने के कांग्रेस के ख्वाब को नारायण दत्त तिवारी पलीता लगाने पर तुल गए हैं. इन दोनों अहम सियासी पार्टियों के भीतर मची आपसी खींचतान से उत्तराखंड में चुनाव की तस्वीर पर बागियों की नज़र लग गई है. हालांकि, भाजपा और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बड़ी पार्टियों को चुनाव में ऐसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है, लिहाज़ा इससे पार्टी की सेहत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहे जो कहें, लेकिन इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपनी-अपनी पार्टियों से लगभग बग़ावत कर चुके रमेश पोखरियाल निशंक और नारायण दत्त तिवारी चुनावी नतीज़ों में कोई बड़ा उलट-फेर भी कर सकते हैं.

विधानसभा की मौजूदा तस्वीर

कुल सीटें	70
भाजपा	34
कांग्रेस	21
बसपा	08
निर्दलीय	03
अन्य	04

arsingh@chauthiduniya.com

मणिपुर

कांग्रेस की राह आसान नहीं

देश में गठबंधन की राजनीति और राजनीतिक दलों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 60 सदस्यीय विधानसभा वाले मणिपुर में, जहां आगामी 28 जनवरी को मतदान होना है, गठबंधन का ऐसा खेल खेला जा रहा है, जो आपको हैरत में डाल सकता है. अब तक गठबंधन प्राय: उन्हीं दलों के बीच होता रहा है, जिनमें थोड़ी-बहुत वैचारिक समानता हो, लेकिन मणिपुर में चुनाव पूर्व गठबंधन की ऐसी खिचड़ी पक रही है, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है. फ़िलहाल मणिपुर में मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है. पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. उस चुनाव में कांग्रेस को 30, मणिपुर पीपुल्स पार्टी (एमपीपी) को 5, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं एनसीपी को 4-4, आरजेडी एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी को 3-3 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 10 सीटें हासिल हुई थीं. इस बार गठबंधन की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), जनता दल यूनाइटेड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मणिपुर पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. हालांकि इस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के भी शामिल होने की बात कुछ समाचार माध्यमों के ज़रिए सामने आई है.

सबसे हैरत भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर के उस बयान पर हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा मणिपुर पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में विकास व सांप्रदायिक एकता को समर्पित सरकार बनाएगी.

सबसे हैरत भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर के उस बयान पर हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा मणिपुर पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में विकास और सांप्रदायिक एकता को समर्पित सरकार बनाएगी. ख़ैर गठबंधन की ऐसी अस्पष्ट तस्वीर शायद ही किसी दूसरे राज्य में देखने को मिले, जैसी मणिपुर में देखने को मिल रही है. एक तरफ़ जदयू का कहना है कि एमपीपी के साथ उसका गठबंधन है, जिसमें एनसीपी और सीपीआई भी शामिल हैं. दूसरी तरफ़ भाजपा का भी दावा है कि एमपीपी के साथ उसका गठबंधन है. अगर भाजपा और जदयू की बात मान लें तो यह एक ऐसा गठबंधन होगा, जिसमें भाजपा की धुर विरोधी पार्टियां यानी सीपीआई और एनसीपी उसके साथ शामिल होंगी. हालांकि मणिपुर में भाजपा का कोई ख़ास वजूद नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. फ़िलहाल मणिपुर की जो हालत है, उसमें विपक्षी पार्टियों की क़वायद और मणिपुर पीपुल्स पार्टी के साथ गठबंधन करने की होड़ के चलते एक अनार सौ बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है.

उधर मणिपुर के लोगों में मौजूदा कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ कुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है. ख़ासकर आतंकवाद और जातीय दंगों के अलावा 100 दिनों से अधिक समय तक चली आर्थिक नाकेबंदी के दौरान जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस वजह से कांग्रेस सरकार की छवि काफी ख़राब हुई. ग़ौरतलब है कि सदर हिल्स ज़िला मांग समिति (एसएचडीडीसी) की ओर से कुकी जनजाति बहुल सदर हिल्स इलाक़े को पूर्ण ज़िले का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले एक अगस्त से आर्थिक नाकेबंदी शुरू की गई थी, जिसका नगा समुदाय ने विरोध किया. तीन माह तक चली इस आर्थिक नाकेबंदी के दौरान लोगों को पेट्रोल, रसोई गैस और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं का घोर अभाव झेलना पड़ा. ज्ञात हो कि मणिपुर पूर्ण रूप से बाहर से आने वाली रसद-सामग्री पर निर्भर है. इस लिहाज़ से मणिपुर में होने वाला विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो सकता है. विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार जनता की बुनियादी समस्याएं हल कर पाने में पूरी तरह नाकाम रही है.

अभिषेक रंजन सिंह
arsingh@chauthiduniya.com

उपजाऊ भूमि अधिग्रहण मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रामनंदन सिंह उर्फ बौकू बाबू पिछले अक्टूबर माह में ही एंजियोग्राफी कराकर दिल्ली से लौटे हैं.

जान देंगे ज़मीन नहीं

सरोज सिंह

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बरौनी ताप विद्युत संयंत्र का विस्तारीकरण किया जाना है. राज्य मंत्रिमंडल ने 3666 करोड़ रुपये की इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है. सरकार का कहना है कि फ़िलहाल 2X250 मेगावॉट क्षमता वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना होगी. भविष्य में 250 मेगावॉट क्षमता वाले तीसरे संयंत्र की भी स्थापना की जा सकती है. बरौनी ताप विद्युत संयंत्र बेगूसराय ज़िले में एनएच 31 के किनारे स्थित है, जिसकी स्थापना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के प्रयासों से हुई थी. बीटीपीएस में फ़िलहाल दो संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिन पर काम शुरू हो चुका है. विद्युत संयंत्र के पास पहले से ही बीटीपीएस की अधिग्रहीत ज़मीन है, जिसका उपयोग ऍश पॉण्ड यानी छाई निस्तारण क्षेत्र के तौर पर किया जा रहा था. सरकार पूर्व के ऍश पॉण्ड इलाक़े को समतल करके 250 मेगावॉट क्षमता के कोयला आधारित दो विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है. दर्जनों जेसीबी एवं पोकलेन मशीनें और सैकड़ों मज़दूर ज़मीन के समतलीकरण में जुट गए हैं. सरकार को कुल 565 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करना है, जिसका उपयोग ऍश पॉण्ड के लिए किया जाना है.

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी बेगूसराय की रामदीरी पंचायत के किसानों की लगभग 270 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं. किसान रामनंदन सिंह उर्फ बौकू सिंह कहते हैं कि विद्युत विभाग उनकी कृषि योग्य उपजाऊ भूमि लेना चाहता है, जिसके सहारे वह अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे हैं. किसानों को इस बात पर गहरी आपत्ति है कि कम उपजाऊ ज़मीन लेने से सरकार क्यों भाग रही है और किसानों की कृषि योग्य उपजाऊ ज़मीन सरकार को इतनी पसंद क्यों आ रही है. चार पंचायतों वाले रामदीरी गांव के किसानों की रोजी–रोटी का एकमात्र सहारा यही ज़मीन है. किसानों की आपत्तियों के संबंध में बेगूसराय के ज़िलाधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव ने मटिहानी प्रखंड के रैली बाध में उनके साथ एक बैठक भी की. ज़िलाधिकारी श्रीवास्तव कृषि योग्य उपजाऊ ज़मीन को देखकर हतप्रभ रह गए और उन्होंने वहां पर मौजूद बीटीपीएस के जीएम अविनाश कुमार से पूछा कि आप इतनी उपजाऊ ज़मीन लेने पर क्यों आमादा हैं? किसानों ने मटिहानी अंचल के अंतर्गत थाना संख्या 424 की रैली बाध की ज़मीन देने से इंकार कर दिया. ज़िलाधिकारी ने किसानों से वैकल्पिक ज़मीन की मांग की तो किसान मनोज सिंह ने गड़हरा रेलवे यार्ड, एनएच 31 और रेलवे लाइन से पश्चिम की ज़मीन विकल्प के तौर पर सुझाई. बीटीपीएस के जीएम अविनाश कुमार ने इस विकल्प को यह कहकर खारिज कर दिया कि पश्चिम की ज़मीन रेलवे लाइन से काफी नीची है और गड़हरा यार्ड के पास स्थित ज़मीन अधिग्रहीत करने पर रेलवे से झंझट का सामना करना पड़ेगा.

मनोज सिंह एवं टुल्लू सिंह सरीखे किसानों ने कथित निचली ज़मीन को राख से भरने की सलाह दी. किसानों का तर्क था कि ऐसा करने से ज़मीन अधिग्रहण पर किसी तरह का बवाल नहीं होगा और कथित निचली ज़मीन को भरे जाने से राख का निस्तारण भी हो जाएगा. बीटीपीएस जीएम अविनाश कुमार एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के अड़ियल रुख को देखते हुए ज़िलाधिकारी ने बीच का रास्ता निकालने की कवायद में दूसरा विकल्प मांगा. इस पर किसानों ने उनसे कहा कि जिस ज़मीन पर फ़िलहाल काम चल रहा है, उससे पूरब और दक्षिण दिशा की ज़मीन ली जा सकती है. ज़िलाधिकारी ने तत्काल एक संयुक्त समिति बना डाली और उसे ज़मीन के चयन के लिए अधिकृत कर दिया. मटिहानी अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी वीरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में गठित इस समिति में बरौनी थर्मल के दो अधिकारियों एवं तीन किसानों को शामिल किया गया. ज़िलाधिकारी के निर्देश पर तय हुआ कि बीटीपीएस यह व्यवस्था करेगा कि संयुक्त समिति तीनों वैकल्पिक ज़मीनों का मौक़ा मुआयना करे. किसानों की सलाह को बीटीपीएस अधिकारी नज़रअंदाज़ करते रहे, लेकिन सीओ द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर संयुक्त समिति ने उक्त तीनों ज़मीनों का निरीक्षण किया. रामदीरी के किसानों ने ज़िला अंतर्गत मटिहानी अंचल के मल्हीपा मौजा के थाना संख्या 503 की ज़मीन सुझाई. इस ज़मीन का रकबा 843 एकड़ है, जो कि आवश्यकता से काफी अधिक है. हैरानी इस बात की है कि सरकार किसानों द्वारा सुझाई गई ज़मीन को खारिज कर रही है और रैली बाध की ज़मीन लेने पर आमादा है.

किसान राजकिशोर कहते हैं कि मसले को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के बजाय सरकार हम लोगों को डंडा दिखा रही है. किसान झुन्ना सिंह चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सरकार इस भुलावे में न रहें कि हम डर जाएंगे. झुन्ना सिंह की मानें तो इलाक़े में पपीते की खेती पहले ही बर्बाद हो चुकी है.

किसान मुन्ना सिंह चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैं कि यदि सरकार हमारी जान लेना चाहती है तो हम जान दे देंगे, पर ज़मीन नहीं. बकौल मुन्ना सिंह, परिवार को भूखा मारने से अच्छा है, एकबारगी जान दे देना.

उपजाऊ भूमि अधिग्रहण मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रामनंदन सिंह उर्फ बौकू बाबू पिछले अक्टूबर माह में ही एंजियोग्राफी कराकर दिल्ली से लौटे हैं, पर ज़मीन छीन लिए जाने के भय से आंदोलन में शामिल हैं. बौकू सिंह कहते हैं कि जब मल्हीपुर मौजा की ज़मीन किसान स्वत: देना चाह रहे हैं तो उस ज़मीन को लेने में अधिकारियों को आख़िर क्या परेशानी है. रामचंद्र सिंह कहते हैं कि रैली बाध और कसहा दियारा मरांची मौजा की ज़मीनों का किसी सूरत में अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा. राम प्रवेश सिंह कहते हैं कि हज़ारों परिवारों की रोजी–रोटी इन्हीं ज़मीनों पर निर्भर है और सरकार को हमारी रोटी छीनने का हक़ नहीं है. राम प्रवेश सिंह की मानें तो सरकार किसानों की आवाज़ दबाने के लिए दमनकारी रवैया अपना रही है. मोकामा में जन सुनवाई के दौरान हुई पुलिसिया ज़्यादती का हवाला देते हुए रामचंद्र सिंह कहते हैं कि मोकामा को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और बेगूसराय–मोकामा के बीच बारह स्थानों पर बैरियर लगाकर किसानों को वहां जाने से जबरन रोका गया. पूर्व मुखिया गणेश सिंह कहते हैं कि जब मरांची मौजा की ज़मीन ग़ैर मजरुआ थी, तब भूदान आंदोलन के दौरान उसे सरकार ने किसानों से कैसे लेकर भूमिहीनों के बीच वितरित कर दी. गणेश सिंह कहते हैं कि मुआवज़े की रकम बचाने के लिए सरकार घिनौना खेल कर रही है.

अमीन और ज़मीन मामलों के जानकार महेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकारी दावा अनुचित है. महेंद्र सिंह की मानें तो सरकार के पास ज़मीन का कोई काग़ज़ात नहीं है और वह केवल जमाबंदी के आधार पर किसानों को उनके हक़ से वंचित कर रही है. ज़मीन बचाओ आंदोलन शुरू करने वाले राम भरोसा सिंह कहते हैं कि यह ज़मीन उन्हें अपने पुरखों से मिली थी, जिसे उन्होंने अपने वंशजों को देने के लिए बचा रखी है. राम भरोसा सिंह कहते हैं कि जान देना ज़्यादा अच्छा है, बजाय ज़मीन देने के. किसान राजकिशोर कहते हैं कि मसले को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के बजाय सरकार हम लोगों को डंडा दिखा रही है. किसान झुन्ना सिंह चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सरकार इस भुलावे में न रहें कि हम डर जाएंगे. झुन्ना सिंह की मानें तो इलाक़े में पपीते की खेती पहले ही बर्बाद हो चुकी है. राजकिशोर आशंका जताते हुए कहते हैं कि प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर लोगों का जीना मुहाल कर देगा. युवा किसान कुमार अभिजीत कहते हैं कि सरकार रामदीरी को फारबिसगंज समझने की भूल कतई न करे. टुल्लू कहते हैं कि किसानों को उनकी ज़मीन के स्वामित्व से वंचित करने के प्रयासों के परिणाम काफी घातक होंगे. किसान आंदोलन में सक्रिय रत्नेश उर्फ टुल्लू कहते हैं कि किसानों ने ज़मीन अधिग्रहण के संबंध में सरकार से बातचीत का रास्ता खुला तो छोड़ रखा है, लेकिन वह आंख दिखाकर किसानों के साथ ज़बरदस्ती हरगिज़ नहीं कर पाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

रामनंदन सिंह

गणेश सिंह

राम प्रवेश सिंह

कुमार अभिजीत

राम भरोसा सिंह

महेंद्र सिंह

रामचंद्र सिंह

कुमार रत्नेश

झुन्ना सिंह

मेरी दुनिया.... भाजपा की चरित्र सुधार योजना

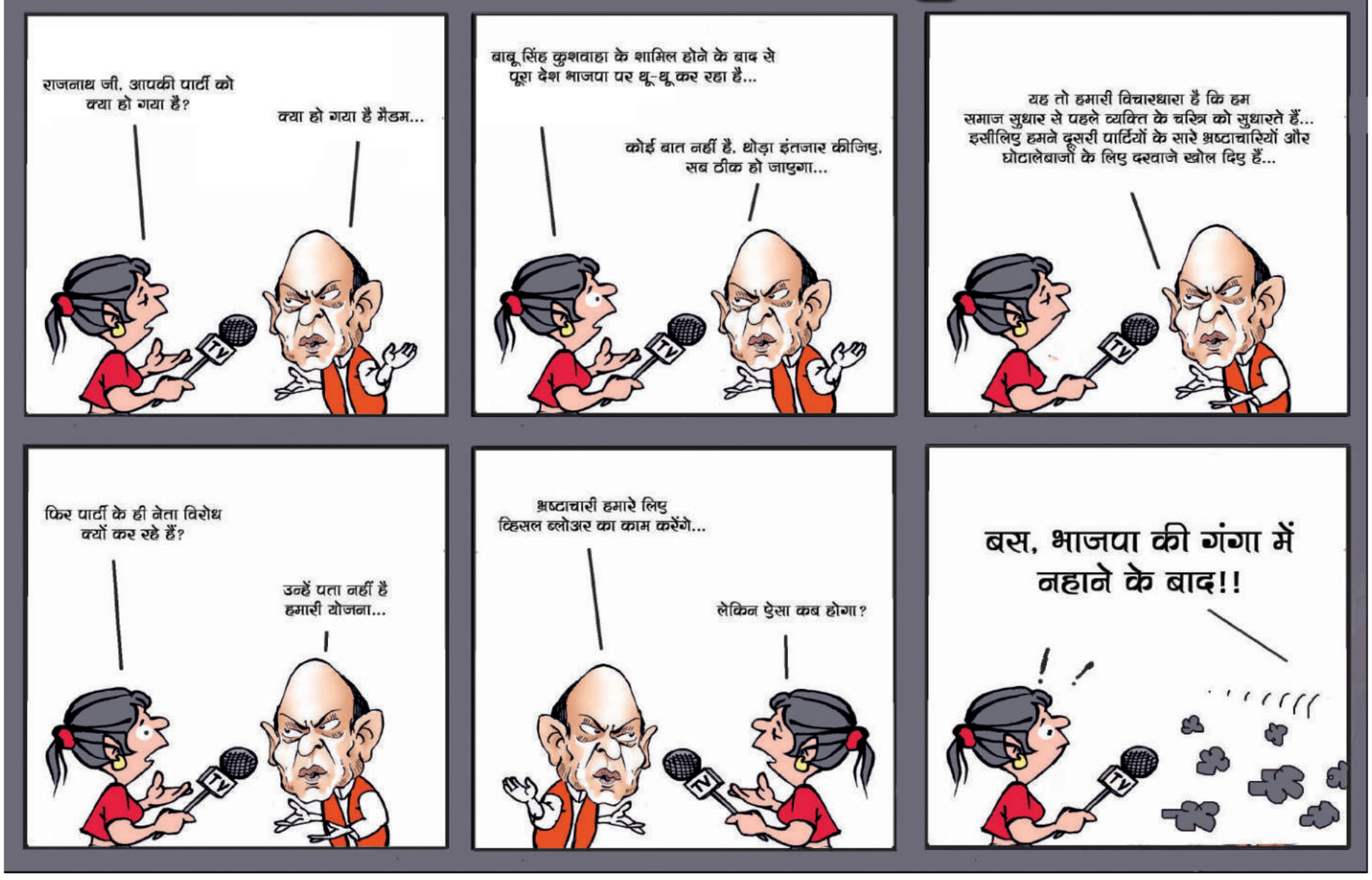

सहकारी बैंक और वित्तीय समावेशन

वी के शर्मा

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है. यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान रहा है. इसने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जिस तरह से सहकारी बैंकों का उपयोग किया है, वह सरहानीय है. इसने न केवल सैद्धांतिक तौर पर सहकारी बैंकों की भूमिका को माना है, बल्कि इसे लागू करने के लिए भी महत्वपूर्ण क़दम उठाया है. देश में विस्तृत रूप से वित्तीय समावेशन को लागू करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए कुछ रणनीति बनाई हैं. भारत सरकार ने सुदूर क्षेत्र में अवस्थित गांवों तक वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई को अपने साथ शामिल किया है. दोनों ने मिलकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कई सुधार करने की नीति बनाई है. भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार इनकी निगरानी करेगी, ताकि इसका फ़ायदा ग़रीब लोगों तक पहुंच सके. बीसी–आईसीटी–सीबीएस (बिजनेस कॉरस्पांडेंट–इंफोर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी–कोर बैंकिंग) द्वारा इस सेवा का विस्तार उन क्षेत्रों तक किया जाएगा, जहां अभी तक वित्तीय सेवा की पहुंच नहीं हो पाई है. यह नहीं कहा जा सकता है कि इस विचार से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यह एक बेहतर विकल्प ज़रूर उपलब्ध कराएगा. सरकार की वित्तीय समावेशन की अवधारणा के मार्ग को प्रशस्त करने में इस विचार की एक अहम भूमिका हो सकती है. हालांकि कुछ कारणों से भारत में सहकारी बैंकों का विकास उम्मीद से कम हुआ है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अगर इसका विकास सही तरीक़े से किया जाए तो यह वाणिज्यिक बैंकों की सहयोगी की भूमिका निभा सकता है. इससे इन वाणिज्यिक बैंकों का बोझ भी कम हो जाएगा.

भारत सरकार को अगर वित्तीय समावेशन के एजेंडे को सफल बनाना है तो ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को और बेहतर करना होगा. लोगों तक इनकी पहुंच बढ़ानी होगी. वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाएं 33000 हैं, से इनकी तुलना की जाए तो सहकारी बैंकों का फैलाव इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक है. भारत में 33 राज्य सहकारी बैंकों की 953 शाखाएं हैं, 371 ज़िला सहकारी बैंकों की 12858 शाखाएं हैं. इसके अलावा हमारे देश में 109000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) भी हैं, अर्थात भारत में ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली सहकारी ऋण समितियों की संख्या 122590 है. इसकी संख्या की अधिकता के कारण इसका संचालन एक कठिन काम रहा है. सरकार के सामने इसका सफल संचालन करना एक बड़ी चुनौती रही है. इसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कई क़दम उठाए हैं. आरबीआई ने न केवल पीएसीएस को वाणिज्यिक बैंकों के व्यापारिक अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दी है, बल्कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक बैंक और किसानों की बीच की कड़ी की भूमिका निभाने के लिए भी अनुमति दी है. पीएसीएस के अलावा किसान सेवा समिति (एफएसएस) तथा लार्ज साइज मल्टीपर्पस सोसायटी (एलएएमपीएस) को भी परोक्ष रूप से किसानों तथा आदिवासियों को ऋण देने की स्वीकृति मिल चुकी है. वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2013 तक 350000 गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराएंगे. वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार तथा आरबीआई सहकारी ऋण सेवा की भूमिका बढ़ाना चाहती है. इसके लिए बहुत समय से उपेक्षित अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनरुद्धार करना चाहती है. इसके लिए आरबीआई ने विद्यानाथ समिति का गठन किया है. इस समिति की अनुशंसा को लागू करने का प्रयास भी आरबीआई कर रही है. विद्यानाथ समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों तथा सहकारिता मंत्रियों के साथ मुलाक़ात की. इस मुलाक़ात के बाद भारत सरकार ने संकटग्रस्त अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना को मज़बूत करने के लिए पहले से घोषित वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी कर दी है. पूर्व में इसके लिए 136 बिलियन रुपये की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ाकर 193 बिलियन रुपये कर दिया गया है. लेकिन इस धन के उपयोग के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. इसके अनुसार अब नियामक अधिकार आरबीआई के पास होगा तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 25 प्रतिशत तक सीमित कर दी जाएगी. इससे बोर्ड के निरीक्षण में राज्य सरकार की भूमिका नहीं होगी. वित्तीय तथा आंतरिक प्रशासन में भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाएगा. पीएसीएस, डीसीसीबी (ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक), एससीबी (राज्य सहकारी बैंक) का ऑडिट चार्टर अकांउटेंट द्वारा कराया जाएगा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) की नियुक्तियों में आरबीआई की भूमिका होगी. इसके अलावा ट्रेनिंग अकाउंट सिस्टम (सीएएस) मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) में सुधार किया जाएगा. साथ ही राज्य सहकारी समिति अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा.

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत के 25 राज्यों ने सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए दिए जाने वाले पैकेज को लागू करने वाले क़रार पर हस्ताक्षर किया है. एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. ये राज्य पूरे देश के एसटीसीसीएस (अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना) के अंतर्गत आने वाली सहकारी समितियों का 96 फ़ीसदी हिस्सा कवर करते हैं. इन राज्यों की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता तभी दी जाएगी, जब ये लोग क़ानूनी और संस्थागत सुधार को लागू करेंगे. 31 अक्टूबर, 2011 तक नाबार्ड ने सात राज्यों में पीएसीएस के पुन: पंजीकरण के लिए भारत सरकार की ओर से 90 बिलियन रुपये दिए हैं, जिसमें 8.5 बिलियन रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं. यह बहुत ही उत्साहवर्द्धक बात है कि 21 राज्यों ने अपने राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन कर दिया है. संशोधन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं. इस प्रकार से ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के प्रबंधन एवं संचालन में किए गए सुधारों का असर ज़रूर होगा तथा इसका लाभ गांवों में रह रहे ग़रीब लोगों तक पहुंचेगा. सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में इसकी अहम भूमिका होगी.

वित्तीय क्षेत्र के आंकलन के लिए बनाई गई समिति जिसके अध्यक्ष राकेश मोहन तथा उपाध्यक्ष अशोक चावला थे, ने अपनी अनुशंसा में कहा था कि जो भी सहकारी बैंक मार्च 2012 तक लाइसेंस नहीं ले पाए हैं, को आगे काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही अप्रैल 2009 में भी यह कहा गया था कि जिन केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को लाइसेंस नहीं मिला है, उन्हें लाइसेंस देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाए. इन निर्देशों के आधार पर नाबार्ड के साथ संपर्क कर सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए गए.

नए सुधारों के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहकारी ऋण संस्थाओं पर नियंत्रण रखेगी तथा नाबार्ड इनका निरीक्षण करेगा. इस तरह आरबीआई इन सरकारी संस्थाओं को सुझाव देगी तथा इन सुझावों के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, इसे देखने की ज़िम्मेदारी नाबार्ड की होगी. पहले कई संस्थाएं इन्हें निर्देश देती थीं, जिससे सुचारु रूप से कार्य करने में काफ़ी कठिनाई होती थी. अब आरबीआई और नाबार्ड ही इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे. इस तरह से सहकारी संस्थाओं का तेज़ी से विकास होगा और इसका परिणाम लोगों के सामने जल्द से जल्द आ जाएगा. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन राज्य सहकारी बैंकों को पुन:पंजीकरण के लिए पुनरुद्धार पैकेज की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी अपने बैंक की शाखाएं खोलने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा. वित्तीय क्षेत्र के आंकलन के लिए बनाई गई समिति जिसके अध्यक्ष राकेश मोहन तथा उपाध्यक्ष अशोक चावला थे, ने अपनी अनुशंसा में कहा था कि जो भी सहकारी बैंक मार्च 2012 तक लाइसेंस नहीं ले पाए हैं, को आगे काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही अप्रैल 2009 में भी यह कहा गया था कि जिन केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को लाइसेंस नहीं मिला है, उन्हें लाइसेंस देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाए. इन निर्देशों के आधार पर नाबार्ड के साथ संपर्क कर सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए गए. इसके साथ आरबीआई के सभी क्षेत्रीय शाखाओं को यह सलाह दी गई कि जो सहकारी बैंक निर्धारित मानदंड का पालन करते हैं, उन्हें लाइसेंस दिया जाए. इससे यह उम्मीद है कि 2012 में बहुत सारे सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा. विद्यानाथ समिति की अनुशंसा के आधार पर जो पुनरुद्धार पैकेज दिए जा रहे हैं, उससे राज्य सहकारी बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और ये लाइसेंस लेने के क़ाबिल बन जाएंगे. ग़ौरतलब है कि 31 मार्च, 2009 तक 17 राज्य सहकारी बैंक तथा 296 ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक बिना लाइसेंस के थे, जिनकी संख्या 30 नवंबर, 2011 तक घटकर क्रमश: 6 और 117 हो गई. सहकारी बैंकों के परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए सही तरीक़े से चल रहे कुछ सहकारी बैंकों का अध्ययन किया गया. इस अध्ययन में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) लार्ज आदिवासी मल्टीपर्पस को ऑपरेटिव सोसायटी (एलएएमपीएस) फार्मर्स सर्विस सोसायटी (एफएसएस) को भी इसमें शामिल किया गया है. 21 राज्यों में सुचारू रूप से चलाए जा रहे 208 सहकारी समितियों का अध्ययन किया गया. रिजर्व बैंक के अनुसार, अध्ययन में इन बैंकों की कार्यप्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इन संस्थाओं के सदस्यों, इनमें धन जमा करने वाले जमाकर्ताओं तथा ऋण लेने वालों का प्रोफाइल इकठ्ठा करके उसका अध्ययन करना, इनके प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इनकी कार्यप्रणाली के प्रभावों का विश्लेषण करना तथा इनके प्रभावशाली संचालन के लिए कुछ सुझाव देना आदि शामिल किया गया है. नवंबर 2011 तक इस अध्ययन को अंजाम दिया जा चुका है. इस अध्ययन से यह पता चला है कि किस तरह से संकट में फंसे सहकारी बैंकों को फिर से सशक्त किया जाए. आरबीआई इस पर निर्देश जारी करेगी. रिजर्व बैंक और भारत सरकार के इन प्रयासों से उम्मीद है कि कुछ समय में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना को एक नया आधार प्राप्त होगा तथा इसका तेज़ी से विकास होगा. सहकारी ऋण संरचना के विकास का सबसे ज़्यादा लाभ सुदूर गांव में रहने वाले किसानों, मज़दूरों तथा आदिवासियों को होगा. इस संरचना को मज़बूत किए बिना सरकार के वित्तीय समावेशन का सपना पूरा होना मुश्किल है. अत: यह भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि वह इस संरचना को और मज़बूत करे. इसकी मज़बूती का फ़ायदा दूसरी हरित क्रांति, पशुपालन, मुर्ग़ी पालन आदि में होगा. इससे हमारे देश की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे भारत खाद्य सुरक्षा संबंधी अपने लक्ष्य को पा सकेगा.

feedback@chauthiduniya.com

(लेखक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत के 25 राज्यों ने सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए दिए जाने वाले पैकेज को लागू करने वाले क़रार पर हस्ताक्षर किया है. एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

जनता को प्रबुद्ध किया जाए, ताकि उनको अपने भले-बुरे का संपूर्ण ज्ञान हो जाए. वे यह समझने लगें कि उनका वोट ही वह ताकत है, जिसकी बदौलत ये अधिकारीगण अपनी मनमानी कर सकते हैं.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

सहकारी अर्थव्यवस्था की प्राचीन परंपरा

एक और आवाज़ आजकल जोरों से उठाई जा रही है, वह है सहकारिता आंदोलन की. सहकारिता आंदोलन देश के लिए, राष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए उपादेय है, बशर्ते कि इस पद्धति का ईमानदारी से अनुसरण किया जाए. यदि सहकारिता के नाम पर भी उसी पूंजीवादी प्रतिष्ठा की स्थापना होनी है तो फिर सहकारिता को बदनाम क्यों किया जाए? यूं तो सृष्टि के आदि से लेकर हर आदमी किसी न किसी रूप में सहकारिता का पक्षपाती रहा है. भारत की परिवार व्यवस्था, ग्राम्य व्यवस्था, नगर व्यवस्था सभी सहकारिता पर ही तो अवलंबित हैं. आज भी उसी रूढ़िगत परिपाटी की छाया मौजूद है. किसी व्यक्ति के यहां लड़की की शादी है. शादी में मान लें, 1 हज़ार रुपया ख़र्च होने वाला है. गांव के क़रीब-क़रीब सारे ही व्यक्ति इस आयोजन में सहयोग देंगे. कोई एक रुपया, कोई दो रुपये, कोई कम, कोई ज़्यादा व्यवहार का या चांदला का अपनी-अपनी सामाजिक रस्म के अनुसार देंगे. लड़की के पिता को अपने पास से मुश्किल से सौ या दो सौ रुपये ख़र्च करने पड़ेंगे. बाक़ी सारी व्यवस्था इसी ग्राम्य सहकारिता या सहयोग से हो जाएगी. जीवन की हर क्रिया में, जन्म से लेकर मरण पर्यंत भारत के हर घर में यह सहकारिता विद्यमान थी. आगे चलकर यह सहकारिता जाति या वर्णभेद में समा गई. लोग अपने जीवनोपयोगी पदार्थों को उपलब्ध करने के लिए संघर्षजीवी थे. अतएव दल के दल अपनी सुरक्षा का उचित प्रबंध स्वयं करते थे. कबीले ठौर-ठौर बन गए थे. यह सारा सहकारिता आंदोलन ही तो था.

अवैध कामों में भी बिना सहकारिता के कार्य होना असंभव सा था. चार चोर मिलकर किसी घर या मकान में चोरी करते थे तो वे भी एक-दूसरे के सहायक बनकर अलग-अलग कामों का जिम्मा लेते थे, बाद में चोरी से प्राप्त धन का सहकारिता के हिसाब से ही बंटवारा होता था. कहने का मतलब यही है कि सहकारिता भारत के लिए कोई नई चीज तो है नहीं. अब इसको वैध रूप से, आंदोलन का स्वरूप देकर, जीवनोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त कर सकने या श्रम वितरण का या वित्त वितरण का सुगम मार्ग मानकर जगह-जगह सहकारी संस्थाएं खोल दी गई हैं. अगर भारत की सहकारी संस्थाओं के अधिष्ठाता ईमानदारी से अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते रहें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का ध्येय बहुत ही जल्दी हासिल किया जा सकता है. समान वित्त वितरण आसान हो जाएगा. पर क्या ये सहकारी संस्थाएं उचित मार्ग पर चलती हैं या चल सकती हैं? यह प्रश्न विचारणीय है. ज़रा ग़ौर कीजिए.

भारत के विभिन्न राज्यों में सहकारी संस्थाओं के नियमन के लिए विभिन्न क़ानून बने हुए हैं. उदाहरण के लिए बंबई सहकारी संस्था एक्ट के सिद्धांत तो सही हैं, पर इस देश में, जहां शिक्षा का नितांत अभाव है, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ कर क्या उचित ढंग से अपना मत दे सकता है? मान लीजिए, आपने एक सहकारी संस्था का स्टोर बनाया, जिसके द्वारा जीवनोपयोगी हर वस्तु उचित मूल्य पर हर मेंबर को मिलेगी. यह संभव इस तरह से होता है कि बहुत सी खाद्य सामग्री, पहनने के लिए कपड़े और अन्य बहुत सी चीजें सरकार से नियंत्रित मूल्य पर मिल जाती हैं या पैदा करने वालों से सीधे बिना किसी बिचौलिए की कमीशन के मिल जाती हैं. कोई थोक विक्रेता भी उस भाव से नहीं दे सकता. अब अगर उस सहकारी संस्था के अधिकारी और कर्मचारीगण ईमानदार हैं, तो निश्चय ही उस संस्था के मेंबरों को तमाम इच्छित वस्तुएं सस्ती और अच्छी सुलभ हो जाएंगी. पर जैसा मानव का स्वभाव है, अपने लाभ की बात सोचे बिना वह रह नहीं सकता. एक धोती जोड़ा बाज़ार में 15 रुपये में बिक रहा है और अपनी संस्था को 10 रुपये में ही मिल रहा है. सारे ख़र्चे लगाकर भी मेंबरों को 12 से ज़्यादा में नहीं दिया जा सकता तो आदमी सोच सकता है, क्यों न इनमें से कुछ लेकर, बाज़ार में ऊंची क़ीमत पर बेचकर मुनाफ़ा कमा लिया जाए?

इसी तरह से ख़रीदने में सैकड़ों प्रलोभन के क्षण आते हैं, जिनका संवरण करना कठिन हो जाता है. सहकारी संस्था के नियमन की देखरेख करने वाले सरकार द्वारा नियुक्त किए गए इंस्पेक्टर या ऑफिसर लोग भी जब तहक़ीक़ात करने के लिए दौरे पर आते हैं, तो वे ही लोग उनकी सेवा-पूजा ज़्यादा कर सकते हैं, जिनका अपना पेट भरा हुआ हो. उपभोक्ताओं की सहकारी संस्थाओं के अलावा अब तो औद्योगिक सहकारी संस्थाएं भी जोर-शोर से चलने लगी हैं. बड़े-बड़े कारखाने या फैक्ट्रियां इस विभाग के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं. शासन की नीति इनको यथाशक्ति सब तरह से सहायता देने की है. परिणाम यही है कि कुछ होशियार व्यक्ति, जो अपने हथकंडों से संस्था पर काबू जमाए रहते हैं, अपनी मनमानी करते रहते हैं. जिस तरह से पूंजीवादी अपनी निजी संपत्ति को अपनी बपौती समझता है, उसी तरह ये कार्यकर्तागण या सहकारिता के अधिकारी भी सहकारिता के लिए प्राप्त सुविधाओं को अपनी बपौती समझने लगे हैं. इस परिस्थिति का आख़िर इलाज हो कैसे?

जनता को प्रबुद्ध किया जाए, ताकि उनको अपने भले-बुरे का संपूर्ण ज्ञान हो जाए. वे यह समझने लगें कि उनका वोट ही वह ताक़त है, जिसकी बदौलत ये अधिकारीगण अपनी मनमानी कर सकते हैं. इस तरह की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने में काफी समय लगता है. इस अज्ञान को दूर करने में किसी भी राजनीतिक पार्टी का हित भी तो नहीं है. इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों का बल जनता की अज्ञानता पर ही निर्भर करता है. लिहाज़ा, राजनीतिक नारों की आवाज़ चाहे जितनी बुलंद हो, जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी प्रयत्नशील नहीं है. राजनेताओं का रवैया राष्ट्र के दुर्भाग्य और जनता के अकल्याण के लिए काफी हद तक ज़िम्मेदार है. सहकारिता के हिमायती उसकी सफलता के इतने ज़्यादा समर्थक हैं कि प्रत्येक बात के लिए वे अब सहकारी संस्था को ही श्रेष्ठ पंथ मानते हैं. कांग्रेस पार्टी के वामपक्षीय दल ने गत नागपुर अधिवेशन में कृषि को भी सहकारिता के सिद्धांत पर करना या कराना श्रेयष्कर समझा है. इस योजना को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयां उपस्थित हुईं, इसलिए कृषि अभी तक सहकारी बुनियाद पर चल नहीं सकी. आगे क्या होगा, ठीक से कहा नहीं जा सकता.

feedback@chauthiduniya.com

भारत के विभिन्न राज्यों में सहकारी संस्थाओं के नियमन के लिए विभिन्न क़ानून बने हुए हैं. उदाहरण के लिए बंबई सहकारी संस्था एक्ट के सिद्धांत तो सही हैं, पर इस देश में, जहां शिक्षा का नितांत अभाव है, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ कर क्या उचित ढंग से अपना मत दे सकता है? मान लीजिए, आपने एक सहकारी संस्था का स्टोर बनाया, जिसके द्वारा जीवनोपयोगी हर वस्तु उचित मूल्य पर हर मेंबर को मिलेगी. यह संभव इस तरह से होता है कि बहुत सी खाद्य सामग्री, पहनने के लिए कपड़े और अन्य बहुत सी चीजें सरकार से नियंत्रित मूल्य पर मिल जाती हैं या पैदा करने वालों से सीधे बिना किसी बिचौलिए की कमीशन के मिल जाती हैं.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

यह देश के लिए परीक्षा की घड़ी है

जितना हम अनुभव करते हैं, उससे ज़्यादा कठिन दौर से हमारा देश गुज़र रहा है. 1991 में हुए आर्थिक सुधारों ने ढेर सारी संभावनाएं पैदा कीं, जिन्होंने इस बात की उम्मीद बढ़ाई कि देश की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी. पिछले बीस सालों में बहुत सारी घटनाएं घटीं. आर्थिक विकास दर में लगातार वृद्धि हुई, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास में देखा जा सकता है. बड़े और छोटे शहरों में सड़कों, फ्लाई ओवरों एवं माल्स आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ. मध्य वर्ग ने अच्छा विकास किया. लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगीं और वे इससे बेहतर सुधार की आवश्यकता महसूस करने लगे. कारों की संख्या लगातार बढ़ती रही. हर महीने नई कारें बाज़ार में आती रहीं. लेकिन आज आर्थिक विकास में गिरावट देखने को मिल रही है. आर्थिक विकास दर 8-9 फ़ीसदी से गिरकर 7 फ़ीसदी या उससे कम हो गई है.

बाज़ार में अवसाद की स्थिति छाने लगी है और पूंजीपतियों को चिंता सताने लगी है. हम इस बात को भूल गए हैं कि आज़ादी के बाद चालीस सालों तक इस देश की आर्थिक विकास दर 3-4 फ़ीसदी रही थी. आज भी चीन को छोड़ दिया जाए तो विश्व के लगभग सभी देशों की आर्थिक विकास दर 3 फ़ीसदी के आसपास ही है. दूसरी तरफ़ देश के ग़रीब लोगों एवं आदिवासियों के मन में काफी गुस्सा है. उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वे ख़ुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. माओवादी हिंसा इसी का परिणाम कही जा सकती है, जिसे रोकने के लिए बर्बर पुलिसिया कार्रवाई की जाती है. ऐसे ही वातावरण में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाया, जिसने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दीं. पश्चिमी देशों की तर्ज पर उच्च विकास दर और प्रतिस्पर्द्धा की नीति पर प्रश्न उठने लगे हैं. एक तरफ़ इस तरह की व्यवस्था लाई जाए और दूसरी तरफ़ कॉरपोरेट क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात हो, यह समझ से परे है. पश्चिमी देशों में भी भ्रष्टाचार मुक्त कॉरपोरेट संस्कृति संभव नहीं है.

अगर अन्ना हजारे के आंदोलन को तार्किक रूप से समाप्त हुआ मान लिया जाए तो फिर हमें इसके विकल्प की तलाश करनी है. एक बात यह कही जा सकती है कि वर्तमान संसद ने लोगों का नेतृत्व करना बंद कर दिया है. ऐसे में फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए. दूसरी बात यह कही जा सकती है कि संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती ही नहीं है और अब इसके विकल्प की तलाश करने का वक़्त आ गया है. अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्तमान संसदीय व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें सांसद धनबल और बाहुबल की बदौलत चुनाव जीतकर आते हैं, तो फिर हमें इसके विकल्प के बारे में सोचना होगा. हमारे पड़ोस और पश्चिम एशिया के कुछ देशों में सत्ता की बागडोर सेना के हाथ में है. इससे पहले कि हम उस अराजक स्थिति में आ जाएं, जबकि लोग किसी तरह की ज़िम्मेदारी के बिना जो चाहें करना शुरू कर दें, हमें इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. हम इस व्यवस्था में भी सुधार कर सकते हैं. अगर हम केवल इस व्यवस्था की खामियों की ओर इशारा करेंगे और इसमें सुधार करने के बजाय इसे त्यागने की बात सोचेंगे तो उसका विपरीत परिणाम निकल सकता है. जैसी व्यवस्था वर्तमान समय में है, उससे भी ख़राब स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

बाघ तो बच गए, पर बेटियां?

ख़बर है कि बीते दस वर्षों में हमारे देश में बाघों की तादाद बढ़ी है, लेकिन ख़बर यह भी है कि इस दौरान छह साल की उम्र की बच्चियों की संख्या तेज़ी से घटी है. बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, पर कन्या शिशुओं का क्या होगा? वह तो आज भी उपेक्षित-असुरक्षित है, वह भी अपने परिवार के ही अंदर. परिवारवालों द्वारा गर्भ में ही मार दी जाती है. अगर बच गई तो पांच साल की होने तक कुपोषण से मार दी जाती है. पिछड़े राज्यों में ग़रीबी और अशिक्षा के कारण उतनी बच्चियां नहीं मरी होंगी, जितनी महंगे चिकित्सा संसाधनों के माध्यम से गर्भपात कराकर मार दी गईं. अगर यही हाल रहा तो कन्या पूजन के लिए लड़कियां कहां से आएंगी?

-नीलम, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश.

धर्म के आधार पर आरक्षण पहले से है

केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की घोषणा करते ही भाजपा नेताओं के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया और उनका मुस्लिम विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनक़ाब हो गया. संविधान के अनुच्छेद 341 में पारित नियम 1950 में जो आरक्षण अनुसूचित जातियों को प्रदान किया गया, उसमें कहा गया है कि यह आरक्षण केवल हिंदू धर्म की अनुसूचित जातियों को ही दिया जाएगा. उसके बाद सिख नेताओं द्वारा विरोध करने पर 1956 में उन अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया, जो सिख धर्म से संबंध रखती हैं. 1990 में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के विरोध पर एक बार फिर संशोधन हुआ और बौद्ध धर्म की अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ दिया गया, जबकि मुस्लिम और ईसाई धर्म की अनुसूचित जातियों को आज तक आरक्षण के लाभ से दूर रखा गया. जब संविधान में पहले से ही धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है तो फिर मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर इतनी हाय तौबा क्यों?

-रफ़ीक़ चौहान, *ई-मेल से.*

मुसलमानों को आरक्षण मिले

देश की एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है. आज़ादी के बाद मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली गई. सरकार द्वारा बनाई गईं समितियों की रिपोर्टों में भी कहा गया है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा बदतर है. साथ ही उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की भी सिफ़ारिशें की हैं. सरकार को चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को झुनझुना थमाने के बजाय उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करे, ताकि उनकी हालत बेहतर हो सके.

-असलम ख़ान, *दिल्ली.*

कीटनाशकों के दुष्प्रभाव

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-भोजन में मीठा ज़हर पढ़ा, अच्छा लगा. किसान अपने फ़ायदे के लिए क़ीटनाशकों और उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे खाद्य पदार्थों में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद नुक़सानदेह है. बाज़ार में प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री इस समस्या को बढ़ा रही है.

-रविकांत आनंद, *खगड़िया, बिहार.*

हलचल

महंगाई का शोर है
भ्रष्टाचार का ज़ोर है,
कशमकश में है आदमी
हलचल हर ओर है,
साधु-संत राजनीति में उतरे
प्रवचनों का दौर है,
सांसद लड़ते लोकसभा में
मचा हुआ घनघोर है,
कौन सही, कौन ग़लत है
हर कोई लगता चोर है,
बुद्धिजीवी हैं लाचार
सरकार भी कमज़ोर है,
असमंजस में पड़ी है जनता
आशंका पुरज़ोर है,
प्रकाश की किरण दिखती नहीं
अंधियारा फैला हर ओर है.

-सीताराम शर्मा, *सीकर, राजस्थान.*

रामदेव को नसीहत

योगगुरु रामदेव ने योग मंचों को राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दिया है. लगता है कि रामदेव का सपना देश पर शासन करने का है, जो कभी पूरा नहीं होगा. देश में ऐसे साधु-संतों की कमी नहीं, जिन्होंने अपने उद्देश्य से हटकर राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कहीं के नहीं रहे. रामदेव को चंद्रास्वामी, बाबा जय गुरुदेव और महर्षि धीरेंद्र ब्रह्मचारी से सबक़ लेना चाहिए.

-शिबली रामपुरी, *सहारनपुर, उत्तर प्रदेश.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस ने केंद्रीयकरण की नीति अपना कर राज्य की स्वायत्तता छीनने की कोशिश की थी. 1947 के बाद समय बदल गया है.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

उत्तर प्रदेश की जनता को हस्तक्षेप करना चाहिए

अखिलेश यादव के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी. अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह यादव के पुत्र. डी पी यादव को पार्टी में न लेने की घोषणा ने उनकी पार्टी में भी मतभेद पैदा किए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा को कॉर्नर पर खड़ा कर दिया. आम तौर पर माना जाता है कि अगर यह फ़ैसला मुलायम सिंह को लेना होता तो वह संभवत: डी पी यादव को पार्टी में लेने के लिए हरी झंडी दे देते, लेकिन अखिलेश यादव ने निजी तौर पर यह फ़ैसला लिया और यह फ़ैसला उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय के ख़िलाफ़ लिया. आजम खान घोषणा कर चुके थे कि डी पी यादव समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिए गए हैं. आज़म खान ने शायद यह सोचा होगा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुसलमानों के समर्थन के लिए इतने ज़्यादा लालायित हैं कि वे उनके किसी भी बयान का खंडन नहीं करेंगे, पर अखिलेश यादव ने तत्काल कहा कि डी पी यादव पार्टी में नहीं लिए जाएंगे.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहन सिंह को लगा कि अखिलेश यादव पार्टी में ताक़तवर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फ़ैसला है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व यह फ़ैसला करेगा कि डी पी यादव को पार्टी में लिया जाए या न लिया जाए. मोहन सिंह के इस बयान को 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया. ये घटनाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों का अपराधियों या दागी लोगों के प्रति जिस तरह का रुझान है, उसे देखते हुए अखिलेश यादव ने यह फ़ैसला लिया. अखिलेश यादव ने एक तरफ यह फ़ैसला लिया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भूकंप आ गया. बाबू सिंह कुशवाहा और बादशाह सिंह को गुपचुप तरीके से, उत्तर प्रदेश भाजपा की ग़ैर जानकारी में, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के घर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया. इसमें राजनाथ सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई. बाबू सिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार के आरोप में बसपा से निकाले गए. उन पर पिछले चार सालों से यह आरोप लग रहे थे कि वह दोनों हाथों से पैसे लूट रहे हैं और यह पैसा वह मायावती के नाम पर ले रहे थे कि उन्हें पैसा मायावती को पहुंचाना है.

चाहे नोएडा हो या आगरा, उत्तर प्रदेश का कोई कोना हो, कहीं पर भी कोई कॉरपोरेशन अगर कोई डील करता था तो बिल्डर्स से कहा जाता था कि बाबू सिंह कुशवाहा से बात करके आओ. बाबू सिंह कुशवाहा के घर पर डील होती थी और बिल्डर्स एक बड़ा कमीशन मुख्यमंत्री मायावती के नाम पर बाबू सिंह कुशवाहा को दे देते थे. किसी ने भी आज तक पैसा मायावती को अपने हाथ से नहीं दिया, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा अवश्य मायावती के नाम पर पैसे लेते रहे. बाबू सिंह कुशवाहा को भाजपा में शामिल करने का फ़ैसला भाजपा के गले की हड्डी बन गया. एक तरफ सुषमा स्वराज एवं अरुण जेटली इस फ़ैसले से भन्ना गए, वहीं लालकृष्ण आडवाणी को लगा कि उनकी भ्रष्टाचार विरोध की सारी यात्रा उत्तर प्रदेश के नेताओं ने मटियामेट कर दी. जैसा भी माहौल उन्होंने बनाया, उसे उत्तर प्रदेश के नेताओं ने जानबूझ कर बिगाड़ दिया. भाजपा को आनन–फानन में यह घोषणा करनी पड़ी कि वह बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं देगी, जबकि उन्हें चुनाव लड़ाने के नाम पर ही पार्टी में लाया गया था.

बाबू सिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार के आरोप में बसपा से निकाले गए. उन पर पिछले चार सालों से यह आरोप लग रहे थे कि वह दोनों हाथों से पैसे लूट रहे हैं और यह पैसा वह मायावती के नाम पर ले रहे थे कि उन्हें पैसा मायावती को पहुंचाना है. चाहे नोएडा हो या आगरा, उत्तर प्रदेश का कोई कोना हो, कहीं पर भी कोई कॉरपोरेशन अगर कोई डील करता था तो बिल्डर्स से कहा जाता था कि बाबू सिंह कुशवाहा से बात करके आओ.

दरअसल, यह स्थिति बताती है कि राजनीति में हम कितने नीचे स्तर पर आ गए हैं. सीट लेने के लिए हम किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, चाहे उस आदमी की साख शून्य हो गई हो. भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मार दिया, अब ऐसा कहा जा सकता है. अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन करना, परोक्ष में यह घोषणा करना कि अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे हमने ही सारे देश में लोगों को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ तैयार किया. उसके बाद लोकसभा में अन्ना हजारे के क़दमों का चालाकी से समर्थन करना और अब जब परीक्षा का वक़्त आया तो सबसे पहले अन्ना हजारे के सिद्धांतों को लात मारकर भ्रष्टाचारियों को गले लगा लेना और यह कहना कि हम गंगा हैं, जो भी इसमें नहाएगा, वह पवित्र हो जाएगा. यानी जितने भ्रष्टाचारी हैं, वे अगर भाजपा की गंगा में चले जाएं तो पवित्र हो जाएंगे. यह सब आख़िर क्या साबित करता है. इस बयान को सुनकर गुरु गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय एवं रज्जू भैया की आत्माएं रो रही होंगी. भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि आत्मा होती है. अगर आत्मा होती है तो वह जार–जार रो रही होगी. मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी इस ख़बर को सुनकर अपने कमरे में अकेले बैठे आंसू बहा रहे होंगे.

भाजपा ने अपने मृत इतिहास पुरुषों का तो अपमान किया ही, अभी उसके पास एक मात्र व्यक्तित्व लालकृष्ण आडवाणी हैं, उनकी भी आशाओं को धो दिया गया. भारतीय जनता पार्टी को इसका ख़ामियाज़ा और कोई नहीं, उसके मतदाता ही शायद चुकाने का मौका दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को उसका यह तरीका, यह क़दम कतई पसंद नहीं आया. मज़े की बात यह कि लोगों की इतनी राय जानने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा पर बेशर्मी से तीन–तीन दिनों तक मीटिंग कर रही है. भाजपा में भ्रष्टाचारियों को लें या न लें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी या केंद्रीय नेता तीन–तीन दिनों तक बैठकर बातें कर रहे हैं. कमाल है भारतीय जनता पार्टी! यह भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है. यह भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी और बाबू सिंह कुशवाहा की भारतीय जनता पार्टी है. उत्तर प्रदेश के लोगों की आंखें इस घटना से खुल जानी चाहिए और उन्हें इसके लिए इसे सबक सिखाना चाहिए, ताकि आगे से राजनीति में ऐसे लोगों को रोकने की संभावना खड़ी हो जाए, जो बेशर्मी के साथ न केवल भ्रष्टाचार करते हैं, बल्कि लाठी, डंडे और गोली की सियासत करना चाहते हैं. इलेक्शन कमीशन या सरकार का रोल कम है, आम आदमी के वोट का रोल बहुत ज़्यादा है. इसलिए ऐसे क़दम उठाने और ऐसी सियासत करने वालों के ख़िलाफ़ अगर किसी का सबसे बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है तो वह उत्तर प्रदेश की जनता का हो सकता है और उत्तर प्रदेश की जनता यह हस्तक्षेप करेगी, ऐसा मेरा मानना है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

दो ख़ुदकुशी और एक क़त्ल

नए साल की समाप्ति का रास्ता क्या है. हम शुरू करते हैं अन्ना हजारे के अनशन और जेल भरो आंदोलन की धमकी से, जिसके बारे में 27 दिसंबर की दोपहर के बाद पता चल गया था कि उनका यह आंदोलन मुंबई में असफल रहा. दिल्ली की बात कुछ और है. यह ऐसा शहर है, जहां राजनीति का प्रभाव है, शक्ति का केंद्र है, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है. वहां तो एक साथ कई क्षेत्रों की प्रधानता है और राजनीति को दूसरा दर्जा भी प्राप्त नहीं है. मैंने पहले ही अनशन को उबाऊ और अप्रभावी बताया था, जो अब साबित भी हो गया है. अन्ना ने 28 दिसंबर को अनशन समाप्त और जेल भरो आंदोलन स्थगित कर, आगे का कार्यक्रम निश्चित न करके एक तरह से आत्महत्या कर ली. इस बीच एक बात और देखने को मिली. अन्ना हजारे की धमकी से मुक्त होने के बाद यूपीए सरकार ने भी आत्महत्या कर ली. इसकी शुरुआत सोनिया गांधी के उस बयान के साथ हुई कि कांग्रेस लोकपाल पर लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. उनकी पार्टी अव्यवस्थित रही. यहां तक कि वह अपनी पार्टी के सभी सांसदों को लोकसभा में रोके रखने में भी असफल रहीं. मैंने भी कम ही इस तरह के

लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कांग्रेस पारित नहीं करा पाई. यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी. कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को पहली बार में ही इतना बड़ा झटका लगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव उन्हीं का था. कांग्रेस ने लोकपाल बिल लोकसभा में पारित कराया, जिसका कारण दोस्ताना तरीक़े से सपा और बसपा के सांसदों द्वारा सदन से बाहर चले जाना था.

नेतृत्व वाला संसदीय दल देखा है, जिसमें पार्टी प्रमुख अपने दल को व्यवस्थित भी न कर सका हो. 27 दिसंबर को लोकसभा में कुछ ऐसा ही देखा गया.

लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कांग्रेस पारित नहीं करा पाई. यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी. कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को पहली बार में ही इतना बड़ा झटका लगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव उन्हीं का था. कांग्रेस ने लोकपाल बिल लोकसभा में पारित कराया, जिसका कारण दोस्ताना तरीक़े से सपा और बसपा के सांसदों द्वारा सदन से बाहर चले जाना था. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख़ों की घोषणा को माना जा सकता है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस समय सबसे अहम मुद्दा मुस्लिम वोट पाना है. कांग्रेस ने नरसिम्हाराव के समय ही मुस्लिमों का समर्थन खो दिया था, जब वह बाबरी मस्जिद को ढहने से नहीं रोक पाए थे. मुलायम सिंह ने इसका फ़ायदा उठाया और मुस्लिमों को अपने पक्ष में कर लिया. कांग्रेस अब फिर से मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है. यही कारण है कि कांग्रेस ने लोकपाल में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का प्रावधान रखा है. इसी कारण सपा और बसपा ने लोकसभा का बहिष्कार किया, जबकि भाजपा के कई संशोधनों का समर्थन किया गया.

लोकसभा में लोकपाल बिल पारित हो गया, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने का संशोधन पारित नहीं हो सका. इस तरह का लोकपाल प्रभावशाली नहीं हो सकता. सीबीआई की स्वायत्तता भी सुनिश्चित नहीं की गई. इसके बाद के दो दिन तो और भी ख़राब रहे. राज्यसभा को एक दिन में ही स्थगित कर दिया गया. यहां लोकपाल बिल पारित नहीं हो पाया. इसका मतलब यह है कि अब लोकपाल बिल संशोधनों के साथ फिर से लोकसभा में नहीं जा सकेगा. यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी. संसद को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इसे जान सकता है. ऐसा जानबूझ कर किया गया है या फिर इसे सरकार की अक्षमता कहा जा सकता है. कांग्रेस इस कदर दिवालिया हो गई है कि उसके पास भाजपा की आलोचना करने के अलावा और कुछ कहने को बचा ही नहीं है. कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक सुधार के लिए ज़रूरी दो तिहाई बहुमत न ला पाने के लिए भी भाजपा ज़िम्मेदार है. अगर कांग्रेस भाजपा को कोसना छोड़ दे तो वह उसका सहयोग प्राप्त कर सकती है. अपनी अक्षमता के लिए कांग्रेस भाजपा को क्यों दोष दे रही है. कांग्रेस या यूपीए सरकार ने 27 दिसंबर को आत्महत्या की और 29 दिसंबर को संसदीय लोकतंत्र की हत्या कर दी. इसकी वजह उसकी कायरता थी. राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था और तृणमूल कांग्रेस भी उसका विरोध कर रही थी. ममता बनर्जी मेरी पसंदीदा नहीं हैं, लेकिन इतना तो है कि उनके द्वारा लाया गया संशोधन प्रभावशाली था.

कांग्रेस ने केंद्रीयकरण की नीति अपना कर राज्य की स्वायत्तता छीनने की कोशिश की थी. 1947 के बाद समय बदल गया है. अब राज्यों के पास अपनी ताक़त और पहचान है. यह संघीय व्यवस्था का ही परिणाम है कि केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है, जिसका ख़ामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है. देखा जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता लोकपाल बिल पारित न हो पाने के लिए भाजपा पर आरोप बौखलाहट वश ही लगा रहे थे. यह सही रवैया नहीं कहा जा सकता. राज्यसभा में लोकपाल बिल पर हुई बहस के अंतिम आधे घंटे में कांग्रेस ने हंगामा कराने की रणनीति अपनाई, ताकि मतदान न हो सके और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाए. यह सारा नाटक इसलिए किया गया, ताकि राज्यसभा में कांग्रेस को पराजय का मुंह न देखना पड़े. कांग्रेस ने 29 दिसंबर की मध्य रात्रि को लोकतंत्र की हत्या कर दी. इसे किसी भी तरह से किसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता. अगर ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहीं तो लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गई सरकार पर से लोगों का भरोसा धीरे–धीरे उठ जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

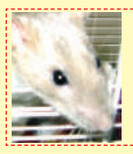

साइंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन के अगुवा इनबाल बेन एमी बर्टल ने कहा कि हम इन चूहों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं.

दिल्ली, 16 जनवरी-22 जनवरी 2012

चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

सरकारी दस्तावेज़ या कार्य का निरीक्षण करें

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइल, किसी भी विभाग द्वारा कराए गए काम का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई सड़क बनाई गई है और आप उसके निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं या सड़क की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो आप निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले अंक में देंगे. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि किसी सरकारी फाइल का निरीक्षण कैसे किया जा सकता है और यह क्यों ज़रूरी है. कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग से सूचना मांगते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अमुक सूचना एक हज़ार पृष्ठों की है और इसके लिए आपको एक ख़ास शुल्क अदा करना होगा.

कुछ मामलों में तो आवेदक से लाखों रुपये मांगे गए. पिछले दिनों बिहार के एक आवेदक से सूचना उपलब्ध कराने के बदले कई लाख रुपये जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन यह सब कुछ सिर्फ़ आवेदक को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है. इसके पीछे सरकारी अधिकारियों की मंशा यह होती है कि ऐसा करने से आवेदक सूचना की मांग नहीं करेगा, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि इस मामले में थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, आवेदन तैयार करने और सवाल पूछने के तरीक़ों में. मसलन, अगर किसी ख़ास फाइल में से कुछ ख़ास सूचनाएं ही चाहिए, तो आवेदक को पूरी सूचना मांगने के बजाय फाइल निरीक्षण के लिए आवेदन करना चाहिए. हम आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करने वाले सभी आवेदकों को सलाह देना चाहेंगे कि जब कभी उन्हें किसी फाइल से कोई सूचना मांगनी हो तो अपने आवेदन में एक सवाल फाइल निरीक्षण को लेकर भी जोड़ें या फिर आप चाहें तो उक्त फाइल के निरीक्षण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. आरटीआई एक्ट की धारा 2 (जे) (1) के तहत आप इसकी मांग कर सकते हैं. इस अंक में हम कार्य एवं फाइल निरीक्षण से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ई-मेल या फोन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(कार्यों/दस्तावेजों का निरीक्षण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
कृपया मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दी जाए:-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (जे)(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार है. इसके तहत मैं निम्नलिखित कार्य का निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे तिथि, समय एवं स्थान बताएं, जब मैं आकर इस कार्य की जांच कर सकूं.
(कार्य का विवरण)
2. मैं निरीक्षण के समय इस कार्य से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों का भी निरीक्षण करना चाहूंगा, इसलिए निरीक्षण के समय उक्त दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराएं:-
क. मेज़रमेंट बुक
ख. खर्चों का विवरण
ग. रेखाचित्र
इन दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी तो कानून के तहत निर्धारित शुल्क लेकर प्रतियां उपलब्ध कराएं.
3. धारा-2 (जे)(3) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सरकारी निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई सामग्री का प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार है. इसके तहत मैं उपरोक्त कार्य में प्रयोग की गई सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूं. नमूना मेरे द्वारा तय स्थान से मेरी उपस्थिति में विभाग द्वारा एकत्र किया जाए और यह सीलबंद हो तथा विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि सीलबंद नमूना कार्य की सामग्री का असली नमूना है. कृपया मुझे स्थान, समय एवं तिथि सूचित करें, जब मैं प्रमाणित नमूने के लिए आ सकूं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम..........
पता..........
फोन नं..........
संलग्नक..........

ज़रा हट के

इमोशनल चूहे

इमोशनल अत्याचार अब सिर्फ़ इंसानों में नहीं, बल्कि चूहों में भी देखा जा सकता है. एक अनुसंधान कहता है कि वे दयालु और उदार होते हैं. शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने प्रयोग के लिए चूहों को जोड़ों में रखा, ताकि वे एक-दूसरे को जान सकें. इसके बाद उन्होंने एक चूहे को चूहेदानी के भीतर और दूसरे को उसी में स्थित एक पारदर्शी ट्यूब में रख दिया और फिर पाया कि पहला चूहा काफी निराश हुआ. हैरान करने वाली बात यह रही कि चूहेदानी में फंसे अपने साथी के लिए पारदर्शी ट्यूब वाला चूहा भी काफी परेशान नज़र आया. दिलचस्प बात यह कि चुहिया चूहों की तुलना में अधिक संवेदनशील पाई गईं. प्रयोग के दौरान पाया गया कि चूहेदानी में फंसे चूहे को देखकर दूसरा चूहा काफी गुस्से में था. इससे साबित हुआ कि वह उसकी तकलीफ देखकर व्यथित था. इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि आज़ाद चूहा यह समझ गया कि कैसे ट्यूब से उसे निकाला जा सकता है. साइंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन के अगुवा इनबाल बेन एमी बर्टल ने कहा कि हम इन चूहों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं. वे अंदर की भावना से प्रेरित होकर सीख रहे हैं. हम उन्हें नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे चूहेदानी का दरवाजा खोला जाए. प्रयोग में पाया गया कि चूहेदानी में रखे गए खिलौने को छुड़ाने में चूहों की दिलचस्पी नहीं थी. वे वास्तविक चूहे के लिए ही बेचैन थे. बर्टल ने कहा कि दरवाजा खोलना काफी कठिन था, लेकिन वे अनवरत प्रयास करते रहे और आख़िरकार सफल रहे. प्रयोग के अगले चरण में उन्हें चॉकलेट लेकर लालच दिखाकर परखा गया. हैरानी की बात थी कि आज़ाद चूहों ने फंसे साथी को मुक्त कराने तक मनपसंद चॉकलेट नहीं खाया. अनुसंधानकर्ता पेगी मैसन ने कहा कि यह काफी भावनात्मक था. चॉकलेट की तुलना में उन्हें चूहेदानी में फंसे चूहे की अधिक चिंता थी. रिपोर्ट के अनुसार, चूहों की तुलना में चुहियों द्वारा अपने साथी को छुड़ाने के लिए किया गया अधिक प्रयास उनके मातृत्व गुण को दर्शाता है कि वे अधिक उदार और दयालु होती हैं.

श्रद्धांजलि

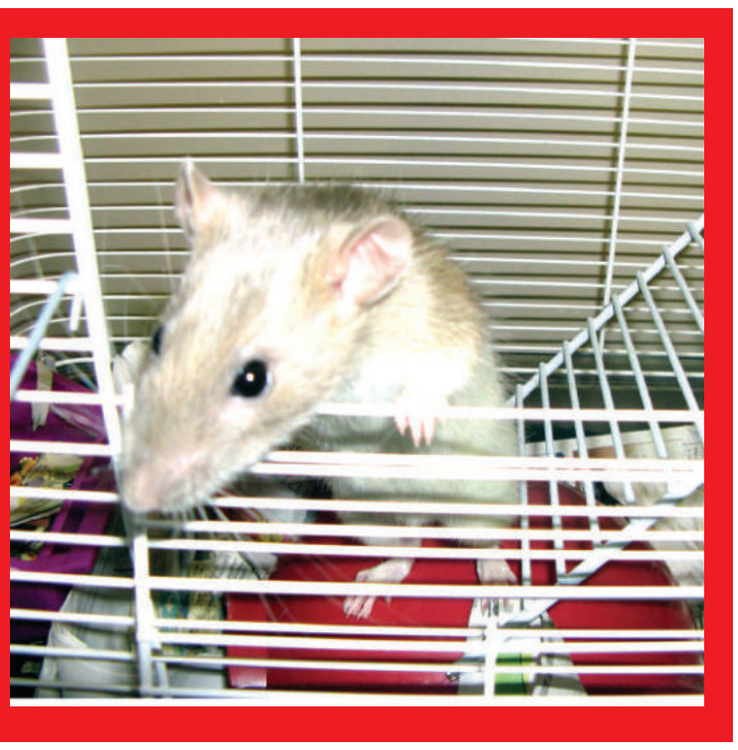

शैलेंद्र दुबे हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे

शैलेंद्र दुबे जिस उम्र में थे, वह उम्र जाने की नहीं होती. वह बहुत हंसमुख, मिलनसार और ठोस ख्याल के व्यक्ति थे. उन्होंने बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जिया और सादगी के ही रास्ते ईश्वर के पास चले गए. उनकी मित्र मंडली में जिन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वे पत्रकार थे. शैलेंद्र जी के निधन का समाचार पाकर जिस तरह पत्रकार बिरादरी उनके पार्थिव शरीर के आसपास खड़ी हो गई और दोनों दिन उनके साथ रही, वह यह दर्शाता है कि शैलेंद्र जी पत्रकारों के बीच कितने लोकप्रिय थे. उनका परिवार मुंबई में रहता था. शैलेंद्र जी जहां रहते थे, वह सातवीं मंजिल का फ्लैट था. उस सोसायटी में लिफ्ट की सुविधा नहीं थी. शैलेंद्र जी इस उम्र में आकर कुछ बीमारियों के शिकार हो गए थे. इसके बावजूद उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट नहीं लिया. अगर वह चाहते तो ऐसा फ्लैट ले सकते थे. दिन में तीन-चार बार ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, पर इसके बावजूद वह अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना सात मंजिल चढ़ते और उतरते थे. शैलेंद्र जी कमल मोरारका के काफी विश्वसनीय सहयोगी थे. वह कमल जी को प्यार से बापू कहते थे और कमल जी की आंख का इशारा समझते थे. शैलेंद्र जी अक्सर अपने यहां पत्रकारों को बुलाते थे. वह शाम इतनी शानदार और यादगार होती थी, वह आयोजन इतना भव्य होता था कि पत्रकार बिरादरी उसका इंतजार करती थी. यह सब शैलेंद्र जी के व्यक्तित्व का ही असर था.

शैलेंद्र दुबे चौथी दुनिया के पहले प्रकाशक थे. चौथी दुनिया जब 1986 में शुरू हुआ तो कमल मोरारका ने उन्हें बुनियादी सुविधाएं जुटाने, बुनियादी ज़मीन बनाने और चौथी दुनिया की टीम को कोई दिक्कत और परेशानी न हो, इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी. शैलेंद्र दुबे इसी कोशिश में रहते थे कि चौथी दुनिया के पत्रकारों को कभी कोई परेशानी न हो. शैलेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे. समूची पत्रकार बिरादरी, ख़ासकर चौथी दुनिया परिवार के लिए उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है. चौथी दुनिया परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि शैलेंद्र जी की आत्मा को शांति मिले और उनकी यादें हमारे दिलों में सदा बनी रहें.

पेट में कार्बेज डंप

भारत में अजब-ग़ज़ब घटनाएं बहुत आम हैं. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में चिकित्सकों ने एक मरीज के पेट का ऑपरेशन कर छह किलो लोहा निकाला है, जिसमें ढेरों सिक्के, चाबियां और नट बोल्ट शामिल हैं. इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई. कोरबा शहर के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर के सर्जन डॉक्टर एस एन यादव के मुताबिक़, जिले के कोरकोमा गांव निवासी आदिवासी युवक कलेश्वर (25) के पेट का ऑपरेशन करके छह किलो लोहा बाहर निकाला गया, जिसमें 431 सिक्के, 196 नट बोल्ट, 17 पिनें और तीन चाबियां शामिल हैं. कुछ दिनों पहले कलेश्वर को पेट दर्द की शिकायत हुई तो उसने एक स्थानीय चिकित्सक की सलाह ली, जिसने उसे दवा तो दी, लेकिन पेट दर्द ठीक नहीं हुआ. तब उसने कोरबा पहुंच कर अपनी जांच कराई. यादव ने बताया कि उक्त युवक के पेट की सोनोग्राफी और एक्स-रे करने के बाद चिकित्सकों को उसके अमाशय में बाहरी वस्तुएं होने की जानकारी मिली. इसके बाद ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया. कुल मिलाकर उसके पेट में अच्छा-खासा कार्बेज डंप बन चुका था.

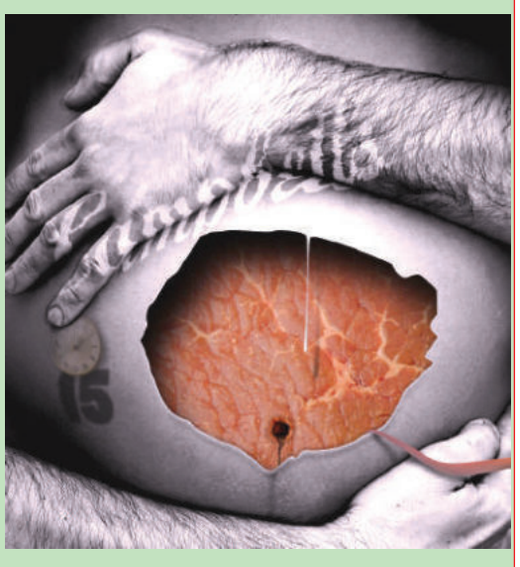

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
व्यर्थ की उलझनों में समय और धन नष्ट होगा. काफी समय के बाद कुछ कर दिखाने का मौक़ा आपको मिल रहा है. कोई भी काम छोटा नहीं होता. एक-एक सीढ़ी चढ़कर ऊंचाई पर पहुंचा जाता है. रातोंरात कोई चमत्कार हो जाए, यह संभव नहीं है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
प्रगति का मार्ग प्रशस्त रहेगा, समस्याएं हल होंगी. यह समय आगे बढ़ने के लिए अच्छा है. सज्जन लोग आपको समर्थन देंगे. यदि किसी खास क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाहते हैं तो उसके लिए सप्ताह का मध्य अनुकूल सिद्ध होगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आर्थिक संकोच नष्ट होंगे, कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. कोई न कोई संकट या लफड़ा आपके आगे खड़ा हो सकता है. जहां तक हो सके, कूटनीति और तरकीब से काम निकालने की कोशिश करें. आपके कर्मचारी या सहयोगी इस वक्त आपके लिए संदेह का पर्याय बने हुए हैं.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
ज्ञान-विज्ञान में वृद्धि होगी, परंतु रचनात्मक कार्यों में अवरोध आएगा. भाग्य कर्म से बनता है. सप्ताह मध्य तक आपके सभी कामों में विघ्न-बाधाएं उत्पन्न आएंगी, लेकिन उसके बाद अच्छे समाचार और संदेश मिल सकते हैं. कारोबार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
अभियान और प्रपंचों के कारण खिल्ली न उड़े, इसका ध्यान रखें. कारोबार में कोई अच्छी घटना घटने वाली है. सहयोगी और पार्टनर कोई अच्छी डील फाइनल कर सकते हैं. घर के छोटे सदस्यों के लिए जो कार्यक्रम या योजना आपने बना रखी है, उसमें आने वाली रुकावट ख़त्म हो जाएगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
किसी की दवा-तीमारदारी में समय और धन ख़र्च होगा. कोई शारीरिक परेशानी आपको चैन नहीं लेने दे रही है. यदि आप परिवारीजनों और नज़दीकी लोगों पर निर्भर रहेंगे तो कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
मित्रगणों के बीच मान-सम्मान होगा, अच्छे समाचार मिलेंगे. काफी समय से रुका हुआ धन मिलेगा या फिर किसी नए कारोबार के रास्ते खुल सकते हैं. आपके उत्साह और कार्यक्षमता को देखते हुए कोई लंबा अनुबंध या अग्रिम आपके हाथ लग सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
कामकाज की व्यस्तता रहेगी. मौसम के बदलते मिज़ाज की तरह आपकी योजनाएं भी बदलती रहती हैं. सप्ताह का मध्य आर्थिक मामलों में अच्छी ख़बर लेकर आ रहा है. दौड़-भाग का सुफल मिलेगा. धैर्य और लगन बनाए रखें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
अस्थायी काम और उद्योग स्थायी होंगे. आर्थिक लाभ होगा. यदि आप अकेले कुछ नहीं कर पाए तो संगठन या साझे में ही कुछ कर दिखाएं. प्रेमी या जीवनसाथी पर अशुभ ग्रहों का विपरीत असर पड़ सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
घरेलू क्लेश परेशान करेंगे, ख़र्च भी अधिक होगा. शत्रु और विरोधी कभी-कभी आपको जागृत और क्रियाशील रखते हैं. खाने-पीने और बातचीत के प्रति आपकी अरुचि बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र या व्यापार स्थल पर किसी से बहसबाजी होने का डर है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
मौलिक चिंताएं पैदा होंगी, पर कुछ नई योजनाएं भाग्योदयकारी सिद्ध होंगी. काफी जोड़-घटाव के बाद भी आपका आर्थिक बोझ कम नहीं हो पा रहा है. एक के बाद एक खर्चे आपके सामने मुंह बाए खड़े हैं. आप पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से घिरे हैं.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
कट्टर शत्रु और विरोधी परास्त होंगे. थोड़ी सी अच्छाई ग्रहण करने से आपका व्यक्तित्व निखर आएगा. कई कारणोंवश आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव चल रहे हैं. ज़मीन-जायदाद के मामले भी चिंता का विषय बने हुए हैं. जो कुछ आप अर्जित कर रहे हैं, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

धार्मिक स्थलों पर हमले का मतलब है कि हमलावर किसी न किसी तौर पर धार्मिक उन्माद से ग्रस्त हैं. ये हमले हिंदुओं एवं मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों पर हुए हैं.

अमेरिका

मार्ग से भटकते नागरिक

राजीव कुमार

संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति को मेल्टिंग पॉट संस्कृति कहा जाता है. मतलब यह कि वहां रहने वाले लोग चाहे किसी देश, समुदाय, धर्म या क्षेत्र से आए हों, लेकिन अमेरिका आने के बाद उन्हें उसी संस्कृति का हिस्सा बनकर रहना पड़ेगा, जिसे अमेरिका ने स्वीकार किया है. मेल्टिंग पॉट संस्कृति का मतलब है सभी संस्कृतियों का मिश्रण, जिसमें किसी की अपनी पहचान नहीं बचती है, बल्कि सभी की पहचान केवल अमेरिकी के रूप में रह जाती है. इस देश को अपनी इस संस्कृति पर नाज़ है. अमेरिका में हाल में हुई घटना से तो यह लगता है कि वहां के कुछ लोग अपनी संस्कृति से भटक गए हैं. उन्हें दूसरे धर्मों के लोगों के धार्मिक स्थलों से चिढ़ होने लगी है. वे उनके धार्मिक आयोजनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वे अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं, जिसका ख़ामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है. हाल में अमेरिका के न्यूयार्क शहर में मंदिर और मस्जिद सहित चार जगहों पर बमों से हमले हुए. इन हमलों का कारण क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस किसी ने यह हमला किया है, वह धार्मिक कट्टरता की भावना से प्रेरित रहा होगा. इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह कैसे कहा जा सकता है कि अगर इस बार जान नहीं गई तो अगली बार भी ऐसा ही होगा. ये हमले दो विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों पर हुए. अगर ये हमले किसी दूसरे देश के लोगों के घरों पर हुए होते तो कहा जा सकता था कि स्थानीय लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि अमेरिका में आकर ये लोग उनका रोज़गार छीन रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर हुए इन हमलों को आर्थिक कारणों से नहीं जोड़ा जा सकता है.

धार्मिक स्थलों पर हमले का मतलब है कि हमलावर किसी न किसी तौर पर धार्मिक उन्माद से ग्रस्त हैं. ये हमले हिंदुओं एवं मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों पर हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दोनों धर्मों के प्रति अमेरिकियों में आक्रोश है और यह आक्रोश इतना बढ़ता जा रहा है कि अब वे इन धर्मों को वहां बर्दाश्त नहीं करना चाहते. हमले का शिकार हुए धार्मिक स्थल न्यूयार्क के उस इलाक़े में स्थित हैं, जहां एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं. न्यूयार्क में रहने वाले कुछ मुसलमानों का कहना है कि पुलिस उनकी निगरानी कर रही है. ग़ौरतलब है कि इन हमलों के एक दिन पहले वहां के मेयर ने एक भोज दिया था, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन उस भोज का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया था. उन्हें शक है कि उनके धार्मिक स्थल पर हुआ हमला कहीं उसी बहिष्कार की प्रतिक्रिया तो नहीं है. हो सकता है कि इस हमले का भोज वाली घटना से कोई ताल्लुक न रहा हो, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि मुस्लिमों के मन में कहीं न कहीं इस बात का संदेह है कि अमेरिका में उनका धर्म सुरक्षित नहीं है. कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पहले से ही इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि इस्लाम ख़तरे में है. मुस्लिम समुदाय के जिन पढ़े-लिखे नौजवानों को गुमराह किया जाता है, जिन्हें आतंकवादी बनाया जाता है, उन्हें यही बताया जाता है कि उनका धर्म ख़तरे में है और यह ख़तरा जिन देशों ने पैदा किया है, उनमें अमेरिका प्रमुख है. अमेरिका को वे अपना शत्रु मानते हैं. जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चरमपंथी संगठनों का काम और भी आसान हो जाता है.

9/11 की घटना के बाद अमेरिका में मुसलमानों पर हमले किए गए थे. यही नहीं, वहां ऐसे हमले दूसरे समुदाय के लोगों, जैसे सिखों पर भी किए गए थे, क्योंकि वे पगड़ी पहनते हैं, जिसके कारण हमलावर उन्हें पठान समझ बैठते हैं.

9/11 की घटना के बाद अमेरिका में मुसलमानों पर हमले किए गए थे. यही नहीं, वहां ऐसे हमले दूसरे समुदाय के लोगों, जैसे सिखों पर भी किए गए थे, क्योंकि वे पगड़ी पहनते हैं, जिसके कारण हमलावर उन्हें पठान समझ बैठते हैं. चरमपंथियों ने इन हमलों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित किया था, ताकि युवाओं का माइंड वास किया जा सके. इस बार हमले धार्मिक स्थलों पर हुए हैं. इसे अमेरिका की आतंकवाद विरोधी मुहिम के मार्ग का रोड़ा कहा जा सकता है.

बहरहाल, अमेरिकी प्रशासन को इन हमलों के लिए ज़िम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और न केवल उन्हें इस अपराध के लिए सज़ा देनी होगी, बल्कि यह भी पता लगाना होगा कि हमलों का कारण क्या है. अमेरिकी प्रशासन को यह विश्वास दिलाना होगा कि वहां रहने वाले सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की दोहरी नीति नहीं अपनाई जा रही है. इस घटना की जांच कर रही टीम ने आशंका ज़ाहिर की है कि कहीं यह हेट क्राइम तो नहीं है. अगर उसका अनुमान सही निकला तो इस पर गंभीरता से विचार करना होगा. ऐसी घटनाएं एक साथ कई प्रश्नों को जन्म देती हैं. ऐसे प्रश्न उन सभी लोगों के मन में उठते हैं, जिन्हें लक्ष्य बनाया जाता है. यह हमला किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है कि अपराधी को सज़ा देकर मामला रफा-दफा कर दिया जाए. यह किसी समुदाय विशेष की आस्था पर हमला है, जिससे उनकी भावना आहत होती है. अगर किसी समुदाय की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसका परिणाम बहुत घातक होता है. वहां रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक ख़ुद को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं. अगर अमेरिका शांति चाहता है तो उसे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े क़दम उठाने होंगे. इसके लिए शस्त्र से ज़्यादा शास्त्र की ज़रूरत होती है. अत: यह ज़रूरी है कि अमेरिका इस तरह के धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए शास्त्र का सहारा ले. ऐसी घटनाओं के परिणामों के बारे में लोगों को बताए, ताकि वह अपनी छवि और अधिक धूमिल होने से बचा सके.

feedback@chauthiduniya.com

चीन को करारा जवाब देना होगा

भारत का रवैया चीन के प्रति हमेशा दोस्ताना रहा है. भारत की हमेशा यही कोशिश रही है कि चीन के साथ उसके संबंध अच्छे हों. इसके लिए वह शुरू से ही सकारात्मक प्रयास करता रहा है, लेकिन चीन एक तरफ़ तो भारत को अपना मित्र बताता है, वहीं दूसरी तरफ़ उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि किसी भी तरह उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत ने चीनी आक्रमण के दंश को भूलने की कोशिश करके उसके साथ फिर से संबंधों को सुधारना चाहा. चीन भी इसके लिए प्रयास करता है, लेकिन उसका प्रयास महज़ दिखावा होता है. वह भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने की तो भरपूर कोशिश करता है, लेकिन भारत को नीचा दिखाने या उसे कमज़ोर करने का कोई भी मौक़ा अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता. वह जब अपना नक्शा पेश करता है तो भारत के कुछ प्रदेशों को उसमें शामिल कर लेता है. सीमा पर उसके सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसकर उत्पात मचाते हैं. अभी दोनों के बीच सीमा संबंधी विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है. ऐसे में हाल की एक घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है.

चीन के यिवू क्षेत्र में दो भारतीय व्यापारी दीपक रहेजा एवं श्याम सुंदर अग्रवाल को अगवा कर लिया गया था. उन पर आरोप लगाया गया कि वे जिस कंपनी में काम करते थे, उसने स्थानीय व्यापारियों के बकाए का भुगतान नहीं किया है. यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी का मालिक फरार हो गया है. मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, इन दोनों व्यापारियों को छुड़ाने के लिए जब भारतीय राजनयिक एस बालचंद्रन न्यायालय गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. राजनयिक को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, क्योंकि वह केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि किसी देश का प्रतिनिधि होता है, लेकिन भारतीय राजनयिक के साथ विशेष व्यवहार की बात तो दूर, उनके साथ सामान्य शिष्टाचार और मानवीय व्यवहार भी नहीं किया गया. भारतीय राजनयिक डायबिटीज से पीड़ित हैं, लेकिन पांच घंटे चली अदालती कार्रवाई के दौरान जब उन्हें कुछ खाने या दवा लेने की ज़रूरत पड़ी तो उसकी इजाज़त नहीं दी गई. वह बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. हालांकि राजनयिक के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, लेकिन इसे काफी नहीं कहा जा सकता. भारत ने कहा कि वह अपने राजनयिकों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता. भारत के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन राहुल छाबड़ा ने भी इस घटना की आलोचना की और कड़ी आपत्ति जताई. विदेश मंत्रालय ने भारत में चीन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुलाया और इस घटना पर चिंता व्यक्त की. भारत में चीन के राजदूत से भी इसका जवाब मांगा गया. हालांकि विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद दोनों भारतीय व्यापारियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है. विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने तो कह दिया कि वह चीनी राजदूत के साथ हुई मुलाकात के बाद संतुष्ट हैं और उनकी आशंकाओं का समाधान हो गया है, लेकिन क्या सचमुच केवल व्यापारियों की रिहाई से संतुष्ट हुआ जा सकता है?

चीन में भारतीय दूतावास ने भारतीय व्यापारियों को कहा है कि वे यिवू इलाक़े में व्यापार करने से परहेज करें. दूतावास का कहना है कि अनुभव यह बताता है कि इस तरह की किसी घटना के बाद तुरंत न्यायिक सहायता मिलना काफी मुश्किल होगा, लेकिन यह कहना क्या किसी समस्या का समाधान हो सकता है? चीन का यिवू इलाक़ा पूर्वोत्तर एशिया का व्यवसायिक गढ़ माना जाता है. ऐसे में भारतीय व्यापारी इस क्षेत्र में व्यापार करने से परहेज क्यों करें? उन्हें सुरक्षा प्रदान करना तो सरकार की ज़िम्मेदारी है, उसे यह प्रयास करना चाहिए कि भारतीय व्यापारियों को चीन में किसी तरह की परेशानी न हो. चीन से इस बारे में बात की जानी चाहिए कि अगर वह हमारे व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे सकता है तो भारत में उसके व्यापारियों के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी चीन की सरकार की होगी, न कि भारत सरकार की. आख़िर कब तक हम तुष्टिकरण की नीति पर चलते रहेंगे. कभी न कभी तो चीन को करारा जवाब देना ही होगा. चीन के सामने हम इतने मजबूर क्यों दिखते हैं. अगर भारत में चीनी व्यापारियों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए तो क्या चीन चुप बैठेगा? जिस तरह का दुर्व्यवहार भारतीय राजनयिक के साथ किया गया, उससे भारत के प्रति चीन की सोच का पता चलता है. चीन अभी भी भारत को 1962 से पहले वाला भारत मानता है. जब तक हम उसे इस बात का एहसास नहीं दिला देते कि भारत अब काफी आगे निकल गया है और चीन की किसी भी कार्रवाई का जवाब दे सकता है, तब तक वह भारत के प्रति अपना रवैया बदलने वाला नहीं है. विदेश मंत्री चाहे जितनी भी सफाई दें, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में हो रहे सुधार पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

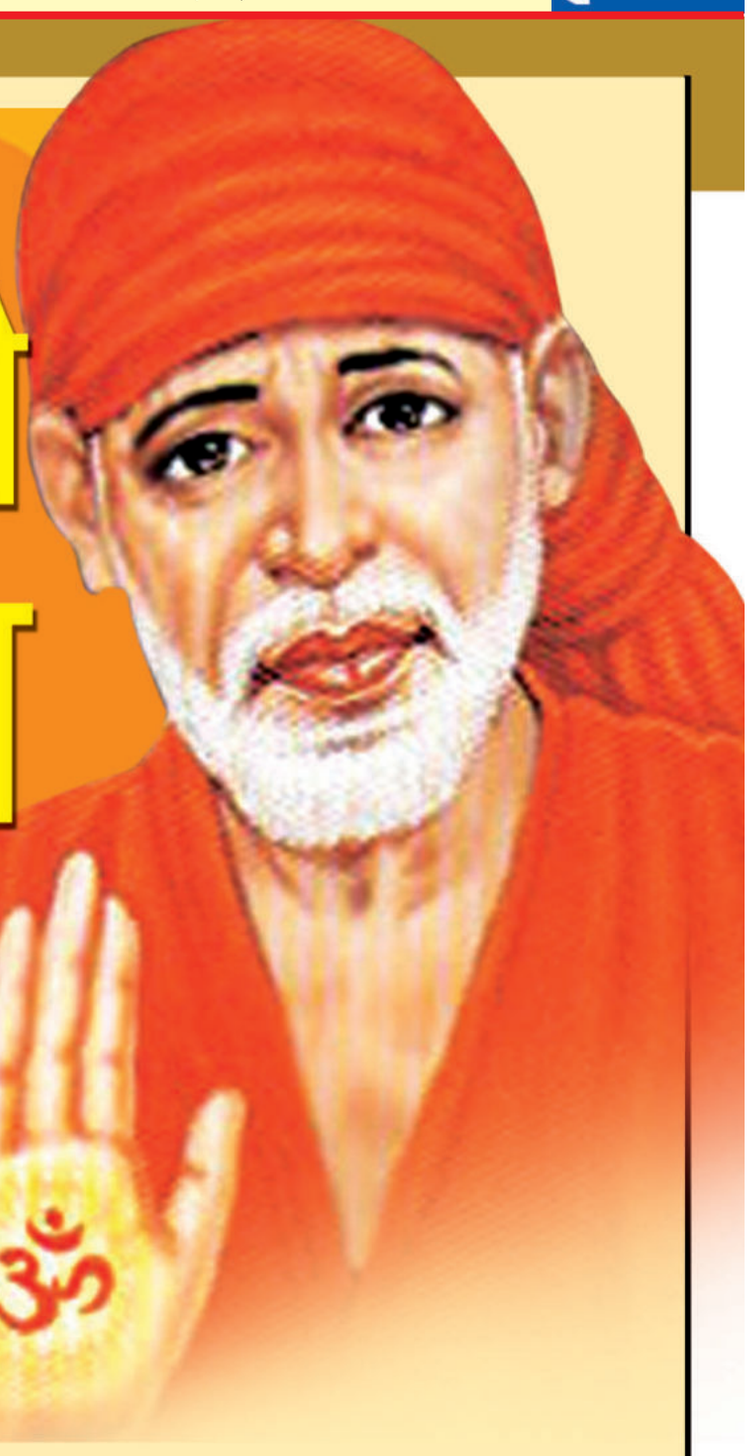

प्रदेश में वर्ष 1800 से लेकर 2011 तक बनी कुल 63 जेलों में से 53 आज़ादी के पहले की और 10 आज़ादी के बाद की हैं.

सद्गुरु की पहचान

जो वेद, वेदांत एवं छहों शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो, जो अपनी श्वांसोच्छवास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक् चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं है. बल्कि जो अपने आचरण से लौकिक एवं पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण करके हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे, जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान (आत्मानुभूति) करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं. जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित हों, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार आत्मानुभूति करा सकते हैं. सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्यों से कोई लाभ या सेवा की लालसा नहीं करते, बल्कि स्वयं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं. उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं महान हूं और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु वे उसे अपने ही सदृश (या ब्रह्मस्वरूप) समझते हैं. सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है. वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का ही गर्व होता है. उनके लिए राजा-रंक, स्वर्ग-नर्क सब एक ही समान है.

हेमाड पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साई बाबा सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति और उनका कृपापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. वह अपने यौवन काल में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह नहीं करते थे, न उनके बाल-बच्चे एवं मित्र थे, न घर-बार था और न उन्हें किसी का आश्रय प्राप्त था. 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था.

हेमाड पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साई बाबा सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति और उनका कृपापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. वह अपने यौवन काल में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह नहीं करते थे, न उनके बाल-बच्चे एवं मित्र थे, न घर-बार था और न उन्हें किसी का आश्रय प्राप्त था. 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था. वह निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते और सदा आत्मलीन रहते थे. वह सदैव भक्तों की नि:स्वार्थ भक्ति देखकर उनकी इच्छानुसार आचरण करते थे. उनका कहना था कि मैं सदा भक्तों के पराधीन रहता हूं. जब वह शरीर में थे, उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें भी उसी प्रकार के अनुभव होते रहते हैं. भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ठ है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्ज्वलित करें तो ज्ञान ज्योति (आत्म साक्षात्कार) स्वयं प्रकाशित हो उठेगी. प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है. ऐसा ज्ञान किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं हो सकता, प्रेम भाव में संतोष नहीं होता. इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए. प्रेमांकुर उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याणरूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है. जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती. इसलिए जहां व्याकुलता और प्रेम है, वहां भगवान स्वयं प्रगट हो जाते हैं. भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का माध्यम है. यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो यह निश्चित है कि वह तर जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

यहां की जेलें यातना गृह हैं

राकेश यादव

राज्य की जेलों में वास्तविक क्षमता से चार गुना अधिक संख्या में रखे गए बंदी किस तरह का जीवन जीते होंगे, इसकी कल्पना भी डराती है, साथ ही यह आज़ाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रश्नचिन्ह भी है. आख़िर शासन और सरकार में आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे राजनेताओं ने आज तक इन जेलों की बंदी धारण क्षमता के विस्तार की कोई ज़रूरत क्यों नहीं समझी? जबकि वे ख़ुद इन्हीं जेलों में आ-जाकर अपनी नेतागीरी चमकाने का काम करते रहे हैं. चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज़ प्रदेश के जेलों की नारकीय स्थिति के सबूत हैं. इनमें जेलों की बंदी धारण क्षमता, बंदियों की मौजूदा संख्या, पिछले पांच वित्तीय वर्षों में किस जेल को कितना धन मिला, किसने कितना ख़र्च किया, इन जेलों में श्रम कर रहे बंदियों को कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है और जो दिया जा रहा है, क्या वह न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के मानकों के अनुरूप है, आदि तमाम जानकारियां हैं.

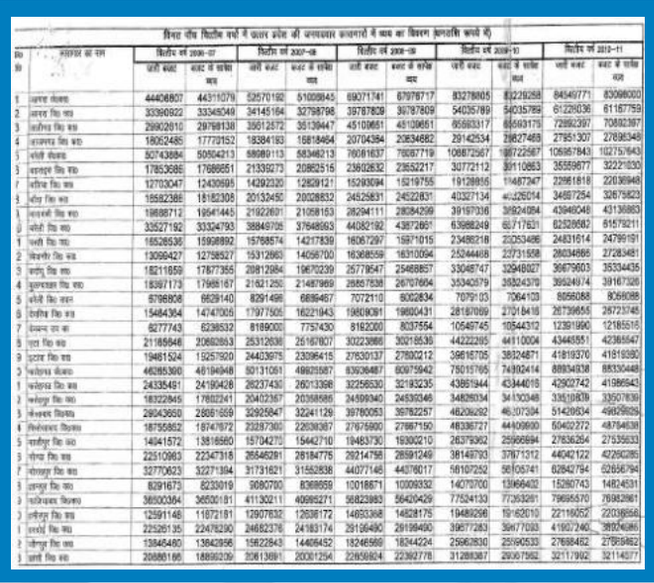

प्रदेश में वर्ष 1800 से लेकर 2011 तक बनी कुल 63 जेलों में से 53 आज़ादी के पहले की और 10 आज़ादी के बाद की हैं. सबसे पुरानी वर्ष 1800 में बनी ज़िला जेल जौनपुर की है, जबकि सबसे नई 2011 में बनी ज़िला जेल महराजगंज की है. लखनऊ, नैनी, बरेली, आगरा एवं वाराणसी में केंद्रीय जेल हैं, जबकि फ़ैज़ाबाद मंडल जेल बी श्रेणी, दोषसिद्ध बंदियों को रखने के लिए बनाई गई इकलौती जेल है, जिसका निर्माण 1840 में हुआ था. किशोर सदनों एवं नारी निकेतनों को छोड़कर सभी जेलें ज़िला कारागार हैं. इनमें सबसे छोटी ललितपुर ज़िला जेल है. जहां तक जेलों की बंदी धारण क्षमता की बात है तो मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, लखनऊ के पत्रांक-18/शोध एवं प्र.सु. अनु.-5 के अनुसार, प्रदेश की कुल 63 जेलों में 46,216 की वास्तविक बंदी धारण क्षमता की जगह 82,935 बंदी हैं यानी क्षमता से लगभग दो गुना अधिक. सर्वाधिक कष्टकारी स्थिति ज़िला जेल देवरिया के बंदियों की है, जहां 293 की क्षमता के सापेक्ष 1068 बंदी हैं यानी क्षमता से लगभग 4 गुना अधिक. महोबा एवं देवबंद में भी क्षमता से तीन गुना अधिक बंदी हैं. मुज़फ्फरनगर, इटावा एवं मुरादाबाद में भी यही हाल है. फ़ैज़ाबाद मंडल कारागार में क्षमता से दो गुना अधिक बंदी हैं. केंद्रीय कारागारों में सबसे दयनीय हालत वाराणसी की है, जहां ढाई गुना अधिक बंदी हैं. बमुश्किल आधा दर्जन जेलों को छोड़कर शेष में क्षमता से डेढ़, दो, तीन अथवा चार गुना अधिक बंदी हैं.

प्रदेश की 60 जेलों को वित्तीय वर्ष 2006-07 में आवंटित 1,41,30,24,497 रुपये के सापेक्ष 1,39,23,97,119 रुपये, 2007-08 में 1,54,41,59,391 के सापेक्ष 1,50,22,61,133, 2008-09 में 1,90,60,64,652 के सापेक्ष 1,89,27,25,400, 2009-10 में 2,56,37,39,627 के सापेक्ष 2,53,33,23,196, 2010-11 में 2,86,56,68,959 के सापेक्ष 2,80,55,11,749 रुपये ख़र्च किए गए. जबकि महराजगंज, कन्नौज एवं बलरामपुर ज़िला जेलों को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में शासन से एक रुपया भी नहीं मिला. नारी बंदी निकेतनों को सिर्फ़ वित्तीय वर्ष 2010-11 में 1,12,87,157 रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से मात्र 92,27,164 रुपये ख़र्च किए गए. आश्चर्य की बात यह है कि करोड़ों रुपये ख़र्च होने के बावजूद किसी भी जेल में अतिरिक्त बैरकों का निर्माण नहीं कराया गया. ऐसा करने की ज़रूरत किसी ने आख़िर क्यों नहीं महसूस की. जेल प्रशासन इस समस्या के प्रति गंभीर क्यों नहीं है, वह बंदियों की दिक्कतों की अनदेखी क्यों कर रहा है?

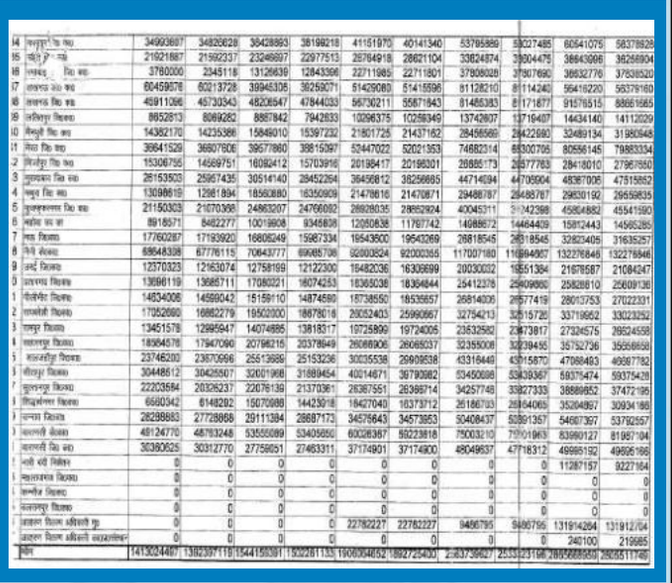

एक अहम बात यह है कि पत्र संख्या-30771/उद्योग-1/32/2010 दिनांक 16-12-2010 के संदर्भ में राज्यपाल के शासनादेश संख्या-489 पी/22/4-2000-48 (43)/99 दिनांक 6-4-2000 के हवाले से कहा गया है कि उन दोषसिद्ध एवं विचाराधीन बंदियों, जिनके द्वारा स्वेच्छा से कारागारों में संचालित उद्योगों, कृषि, बागवानी, पाकशाला एवं अन्य विभिन्न कार्यों में श्रम किया जाता है, को कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रम के बदले देय मज़दूरी की दर क्रमश: 18, 13 और 10 रुपये से बढ़ाकर क्रमश: 40, 30 और 25 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है. बढ़ी हुई दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी, लेकिन दस्तावेज़ों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह देय पारिश्रमिक न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अंतर्गत है अथवा नहीं. यहां की विभिन्न जेलों में उक्त पारिश्रमिक दिए जाने का कार्य किस हद तक किया जा रहा है, यह भी पूरी तरह संदिग्ध है.

यहां की जेलों में मानवाधिकारों की बात बेमानी साबित हो रही है. समय-समय पर जेल भरो आंदोलन के तहत जेलों में पहुंचने वाले राजनेता बंदियों के जीवन के इस कड़वे सच का स्वाद आख़िर क्यों नहीं चख सके? दरअसल, लोकतंत्र के चुनावी उत्सव में भागीदारी से बंदियों का वंचित होना ही उनका दुर्भाग्य बन गया है. अगर बंदी भी वोट दे सकते तो शायद राजनेताओं और राजनीतिक दलों को उनकी कोई फ़्रिक होती, शासन-प्रशासन भी उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करता. जेलों की बंदी धारण क्षमता के विस्तार की ज़रूरत एक ऐसा प्रश्न है, जिसके उत्तर की प्रतीक्षा हर उस बंदी को है, जो इन जेलों में जानवरों जैसी ज़िंदगी जी रहा है. इन जेलों की बंदी धारण क्षमता तुरंत बढ़ाई जानी चाहिए, साथ ही उनके श्रम के बदले उन्हें विधिक रूप से आदेशित मज़दूरी दिलाने के लिए प्रभावी एवं कारगर उपाय किए जाने चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

Prisoner's Capacity, Population& EstablishmentYear of Prisons in Uttar Pradesh

कई विश्वविद्यालयों में जाने और वहां की प्रक्रिया को देखने-जानने के बाद मेरी यह धारणा बनी थी कि विश्वविद्यालयों में शोध प्रबंध बेहद जटिल और शास्त्रीय तरीक़े से पुराने विषयों पर ही किए जाते हैं.

अनंत विजय

बार-बार वर्धा

क़रीबन दस-ग्यारह महीने बाद एक बार फिर वर्धा जाने का मौक़ा मिला. वर्धा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने का मौक़ा था. दो छात्रों हिमांशु नारायण और दीप्ति दाधीच के शोध को सुनने का अवसर मिला. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में यह एक अच्छी परंपरा है कि पीएचडी के लिए किए गए शोध को जमा करने के पहले छात्रों, शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. कई विश्वविद्यालयों में जाने और वहां की प्रक्रिया को देखने-जानने के बाद मेरी यह धारणा बनी थी कि विश्वविद्यालयों में शोध प्रबंध बेहद जटिल और शास्त्रीय तरीक़े से पुराने विषयों पर ही किए जाते हैं. मेरी यह धारणा साहित्य के विषयों के इर्द-गिर्द बनी थी. जब महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के छात्रों से मिलने और उनके शोध सुनने का मौक़ा मिला तो मेरी यह धारणा थोड़ी बदली. हिमांशु नारायण के शोध का विषय भारतीय फीचर फिल्म और शिक्षा से जुड़ा था, जबकि दीप्ति ने इंडिया टीवी और एनडीटीवी का तुलनात्मक अध्ययन किया था. दोनों के अध्ययन में कई बेहतरीन निष्कर्ष देखने को मिले.

हिमांशु ने तारे जमीं पर और थ्री इडियट जैसी फिल्मों के आधार पर श्रमपूर्वक कई बातें कहीं, जिन पर ग़ौर किया जाना चाहिए. हिमांशु ने पांच सौ से ज़्यादा लोगों से बात करके उनकी राय को अपने शोध प्रबंध में शामिल किया है, जो उसे प्रामाणिकता प्रदान करती है. उसके शोध के प्रेजेंटेशन के समय कई सवाल खड़े हुए. यह देखना बेहद दिलचस्प था कि दूसरे विषयों के छात्र या फिर उसके ही विभाग के छात्र भी पूरी तैयारी के साथ आए थे, ताकि शोध करने वाले अपने साथी छात्रों को घेरा जाए. सुझाव और सलाह के नाम पर जब छात्र खड़े हुए तो फिर शुरू हुआ ग्रीलिंग का सिलसिला, जिसे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय अंकित ने रोका. दीप्ति का शोध बेहद दिलचस्प था. एनडीटीवी और इंडिया टीवी की तुलना ही अपने आप में दिलचस्प विषय है. ख़बरों को पेश करने का दोनों चैनलों का बेहद अलहदा अंदाज है, लेकिन दो साल के अपने शोध के बाद दीप्ति ने यह निष्कर्ष दिया कि समाचारों में कमी आई है और न्यूज़ चैनलों पर मनोरंजन बढ़ा है. दोनों चैनलों की कई हज़ार मिनटों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करने के बाद उसके निष्कर्ष दिलचस्प थे और चौंकाने वाले भी. वर्धा जाकर एक बार फिर बापू की कुटी या आश्रम में जाने का मन करने लगा था. दूसरे दिन सुबह-सुबह वर्धा के ही गांधी आश्रम पहुंच गया, जो विश्वविद्यालय से आधे घंटे की दूरी पर स्थित है. वहां पहुंच कर एक अजीब तरह की अनुभूति होती है. वातावरण इस तरह का है, लगता है कि आप वहां घंटों बैठ सकते हैं. तक़रीबन दस महीने पहले जब वर्धा गया था तो भी गांधी आश्रम गया था. वहां गांधी जी की कई वस्तुएं रखी हैं, गांधी का बाथ टब, मालिश टेबल एवं चक्की आदि. उनके बैठने का स्थान भी सुरक्षित रखा हुआ है. पिछली बार जब गया था तो वहां बंदिशें कम थीं, लेकिन इस बार पाबंदियां इस वजह से ज़्यादा थीं, क्योंकि कुछ महीनों पहले वहां रखा बापू का ऐनक चोरी चला गया था. ऐनक चोरी हो जाने के बाद वहां रहने वाले कार्यकर्ताओं ने थोड़ी ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी. गांधी जिस कमरे में बैठते थे, वहां बैठने के बाद आप उनके सिद्धांतों को महसूस कर सकते हैं. एक अजीब सा एहसास. गांधी आश्रम में हम चार लोग गए थे यानी मैं, अनिल राय जी, विश्वविद्यालय के शिक्षक मनोज राय और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर सी पी सिंह. वहां इस बार मेरी मुलाकात गांधी जी के वक़्त से आश्रम में रह रहीं कुसुम लता ताई से हुई. वह गांधी जी के कमरे के बाहर बैठी थीं. वहां हम उनके साथ बैठे, बतियाए. हम एक ऐसी महिला के साथ बैठे थे, जिन्होंने गांधी को न सिर्फ़ देखा था, बल्कि उनके आश्रम में कई साल तक उनके साथ रही थीं. बातचीत के क्रम में मैंने उनसे गांधी जी के बारे में पूछा. गांधी कैसे थे, वह कैसे रहा करते थे, आदि-आदि. गांधी, कस्तूरबा और जय प्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती के बारे में उन्होंने कई बातें बताईं.

उनसे प्रभावती देवी और जय प्रकाश के बारे में बात करते हुए मुझे गोपाल कृष्ण गांधी की कुछ बातें याद आ गईं, जो उन्होंने अपनी किताब-ऑफ अ सर्टेन एज में लिखी हैं. गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है, जय प्रकाश नारायण को गांधी जी जमाई राजा मानते थे, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए जय प्रकाश के अमेरिका चले जाने के बाद प्रभावती जी गांधी के साथ वर्धा में ही रहने लगी थी और बा एवं बापू दोनों उन्हें पुत्रीवत् स्नेह करते थे. दरअसल, जय प्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई की लड़की थीं. वर्धा के आश्रम में रहने के दौरान बापू और कस्तूरबा दोनों उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगे. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी और कस्तूरबा को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया. वहां बा की तबीयत बिगड़ गई तो गांधी ने 6 जनवरी, 1944 को अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि दरभंगा जेल में बंद प्रभावती देवी को पुणे जेल में स्थानांतरित किया जाए, ताकि कस्तूरबा की उचित देखभाल हो सके. उस पत्र में गांधी ने लिखा कि प्रभावती उनकी बेटी की तरह हैं. ये बातें कुसुमलता ताई ने भी बताईं. उन्होंने कहा कि बा और बापू दोनों प्रभावती देवी को बेटी की तरह मानते थे.

गोपाल कृष्ण गांधी ने गांधी और जय प्रकाश के बीच पहली मुलाकात का दिलचस्प वर्णन किया है. उनके मुताबिक़ , तक़रीबन सात साल बाद जब जय

प्रकाश नारायण अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अमेरिका से भारत लौटे तो अपनी पत्नी से मिलने वर्धा गए, जहां वह गांधी के सानिध्य में रह रही थीं. पहली मुलाकात में गांधी ने जय प्रकाश से देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलन के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि उन्हें ब्रह्मचर्य पर लंबा उपदेश दिया. बताते हैं कि गांधी जी ने प्रभावती जी के कहने पर ही ऐसा किया, क्योंकि प्रभावती जी शादी तो क़ायम रखना चाहती थीं, लेकिन ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ. जय प्रकाश नारायण ने अपनी पत्नी की इस इच्छा का आजीवन सम्मान किया. तभी तो गांधी जी ने एक बार लिखा, मैं जय प्रकाश की पूजा करता हूं. गांधी जी की यह राय 25 जून, 1946 को एक दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित भी हुई थी. गांधी से जय प्रकाश का मतभेद भी था. गांधी जय प्रकाश के व्यक्तित्व में एक प्रकार की अधीरता भी देखते थे, लेकिन बावजूद इसके वह कहते थे कि जय प्रकाश एक फकीर हैं, जो अपने सपनों में खोए रहते हैं. कुसुमलता ताई ने भी जय प्रकाश और प्रभावती के बारे में कई दिलचस्प किस्से सुनाए. इसके अलावा देश की वर्तमान हालत और राजनीति के बारे में भी कुसुमलता ताई से लंबी बातचीत हुई. उसके बाद हम लोग वापस विश्वविद्यालय लौटे. वहां भी कुलपति विभूति नारायण राय की पहल पर गांधी हिल्स बना है. गांधी हिल्स पर बापू का ऐनक, उनकी बकरी, उनकी चप्पलें और उनकी कुटी बनाई गई है. आप वहां घंटों बैठकर गांधी के दर्शन के बारे में मनन कर सकते हैं बग़ैर ऊबे. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में गांधी के बाद अब कबीर हिल्स बन रहा है, जहां कबीर से जुड़ी यादें ताजा होंगी. बार-बार वर्धा जाना और गांधी से जुड़ी चीजों को देखना, पढ़ना और चर्चा करना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है, जिसे सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

सर्वश्रेष्ठ पत्र लेखकों का सम्मान

चौथी दुनिया उर्दू में प्रकाशित होने वाले पत्रों में से हर सप्ताह एक सर्वश्रेष्ठ पत्र को पुरस्कृत किया जाता है. पुरस्कार के रूप में उक्त पत्र के लेखक को क़ौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू द्वारा एक हज़ार रुपये की पुस्तकें प्रदान की जाती हैं. पिछले दिनों चौथी दुनिया के कार्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में काउंसिल के निदेशक डॉ. हमीदुल्ला भट, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के महासचिव एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वसी अहमद नोमानी और चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ पत्र लेखकों को प्रशस्ति पत्र एवं पुस्तकें देकर सम्मानित किया. इस मौक़े पर डॉ. भट ने कहा कि पत्र लिखना एक अच्छी आदत है. पत्रों के माध्यम से अख़बारों को नए-नए प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है. एडवोकेट वसी अहमद नोमानी ने कहा कि किसी भी अख़बार के लेखों को पढ़ना एक बात है, लेकिन उसे पढ़ने के बाद अख़बार को पत्र लिखकर अपने विचार रखना बड़ी बात है. इससे यह समझ में आता है कि पाठक क्या सोचते हैं. चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने कहा कि हमने उर्दू के माध्यम से समाज की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को सरकार तक और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है. अगर पाठकों का समर्थन मिलता रहा और लोग इसी तरह पत्र लिखकर बाख़बर करते रहे तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा. चौथी दुनिया उर्दू की संपादक वसीम राशिद ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाठक भविष्य में भी चौथी दुनिया को इसी तरह पत्र लिखकर अपने विचारों-प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
कथा-समय में तीन हमसफ़र

लेखिका
निर्मला जैन

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
300 रुपये

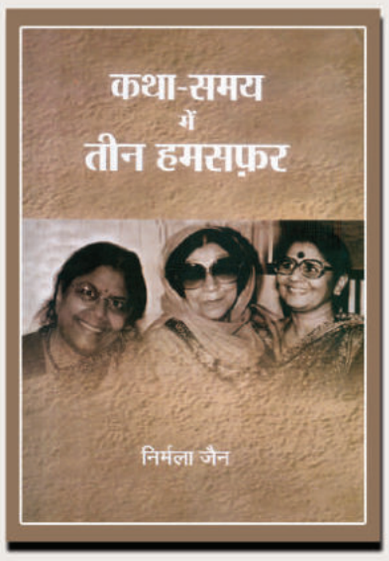

आलोचना की यह किताब लेखिका कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा पर आधारित है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

कंपनी को उम्मीद है कि युवा एग्ज़ीक्यूटिव्स और कॉलेज छात्रों के बीच यह फोन पसंद किया जाएगा.

पैनासोनिक के नए एसी

पैनासोनिक इंडिया के प्रेसिडेंट डायजो इटो, निदेशक (सेल्स एंड मार्केटिंग) मनीष शर्मा एवं कार्यकारी निदेशक (उत्पादन, पैनासोनिक होम एप्लायंसेस एयर कंडीशनिंग मलेशिया) सिल्वाराजू के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी मौजूद थीं. स्प्लिट एसी की नई सीरीज आधुनिकतम इकोनेवी से सुसज्जित है.

पैनासोनिक ने स्प्लिट एसी वर्ग में क्यूब एसी की अपग्रेडेट सीरीज के साथ-साथ व्यापारिक वर्ग के लिए एसी के नए मॉडल पेश किए. इस अवसर पर पैनासोनिक इंडिया के प्रेसिडेंट डायजो इटो, निदेशक (सेल्स एंड मार्केटिंग) मनीष शर्मा एवं कार्यकारी निदेशक (उत्पादन, पैनासोनिक होम एप्लायंसेस एयर कंडीशनिंग मलेशिया) सिल्वाराजू के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी मौजूद थीं. स्प्लिट एसी की नई सीरीज आधुनिकतम इकोनेवी से सुसज्जित है. इकोनेवी एक इंटेलिजेंट सेंसर टेक्नोलॉजी है, जो इंसान की स्थिति, गतिविधि स्तर, अनुपस्थिति और कमरे में सूर्य के प्रकाश की तीव्रता की पहचान कर सकती है.

इकोनेवी तकनीक बिजली की बचत करती है. स्प्लिट एयर कंडीशनर श्रेणी में पैनासोनिक ने 11 अलग-अलग सीरीजों में 65 मॉडल पेश किए हैं. इन एयर कंडीशनरों की क़ीमत 17,000 से लेकर 60,000 रुपये तक है. नई क्यूब एसी सीरीज चार रंगों यानी सफेद, रूबी, डार्क ग्रे और डार्क ब्राउन में उपलब्ध होगी. कंपनी ने सिंगल पैकेज एयर कंडीशनरों के 16 मॉडलों और 60 एचपी तक की वीआरएफ सीरीज को बाज़ार में उतारा है. इस अवसर पर पैनासोनिक होम एप्लायंसेस की ब्रांड एंबेसडर कैटरीना कैफ ने कहा कि कंपनी से जुड़कर उन्हें काफी ख़ुशी हुई. पैनासोनिक ने क्यूब एसी की सीरीज का भी विस्तार किया है. निदेशक (सेल्स एंड मार्केटिंग) मनीष शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता और व्यवसायिक सेक्टर में एयर कंडीशनिंग समाधान के सर्वाधिक व्यापक पोर्टफोलियों के साथ कंपनी का उद्देश्य स्प्लिट एसी वर्ग में 25 फ़ीसदी बाज़ार हिस्सेदारी हासिल करना है.

कंपनी के स्प्लिट एसी मॉडल इकोनेवी तकनीक से युक्त हैं, जो ग्राहकों को क्वालिटी सॉल्यूशन उपलब्ध कराते हैं. इकोनेवी के अलावा पैनासोनिक उत्पादों में क्रांतिकारी इंवर्टर टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी मदद से एयर कंडीशनरों को वांछित तापमान तेजी से मिल पाता है और नॉन इंवर्टर एयर कंडीशनरों के मुक़ाबले ये ज़्यादा प्रभावी तरीक़े से संचालित हो पाते हैं. ये उत्पाद ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करते हुए भारत में ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा में नए कीर्तिमान बना रहे हैं.

टीनएजर्स के लिए सुप्पंडी-48

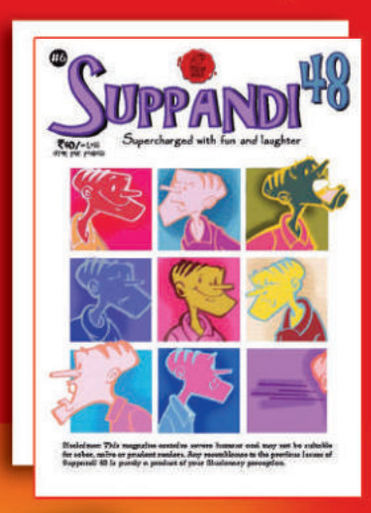

तीन दशक पहले सुप्पंडी का जन्म हुआ था भारतीय बच्चों के चहेते मासिक टिंकल में. सुप्पंडी को मिली लोकप्रियता देखते हुए ए सी के मीडिया ने अक्टूबर 2010 में 48 पृष्ठों का मासिक संस्करण अलग से सुप्पंडी-48 के रूप में उतारा.

युवाओं के लिए बनाया गया है सुप्पंडी-48 का छठा अंक. यह मजेदार कहानियों और मौजमस्ती से भरपूर है. टेढ़ा-मेढ़ा सिर, लंबी नाक और तीन गुच्छों वाले बाल, ऐसा है भारत का दुलारा, नटखट, बावरा सुप्पंडी. टिंकल में पेश हुआ एक सुप्रसिद्ध एवं मजेदार पात्र अब युवाओं के लिए तैयार किए गए सुप्पंडी-48 मासिक के छठे अंक में आया है. तीन दशक पहले सुप्पंडी का जन्म हुआ था भारतीय बच्चों के चहेते मासिक टिंकल में. सुप्पंडी को मिली लोकप्रियता देखते हुए ए सी के मीडिया ने अक्टूबर 2010 में 48 पृष्ठों का मासिक संस्करण अलग से सुप्पंडी-48 के रूप में उतारा. इसका हर एक अंक पठनीय होता है. सुप्पंडी की मजेदार कहानी पढ़ने के लिए लोग बेताब रहते हैं. सुप्पंडी-48 का सुप्पंडी टिंकल में मिलने वाले सुप्पंडी से बिल्कुल अलग है. सुप्पंडी की कथा को कौन सा नया मोड़ मिला है, क्या वह बदल जाएगा, अपने दोस्तों के साथ नए-नए कार्यों में हिस्सा लेगा समेत कई अन्य कथाओं का इसमें समावेश है. युवा अक्सर बच्चों की कहानियों में दिलचस्पी नहीं लेते, इसीलिए सुप्पंडी-48 की टीम ने ख़ास उनके लिए मासिक तैयार करने का निश्चय किया. इसमें सुप्पंडी कैरेक्टर अलग-अलग भूमिकाओं में दिखाई देगा. सुप्पंडी की कथाओं के अलावा इस छठे अंक में अन्य कथाएं भी पढ़ने को मिलेंगी. सुप्पंडी-48 की क़ीमत है सिर्फ़ 40 रुपये.

फोन स्टाइल स्टेटमेंट

मोबाइल फोन ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत हैं. एटीट्यूड, फंक, स्टाइल और फैशन के मद्देनज़र लावा ने मोबाइल फोन की नई रेंज पेश करने के लिए एमटीवी इंडिया के साथ साझेदारी की है. लोगों को संचार शक्ति देने के उद्देश्य से कंपनी ने नया लावा ए-16 एमटीवी फोन लांच किया है, जिसमें करंट स्टाइल और बेहतरीन वैल्यू का मेल है. यह फोन विशेष तौर पर एमटीवी जनरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है. लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक एस एन राय ने कहा कि उपभोक्ता इस बात का ख्याल ज़रूर रखते हैं कि फोन दिखने में सुंदर होना चाहिए. इसीलिए कंपनी ने लावा ए-16 फोन पेश किया है. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुनील रैना के अनुसार, नई पीढ़ी फैशन के प्रति काफी जागरूक है. वह एसेसरीज, शूज से लेकर कपड़ों तक हर चीज फैशन के हिसाब से पसंद करती है. क्लासी लुक के साथ-साथ इस फोन में कई फीचर्स हैं, जैसे विशिष्ट एनिमेटेड थीम, 3.2 मेगा पिक्सल कैमरा और 2.6 इंच की हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन. कंपनी को उम्मीद है कि युवा एग्जीक्यूटिव्स और कॉलेज छात्रों के बीच यह फोन पसंद किया जाएगा. इसका बैक कवर काफी स्टाइलिश है और आसानी से पकड़ने के लिए सॉफ्ट कर्व है. इसमें मल्टीपल वालपेपर एवं थीम के साथ एनिमेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ट्रेंडी एसेसरीज युवाओं को आकर्षित करेंगी. शानदार लम्हों को कैद करने के लिए इसमें लोमो इफेक्ट के साथ 3.2 मेगापिक्सल कैमरा भी है. इसमें 2.6 इंच आईपीएस स्क्रीन है, जो हाई रेजोल्यूशन की वाइड स्क्रीन पिक्चर दिखाती है और उपभोक्ताओं को बेहतरीन मल्टी मीडिया अनुभव देती है. इसके ईयरफोन एसआरएस वॉव एचडी अनुभव देते हैं. लावा ए-16 में सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन फेसबुक है, जो उपभोक्ताओं को हमेशा जोड़े रखता है. यह स्टाइलिश नया फोन लावा की वृहद रेंज का नवीनतम विस्तार है. लावा ए-16 में प्राइवेसी फीचर भी हैं, जो उपभोक्ताओं को अपने फोन पर पूर्ण नियंत्रण देते हैं. इनके ज़रिए एसएमएस और पिक्चर आदि लॉक किए जा सकते हैं. लावा के पहले फोन ए-10, एम-30, एम-70 और स्मार्टफोन एस-12 युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं. ए-16 भारत के सभी रिटेल आउटलेट्स पर 4000 से लेकर 4500 रुपये में उपलब्ध है.

मज़ेदार स्पीकर

भारत की अग्रणी कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने अपना नया 2.1 मल्टी मीडिया स्पीकर सेट जेब-एसडब्ल्यू 3500 आरयूसीएफ डिजिटल डिस्पले के साथ पेश किया है. इस नए मॉडल की ख़ूबियों में शानदार बास रिफ्लेक्स सबवूफर फुल फंक्शनल रिमोट कंट्रोल के साथ शामिल है, जो जेब्रोनिक्स के स्पीकर की विस्तृत रेंज में एक नया आयाम जोड़ रहा है. स्मार्ट स्पीकर सिस्टम में वॉल्यूम कंट्रोल और पावर बटन है, जो नारंगी रंग के एलईडी डिस्प्ले पर प्रदर्शित होता है.

यह आईपॉड और स्टीरियो लाइन केबल और 3.5 एमएम स्टीरियो एडाप्टर वाले पीसी के लिए एकदम मुफीद है. इस्तेमाल में एकदम आसान इंटरफेस वाले जेब-एसडब्ल्यू 3500 आरयूसीएफ में फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल लगा है, ताकि इसका संचालन एकदम सुविधाजनक हो. बास/ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल आवाज की स्पष्टता बढ़ाकर ग़ज़ब का एहसास दिलाता है.

इसकी सबसे आकर्षक ख़ूबी एसडी/यूएसबी इनपुट फैसिलिटी है, जिसकी मदद से मेमोरी कार्ड या डेटा स्टोरेज डिवाइस से सीधे गाने सुने जा सकते हैं. स्पीकर सिस्टम वजन में इतना हल्का है कि यह छुट्टी या यात्रा के दौरान आसानी से कैरी किया जा सकता है, ताकि आप अपना पसंदीदा ऑडियो कहीं भी सुन सकें. जेब-एसडब्ल्यू 3500 आरयूसीएफ एक अनूठे डिज़ाइन वाला पीसी मल्टी मीडिया स्पीकर सिस्टम है, जो कनेक्टर एवं अतिरिक्त इनपुट-आउटपुट पोर्ट्स जैसी सुविधाओं से लैस है. अगर आप ऐसी ख़ूबियों से लैस 2.1 स्पीकर सिस्टम की तलाश में हैं तो आपके लिए इससे बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता. जेब-एसडब्ल्यू 3500 एक साल की वारंटी के साथ 1999 रुपये की किफायती क़ीमत पर उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

केकेआर की नई तलाश

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच पद लगभग हासिल कर चुके डेव वाटमोर ने पिछले दिनों इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच के पद से इस्तीफ़ा दे दिया. आईपीएल के तीसरे सत्र से पहले जॉन बुकानन की जगह लेने वाले वाटमोर ने दो सत्रों में टीम की कोचिंग की. कभी बांग्लादेश के कोच रहे वाटमोर के मार्गदर्शन में केकेआर टीम पहले सत्र में छठे स्थान पर रही, जबकि आईपीएल-चार में गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम नॉकआउट में जगह बनाने में सफल रही और चैंपियंस लीग में भी खेली. वाटमोर ने एक बयान में कहा, टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है. मैं टीम की सफलता जारी रहने की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि टीम 2012 में भी आगे बढ़ेगी. उन लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मुझमें विश्वास जताया. सूत्रों के मुताबिक़ , पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने वाटमोर की नियुक्ति के बारे में चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित किया है. आईपीएल-पांच के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आगामी चार फरवरी को होनी है और वाटमोर के संभावित विकल्प की जल्द घोषणा हो सकती है. अब ऐसे में केकेआर के मालिक शाहरुख को कोई नया कोच जल्द ही तलाशना होगा.

समांथा की ख़्वाहिश

इस वर्ष अमेरिकी ओपन का एकल खिताब जीतने वाली आस्ट्रेलिया की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त महिला टेनिस स्टार समांथा स्टोसुर ने आगामी आस्ट्रेलियन ओपन में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. एक समाचार पत्र के मुताबिक़, स्टोसुर को इस बात का यक़ीन है कि वह घरेलू माहौल का फ़ायदा उठाकर आस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में सफल रहेंगी. वह कहती हैं, मुझे नए वर्ष की शुरुआत आस्ट्रेलिया में खेलते हुए करने की ख़ुशी है. मेरा लक्ष्य अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना है. स्टोसुर ने गत सितंबर में अमेरिकी ओपन के फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को पराजित किया था. इस जीत के बाद स्टोसुर से अपेक्षा काफी बढ़ गई है. आस्ट्रेलियाई दर्शक चाहते हैं कि स्टोसुर 1978 के बाद आस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनें. इससे पहले क्रिस ओनील ने यह खिताब जीता था. देखना दिलचस्प होगा कि समांथा को किस हद तक कामयाबी मिलती है.

मैक्ग्राथ की भविष्यवाणी

ग्लेन मैक्ग्राथ ने हाल में भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम इंडिया का सफाया होना तय है. ग्लेन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज 4-0 से जीतने की भविष्यवाणी की है. भारत के साथ खेली जा रही चार टेस्ट मैचों की इस सीरीज में मेजबान आस्ट्रेलिया पहले ही 1-0 से आगे है. ऐसे में उनकी यह भविष्यवाणी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने जैसी है. उनका कहना है कि अभी तीन टेस्ट मैच खेले जाने हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उनकी टीम 4-0 से सीरीज जीतने में सफल रहेगी. मैक्ग्राथ का कहना है कि इस समय उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खिलाड़ियों ने उन्हें अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है. एक समाचारपत्र के अनुसार, उन्होंने कहा, टीम के खिलाड़ी इस समय जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे मैं प्रभावित हूं. मुझे लगता है कि एक टीम को अच्छा बनाने के लिए उसकी गेंदबाज़ी अहम भूमिका निभाती है. आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार का गेंदबाज़ी आक्रमण है, उससे अन्य खिलाड़ियों में भी आत्मविश्वास लौट आया है. मैक्ग्राथ के इस बयान से टीम इंडिया को सबक लेने की ज़रूरत है और होना तो यह चाहिए कि वह अपने प्रदर्शन के ज़रिए जल्द से जल्द इसका जवाब दे.

ओलंपिक की तैयारी

लंदन ओलंपिक खेल शुरू होने में अभी क़रीब सात महीने का समय है, लेकिन भारत का कोई भी पहलवान अभी तक ओलंपिक का टिकट नहीं पा सका है. बावजूद इसके ओलंपियन सुशील कुमार के गुरु एवं द्रोणाचार्य अवॉर्डी महाबली सतपाल का मानना है कि भारतीय पहलवान आने वाले साल में न सिर्फ़ टिकट हासिल करेंगे, बल्कि लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीतेंगे. ओलंपिक खेल इस साल 27 जुलाई से लंदन में होने हैं और भारतीय पहलवान क्वॉलिफाइंग प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं. पिछले साल सितंबर में इस्तांबुल में हुई क्वॉलिफाइंग प्रतियोगिता में भारत की ओर से 19 पहलवान गए, जिनमें पेइचिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार भी शामिल थे, लेकिन कोई भी पहलवान ओलंपिक का टिकट नहीं पा सका था. इन दिनों नेशनल स्कूल गेम्स के आयोजन में जुटे सतपाल कहते हैं कि सुशील के ओलंपिक कांस्य पदक जीतने के बाद देश की कुश्ती का स्तर बढ़ा है. यह ज़रूर है कि अभी हमारा कोई भी पहलवान ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई नहीं कर सका है, लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत है. आने वाले महीनों में हमारे पहलवानों के पास क्वॉलिफाइंग के मौक़े आएंगे, जिनमें कई पहलवान टिकट पाने में सफल रहेंगे. कजाकिस्तान में आगामी 28 मार्च से ओलंपिक क्वॉलिफाइंग प्रतियोगिता होगी, जो भारतीय पहलवानों को ओलंपिक का टिकट ज़रूर दिलाएगी. इस प्रतियोगिता में सिर्फ़ एशिया के पहलवान भाग लेते हैं. इसके बाद अप्रैल में चीन और मई में हेल्सिंकी में ओलंपिक क्वॉलिफाइंग प्रतियोगिताएं होंगी. ग़ौरतलब है कि पेइचिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए सुशील कुमार ने 56 सालों बाद पदक जीता था. सतपाल ने कहा कि सुशील पूरी मेहनत कर रहा है. मुझे उससे काफी उम्मीदें हैं. वह अपनी तैयारी में जुटा हुआ है. यदि क़िस्मत ने साथ दिया तो वह लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा.

प्रेशर बहुत टाइट है

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर लगता है कि महाशतक का प्रभाव इस कदर हावी हो गया है कि पिछले पांच साल में पहली बार वह साल का आगाज सैकड़े से करने में नाकाम रहे. तेंदुलकर आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में मंगलवार को 41 रन बनाकर आउट हो गए. यह 2008 केबाद पहल अवसर है जबकि यह स्टार बल्लेबाज नए साल की अपनी शुरुआती पारी में शतक नहीं लगा पाया. तेंदुलकर अगर सैकड़ा जड़ने में सफल रहते तो यह उनका 100वां अंतरराष्ट्रीय और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चौथा शतक होता. तेंदुलकर ने 2008 में आस्ट्रेलिया केखिलाफ सिडनी में दो जनवरी से खेले गए मैच की पहली पारी में नाबाद 154 रन बनाए थे. इसके एक साल बाद 2009 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में खेला था और उसमें पहली पारी में ही 160 रन बनाए थे. इस चैंपियन बल्लेबाज ने वर्ष 2010 का शुरुआती टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ 17 जनवरी से चटगांव में खेला था और उसमें उन्होंने नाबाद 105 रन बनाए थे. उन्होंने 2011 में दक्षिण अफ्रीका केखिलाफ केपटाउन में दो जनवरी से शुरू हुए सीरीज केतीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में 146 रन की पारी खेलकर साल का शानदार आगाज किया था. तेंदुलकर पिछली 20 अंतरराष्ट्रीय पारियों से शतक नहीं लगा पाए हैं, जिससे उनकेशतकों केशतक का इंतजार भी बढ़ गया है. कुल मिलाकर आजकल तेंदुलकर बहुत प्रेशर में हैं.

मैराडोना की नई उम्मीदवारी

अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं. स्लोवेनिया के कोच सेर्को काटानेक को बर्ख़ास्त किए जाने के बाद से मैराडोना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताए जा रहे हैं. ग़ौरतलब है कि काटानेक को गत सितंबर में लेबनान के साथ हुए दोस्ताना मुक़ाबले में मिली 1-3 की हार के बाद बर्ख़ास्त कर दिया गया था. ख़बरों के मुताबिक़, इसके बाद से अंतरिम कोच की देखरेख में यूएई को लगातार तीन मैचों में हार मिली है. मैराडोना ने यह नहीं कहा है कि राष्ट्रीय फुटबॉल संघ ने इस काम के लिए उनसे संपर्क किया है, लेकिन वह इस पद पर ख़ुशी-ख़ुशी आसीन होने को तैयार हैं. मैराडोना इस वर्ष मई से यूएई के पेशेवर फुटबॉल क्लब अलवासी को प्रशिक्षित करेंगे. उन्होंने कहा कि वह एक साथ पेशेवर और राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित कर सकते हैं.

गवली का संन्यास

भारतीय टीम के डिफेंडर महेश गवली ने हाल में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी. 82 इंटरनेशनल मैच खेल चुके 31 वर्षीय गवली पिछले लंबे समय से टीम की डिफेंस की अहम कड़ी थे. अपने इस फ़ैसले के बारे में उन्होंने कहा कि फुटबॉल काफी डिमांडिंग गेम है. इसलिए उन्होंने अपने परिवार से सलाह की और पाया कि इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कहने का समय आ गया है. हालांकि वह कुछ वर्षों तक क्लब फुटबॉल खेलते रहेंगे. उन्होंने सहयोग देने के लिए अपने कोचों, साथियों, क्लबों और अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया. गवली ने कहा कि प्रयाग यूनाइटेड के अर्णब मंडल में वह अच्छा डिफेंडर देखते हैं. इसके अलावा राजू गायकवाड़, क्रिसेंटर अंटोओ और गुरमांगी सिंह भी काफी मज़बूत डिफेंडर हैं. उन्होंने कहा कि 15 सालों के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान देश के लिए हर मैच खेलना उनके जीवन का सबसे अनमोल क्षण रहा है. यह कुछ ऐसा है, जो उनके जेहन से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हर किसी को देश की ओर से खेलने का मौक़ा नहीं मिलता. वह कई टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के सदस्य रहे, लेकिन एएफसी चैलेंज कप की खिताबी जीत उनके लिए बहुत अहम है. इसके अलावा एशियन कप में हिस्सेदारी को भी वह एक उपलब्धि मानते हैं. आई लीग में डैंपो स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलने वाले गवली ने कहा कि अब उन्हें अपना पूरा फोकस क्लब फुटबॉल पर लगाना होगा. वह पांच-छह सालों तक यह प्रतिस्पर्धी फुटबॉल खेलना चाहेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 16 जनवरी–22 जनवरी 2012

हॉलीवुड सुंदरी रीस विदरस्पून कहीं भी जाएं, उनके साथ उनका पूरा मेकअप किट चलता है. रीस को अगर कोई बिना मेकअप में देख ले तो उन्हें बहुत अजीब लगता है.

जेनिफर की नई पारी

मशहूर डेली सोप एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट बहुत जल्द फिल्मों में नज़र आने वाली हैं. गौरतलब है कि जेनिफर ने कई टीवी धारावाहिकों में काम किया है और कई टीवी शोज में एंकरिंग भी की है. अब वह श्रीराम इंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्देशक राहत काजमी की आने वाली फिल्म लव किया और लग गई में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में नज़र आएंगी. अभी हाल में इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में संपन्न हुई. जेनिफर के अलावा इसमें मशहूर अभिनेता पवन मल्होत्रा, सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी और सारेगामापा-2009 के टॉप 5 प्रतियोगी रहे गायक राजा हसन भी नज़र आएंगे. राहत काजमी के अनुसार, यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें जेनिफर लोगों हंसाते हुए नज़र आएंगी. चूंकि आजकल कॉमेडी फिल्मों का जमाना है, इसलिए उन्हें अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर होने के नाते इस फिल्म को बनाने में उन्होंने पूरी मेहनत की है. उन्हें उम्मीद है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी. फिल्म लव किया और लग गई के गाने मशहूर पार्श्व गायक कैलाश खेर एवं दलेर मेंहदी ने गाए हैं.

जेनिफर के अलावा इसमें मशहूर अभिनेता पवन मल्होत्रा, सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी और सारेगामापा-2009 के टॉप 5 प्रतियोगी रहे गायक राजा हसन भी नज़र आएंगे. राहत काजमी के अनुसार, यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें जेनिफर लोगों हंसाते हुए नज़र आएंगी.

हॉलीवुड रीस विदरस्पून का जीवन मंत्र

अदाकारा रीस विदरस्पून निर्माणाधीन कॉमेडी फिल्म सेक्स टेप में नज़र आएंगी और इसमें उनके साथ अमेरिकी अभिनेता जैक्सन सीगल भी होंगे. सेक्स टेप एक ऐसे विवाहित जोड़े की कहानी है, जो शादी के बाद अपने बच्चों से दूर रहकर अपनी एक रात रोमांचक बनाना चाहते हैं और एक वीडियो बनाते हैं, पर अगली सुबह जब उठते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह वीडियो वहां से ग़ायब हो जाता है और वे उसे ढूंढने लगते हैं. दर्शकों को तो इंतज़ार रहेगा इस फिल्म का, लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं कि उनके रीयल लाइफ पति को उनके रील लाइफ पति से कोई प्रॉब्लम न हो. कुछ ही वक़्त पहले ही विदरस्पून ने अपने एजेंट जिम टोथ के साथ एक परंपरागत समारोह में शादी की है. अतिथियों में सलमा हायेक और रेनी जेलवेगेर भी मौजूद थे. ऑस्कर पुरस्कार विजेता रीस विदरस्पून ने कैलिफोर्निया केओजाई स्थित अपने सत्तर लाख डॉलर के शानदार घर में टोथ के साथ संकल्प लिया था. विदरस्पून ने मोनिक लहुइलिअर द्वारा डिज़ाइन किए गए गाउन को पहना था. इससे पहले टोथ अपने बच्चों के साथ शादी के लिए पहुंचे. हॉलीवुड सुंदरी रीस विदरस्पून कहीं भी जाएं, उनके साथ उनका पूरा मेकअप किट चलता है. रीस को अगर कोई बिना मेकअप में देख ले तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और इसलिए वह अपनी कार, घर और सेट पर पूरा मेकअप किट रखती हैं. रीस ने स्वीकार किया कि उनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, जिन्हें वह हमेशा दूर करने का प्रयास करती हैं. कभी-कभी यह लाभदायक भी होता है. रीस विदरस्पून का कहना है कि जीवन में वह ऐसे मंत्र को अपनाती हैं, जिससे उनकी सभी समस्याएं दूर हो सकें. वेबसाइट कांटेक्ट म्यूजिक डॉट काम के मुताबिक़ , विदरस्पून ने कहा, कष्टदायक चीजों को मैं अपने जेहन में नहीं रखती. ऐसी चंद यादें ही मेरे जेहन में मौजूद हैं.

अक्षय का डर

अक्षय कुमार ने करियर की शुरुआत में कई एक्शन फिल्में कीं. बाद में वह दर्शकों को हंसाने में जुट गए. अब दर्शक उनकी हास्य फिल्मों से ऊब गए हैं तो एक बार फिर उन्होंने एक्शन का साथ पकड़ा है. उनकी खिलाड़ी सीरीज की कई फिल्में हिट हुई थीं, इसीलिए वर्षों बाद वह रॉडी राठौर नामक एक्शन फिल्म कर रहे हैं. पचास साल के होने के पहले वह कुछ एक्शन फिल्में करना चाहते हैं. साथ ही वह सोनी चैनल के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं, क्योंकि उन्हें यह विचार अच्छा लगा कि यह चैनल यंग एडल्ट्स के लिए कार्यक्रम दिखाएगा. वह चाहते हैं कि उनका बेटा भी यह चैनल देखे, क्योंकि इसके कार्यक्रम एक्शन और एडवेंचर आधारित होंगे. एडवेंचर और स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले अक्षय युवाओं से अपील करते हैं कि वे प्रतिदिन कुछ घंटे मैदान में बिताया करें. वह हर वर्ष अक्टूबर में मार्शल आर्ट का तीन दिवसीय टूर्नामेंट कराते हैं, जिसमें देश भर के खिलाड़ी आते हैं, जिनके ठहरने-खाने का जिम्मा वह ख़ुद उठाते हैं. जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें वह विशेष प्रशिक्षण के लिए जापान भेजते हैं. हाल में उन्होंने स्पीडी सिंह नामक फिल्म बनाई, जो आइस हॉकी पर आधारित थी. भारत में इस खेल के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए वह फिल्म यहां कम चली, लेकिन उत्तरी अमेरिका में उसने ज़बरदस्त व्यवसाय किया. उन्होंने अपनी फिल्मों के सारे स्टंट ख़ुद किए और कभी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया. हवाई जहाज के ऊपर खड़े होकर भी उन्होंने स्टंट किए, जो उनकी फिटनेस के कारण ही संभव हो सका. उनके घर पर ही जिम है, जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है. ऊपर जाना हो तो रस्सियों का इस्तेमाल करना पड़ता है. उनके जिम को श्रेष्ठ जिम का अवॉर्ड मिल चुका है. एक्शन फिल्में पसंद करने वाले अक्षय ख़ुद एक्शन फिल्म का निर्देशन करने में दिलचस्पी नहीं रखते. ख़तरों से खेलना उन्हें पसंद है, वह डरते हैं तो केवल अपनी बीवी से.

किम शर्मा : काम कम, चर्चा ज़्यादा

अहमदनगर (गुजरात) में 21 जनवरी को जन्मी किम शर्मा उर्फ मोहब्बतें की संजना को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन फिर भी वह बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी रहीं. प्रतिष्ठित यशराज बैनर के साथ अपनी पहली फिल्म करने वाली किम शर्मा का फिल्मी करियर कभी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया, जो उन्होंने सोची थीं. मोहब्बतें जैसी बड़ी फिल्म से अभिनय की शुरुआत करने वाली किम अपने फिल्मी करियर को कभी सही दिशा नहीं दे पाईं. वह बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और बादशाह शाहरुख़ खान के साथ फिल्म मोहब्बतें में काम कर चुकी हैं. पिछले सात वर्षों का उनका फिल्मी सफर पूरी तरह निराशाजनक रहा. कभी वह बड़े कलाकारों वाली फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाती नज़र आईं तो कभी दूसरे दर्जे की फिल्मों में बतौर अभिनेत्री दिखीं. किम फिल्मों से ज़्यादा एक क्रिकेटर के साथ अपने रिश्ते के कारण चर्चा का विषय बनीं. अब वह एक फिर चर्चा में है. दरअसल वह अभिनेत्री भूमिका चावला के पति एवं योग गुरु भरत ठाकुर की तेलुगु फिल्म यगम में हॉट बिकनी में सेक्सी और एक अलग अंदाज़ में नज़र आने वाली हैं. योग गुरु भरत ठाकुर की फिल्म हो और उसमें उनकी पत्नी भूमिका चावला न हों, यह कैसे हो सकता है. फिल्म तेरे नाम में नज़र आने वाली भूमिका चावला फिल्म यगम में एक एयर होस्टेज का किरदार निभा रही हैं. हालांकि फिल्म में किम का किरदार छोटा है, मगर प्रभावपूर्ण है. इसमें किम एक हॉट बार गर्ल के किरदार में नज़र आने वाली हैं, परंतु वह बार में नृत्य करते हुए नहीं, बल्कि खाने का ऑर्डर लेती हुई दिखेंगी. फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में की गई है. फिल्म के अभिनेता नवदीप हैं. आकर्षक व्यक्तित्व के बावजूद किम शर्मा को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाने का जोखिम निर्माता-निर्देशक नहीं उठाना चाहते हैं. किम स्वयं को कभी हिंदी फिल्मों की सफल अभिनेत्रियों में शामिल नहीं कर पाईं, पर सुर्खियों में हमेशा बनी रहीं. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान युवराज सिंह के साथ चले प्रेम प्रसंग के चलते वह खासी चर्चित रहीं. उन्होंने केन्या के बिजनेसमैन अली पंजानी से शादी करके बॉलीवुड से विदा ले ली. उनके करियर की मुख्य फिल्में हैं, मोहब्बतें, तुमसे अच्छा कौन है, कहता है दिल बार-बार, फिदा, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, यकीन, ताजमहल, टॉम डिक एंड हैरी, कुड़ियों का है जमाना, लेडीज टेलर, जिंदगी रॉक्स, छोड़ो ना यार, देशद्रोही और मूनलाइट.

विद्या शो पीस नहीं

फिल्म द डर्टी पिक्चर्स की सफलता के बाद विद्या बालन का दिमाग़ सातवें आसमान पर पहुंच गया है. वह अब कोई भी ऐसी फिल्म नहीं करना चाहतीं, जिसमें अभिनेत्री को ग्लैमर बढ़ाने के लिए साइन किया जाता हो. उन्होंने फिल्म शूटआउट एट वडाला में काम करने से इंकार कर दिया है. इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि विद्या अब किसी पुरुष प्रधान फिल्म में काम नहीं करना चाहती हैं. उनका मानना है कि ऐसी फिल्मों में एक्ट्रेस को महज़ शो पीस की तरह पेश किया जाता है. खास बात यह है कि द डर्टी पिक्चर की निर्माता एकता कपूर ही शूटआउट एट वडाला का भी निर्माण कर रही हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं विद्या और एकता के बीच कोई मनमुटाव तो नहीं हो गया, लेकिन हम बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं है. अब विद्या सिर्फ़ वही फिल्म करना चाहती हैं, जिसमें उनका रोल दमदार हो. उनका मानना है कि मल्टी स्टारर फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का बेहतर प्रदर्शन संभव नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मां के प्रशंसक नील

फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के बाद से नील नितिन मुकेश को एक अदद हिट का इंतज़ार है. उनकी यह चाहत 2012 में पूरी हो सकती है. ख़बर है कि निर्माता अब्बास मस्तान ने नील के साथ तीन फिल्मों की डील की है. इनमें एक फिल्म शाहरुख खान की बाज़ीगर की रीमेक है. प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश और निशी मुकेश के घर 15 जनवरी, 1982 को जन्मे नील का नामकरण लता मंगेशकर ने किया था. लता जी ने उनका नाम नील नितिन मुकेश रखा, क्योंकि नील के पिता नितिन अंतरिक्ष यात्री नील ऑर्मस्ट्रांग के फैन थे, लेकिन नील फैन थे हिंदी फिल्मों के. उन्होंने मुंबई के ग्रीन लॉन हाईस्कूल से शुरुआती पढ़ाई की, जबकि एच आर कॉलेज से कम्युनिकेशन की बैचलर डिग्री ली. ट्रेनिंग के लिए वह किशोर नमित कपूर और अनुपम खेर के संस्थानों में भी गए. बचपन से ही उनका सपना था कि वह अभिनेता बनें. नील अपनी मां के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और वह हर बार नितिन एवं निशी के बेटे के रूप में जन्म लेना चाहते हैं. उन्होंने कहा, वे सबसे अच्छे अभिभावक हैं. वे बहुत भावुक, प्यार एवं देखभाल करने वाले हैं. मुझे उनका बेटा होने पर गर्व है. उन्होंने मुझे महान मूल्य सिखाए हैं, सम्मान और सच्चा प्यार करना सिखाया है. नील ने 2007 में जॉनी गद्दार में अभिनय से बॉलीवुड में शुरुआत की थी. नील नितिन मुकेश को नील मुकेश के नाम से भी जाना जाता है. कॉलेज के दौरान ही उन्होंने आदित्य चोपड़ा की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी में उनके सहयोगी के तौर पर काम किया था. अब तक वह जॉनी गद्दार, न्यूयॉर्क, जेल, लफंगे परिंदे, तेरा क्या होगा जॉनी और सात ख़ून माफ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. बतौर बाल कलाकार उन्होंने 1988 में फिल्म विजय और 1989 में फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी में काम किया.

चौथी दुनिया

दिल्ली, 16 जनवरी–22 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

नई वस्त्रोद्योग नीति

विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के साथ धोखा है

प्रवीण महाजन

विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के पिछड़ेपन को दूर करने की चाहत राज्य सरकार में कितनी है, यह हाल ही में घोषित की गई नई वस्त्रोद्योग नीति से ज़ाहिर हो गया है. राज्य सरकार ने पहले तो विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश को ध्यान में रखकर वस्त्रोद्योग नीति की घोषणा की और वाहवाही लूटी, लेकिन बाद में उसे मंजूरी देने के लिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तुरंत बदल भी दिया गया. इस बैठक में कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के पिछड़े ज़िलों को भी शामिल किया गया है. विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इससे राज्य सरकार ने एक बार फिर कपास उत्पादक किसानों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है. ग़ौरतलब है कि 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राज्य सरकार ने नई वस्त्रोद्योग नीति लाई है, जिसमें दावा किया गया है कि आगामी पांच वर्षों में 40 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 11 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा. इसका सबसे अधिक फ़ायदा विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के किसानों को मिलने की घोषणा की गई है, लेकिन यदि विपक्ष की मानें तो यह नीति नई बोतल में पुरानी शराब जैसी है. वर्ष 2003 से वस्त्रोद्योग से संबंधित नागपुर के 4 बड़े प्रोजेक्ट अधूरे हैं. उनके बारे में नीति में कुछ नहीं कहा गया है. अप्रैल 2009 से दिसंबर 2011 के बीच शुरू हुई नई वस्त्रोद्योग इकाइयों के लिए योजना में कुछ नहीं है. हालांकि इसमें कपास बेल्ट को ध्यान में रखा गया है, लेकिन फिर भी अनिश्चितता का माहौल बना है.

राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री आरिफ़ नसीम ख़ान ने जीनिंग, प्रोसेसिंग, विविंग, निटिंग, डाइंग आदि सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए 40 हज़ार करोड़ रुपये निवेश करने की संभावना नई वस्त्रोद्योग नीति में ज़ाहिर की है. इससे 11 लाख नए रोज़गार के अवसर पैदा होने का दावा किया गया है, लेकिन यदि महाराष्ट्र राज्य हथकरघा धारक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं इंडियन पावरलूम फेडरेशन के सचिव प्रताप होगाड़े की मानें तो महज़ 4 हज़ार करोड़ का ही निवेश होने की संभावना है, जिससे 1 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जा सकेगा. उन्होंने इसमें कई ख़ामियां भी गिनाई. होगाड़े ने कहा कि पावरलूम उद्योग के लिए सबसे बड़ा संकट बैंक से कर्ज़ नहीं मिल पाना है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ब्याज़ पर अनुदान के बदले 20 फ़ीसदी पूंजी निवेश अनुदान वाली वैकल्पिक योजना अमल में लाई थी, जिसे काफी सफलता मिली. इसी के आधार पर राज्य सरकार ने 100 से 120 प्रतिशत तक पूंजी निवेश अनुदान पांच वर्ष में देने का वादा किया था, लेकिन नई वस्त्रोद्योग नीति में सरकार ने केवल 10 फ़ीसदी पूंजी निवेश अनुदान का प्रावधान किया है. इसे उन्होंने जनता के साथ धोखा क़रार दिया. ग़ौरतलब है कि जहां कपास अधिक होता है, वहां कम और जहां कपास नाममात्र होता है वहां अधिक सहकारी और निजी सूत मिलें हैं. वर्तमान में राज्य में 59 सहकारी और 111 निजी सूत मिलें हैं. इनमें से विदर्भ में 14 सहकारी और 50 निजी मिलें हैं. मराठवाड़ा में 8 सहकारी और 10 निजी मिलें हैं, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे अधिक 31 सहकारी और 51 निजी मिलें हैं.

फिर हावी हुआ पश्चिम महाराष्ट्र

पिछले 11 वर्षों से लंबित वस्त्रोद्योग नीति को लाने के पीछे सरकार की यह मंशा बताई जा रही है कि वह कपास उत्पादक क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन उसका यह दावा नीति घोषित करने के कुछ दिनों बाद ही झूठा साबित हो गया. मंत्रिमंडल की बैठक में जब इसे मंजूरी देने की बात आई तो उद्योग मंत्री नारायण राणे ने नीति का ज़ोरदार विरोध किया. उन्होंने मांग की कि इसमें कोंकण के पिछड़े ज़िलों को भी शामिल किया जाए. उनकी देखा-देखी पश्चिम महाराष्ट्र के मंत्रियों ने भी उनके इलाकों को शामिल करने की मांग करनी शुरू कर दी. कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के मंत्रियों की मांग का कड़ा विरोध विदर्भ के मंत्रियों ने किया. रोज़गार गारंटी योजना मंत्री डॉ. नितिन राऊत ने कहा कि वस्त्रोद्योग नीति कपास उत्पादक क्षेत्रों के लिए हैं. यदि इसमें ग़ैर कपास उत्पादक क्षेत्रों को शामिल किया गया तो इसका लाभ विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश को नहीं मिलेगा. डॉ. राऊत ने सुझाव दिया कि कोंकण में गारमेंट उद्योग के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए न की वस्त्रोद्योग के लिए. सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने भी इस मुद्दे पर सहमति जताई, लेकिन विदर्भ के मंत्रियों के विरोध को दरकिनार कर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के पिछड़े ज़िलों को नीति में शामिल करने की घोषणा कर दी. इससे साफ हो गया है कि विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के नाम पर एक बार फिर कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है. विदर्भ के कई उद्योग पश्चिम महाराष्ट्र में ले जाए गए हैं. अब वस्त्रोद्योग नीति में भी वहां के ज़िलों को शामिल कर विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के किसानों और जनता को भूखा-नंगा रखने की साजिश रची जा रही है. जानकारों का कहना है कि अब यह तय है कि पिछड़े क्षेत्रों की बजाय कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में ही अधिक प्रोसेसिंग और

मिलता है 3500 करोड़ रुपये का राजस्व

सूत व उससे बने कपड़े पर वैट, चुंगी व व्यवसाय कर आदि के माध्यम से राज्य सरकार की तिजोरी में हर वर्ष 3500 करोड़ रुपये का राजस्व जमा होता है, लेकिन नई वस्त्रोद्योग नीति के तहत पांच वर्ष में केवल 2011 करोड़ रुपये मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है. देश के कुल 22.50 लाख पावरलूमों में से 11.25 लाख पावरलूम महाराष्ट्र में है. इसमें 28 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है. होगाड़े ने कहा कि उम्मीद थी कि नई नीति में इनके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है.

क्या कहती है सरकारी नीति

- विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश (उत्तर महाराष्ट्र) में उद्योग लगाने के लिए साढ़े 12 प्रतिशत ब्याज़ दर से सुविधाएं दी जाएंगी. 10 फ़ीसदी पूंजी अनुदान में दी जाएगी.
- शेष महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए साढ़े 10 फ़ीसदी ब्याज़ दर से सहूलियतें दी जाएंगी. सभी सहूलियतें सहकार और निजी क्षेत्र के उद्योगों को मिलेंगी.
- श्रमिकों को बीमा योजना, आवास योजना और स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा.
- विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र की सहकारी सूत मिलों को मौजूदा ढांचे के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए 5-45-50 योजना चालू रहेगी.
- जिस तहसील में पहले से ही इसी पद्धति से अंश पूंजी दी गई है, वहां पुनः मिल शुरू करने के लिए मदद नहीं दी जाएगी. इससे एक तहसील में एक ही सहकारी मिल रहेगी.
- वर्तमान में ठाणे ज़िले के भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापुर, मालेगांव, नागपुर क्षेत्र में कुल 11.25 लाख पावरलूम हैं. उनका भी समावेश इस नीति में किया गया हैं. उन्हें भी उद्योगों का नवीनीकरण करने के लिए साढ़े 10 फ़ीसदी ब्याज़ दर से सुविधा दी जाएगी.
- पुराने उद्योगों के नवीनीकरण और उनका स्तर सुधारने के लिए नियुक्त किए जाने वाले सलाहकारों की फीस शासन की ओर से दी जाएगी.
- वर्तमान में 59 सहकारी और 111 निजी सूत मिलें हैं. इनमें से विदर्भ में 14 सहकारी और 50 निजी मिलें हैं. मराठवाड़ा में 8 सहकारी और 10 निजी मिलें हैं, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे अधिक 31 सहकारी और 51 निजी मिलें हैं.

अन्य इकाइयों की स्थापना होगी, जिससे वहां रोज़गार बढ़ेगा और विदर्भ क्षेत्र पिछड़ा ही रहेगा.

नागपुर में अटके चार बड़े प्रोजेक्ट

वस्त्रोद्योग के संबंध में सरकार की गंभीरता का जीता जागता उदाहरण नागपुर में है. कपास बेल्ट में होने से यहां एक नहीं, बल्कि चार बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई. उम्मीद थी कि इससे बड़े पैमाने में रोज़गार का सृजन होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया है. राज्य सरकार ने 2003 में उमरेड रोड पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की थी. इसमें बुनकरों के लिए पोस्ट विविंग और प्री विविंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट राजनीति का शिकार हो गया. वर्ष 2005 वांजरा रोड कामठी में पावरलूम पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने की. इसकी कुल लागत 18 करोड़ रुपये थी. इसके पूर्ण होने पर नागपुर और कामठी के बुनकरों को उनके निवास स्थानों के क़रीब वांजरा में विविंग के लिए ढांचागत सुविधाएं मिलतीं, लेकिन सरकारी ज़मीन खाली होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन नहीं मिली. वर्ष 2006 में एम्प्रेस मिल की जगह पर गारमेंट पार्क बनाया जाना था, लेकिन दो बार घोषणा होने के बाद भी यह नदारद है. इसमें स्टीचिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया कराने वाली थी. केंद्र सरकार की टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में 16 करोड़ की लागत से हिंगना एमआईडीसी में टेक्सटाइल जोन बनाने की घोषणा की पर यह भी आज तक हवा में ही है. नागपुर ज़िले से भाजपा विधायक विकास कुंभारे ने भी वस्त्रोद्योग नीति को पूरी तरह खोखला बताया है. होगाड़े के अनुसार मार्च 2009 के आख़िर तक 35 फ़ीसदी या अधिकतम 25 लाख रुपये पूंजी निवेश अनुदान दिया जाता था. नई नीति में इसे पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है.

करोड़ों मिले, लेकिन नतीज़ा सिफ़र

अब इसे किसानों का भाग्य कहा जाए या नेताओं की बेईमानी, लेकिन विदर्भ के हिस्से में जो भी आता है उसका परिणाम दिखाई नहीं देता है. सरकार ने राज्य की सूत मिलों को उबारने के लिए 106 करोड़ 30 लाख रुपये बिना ब्याज़ कर्ज़ देने की घोषणा की. इसमें विदर्भ की 14 सहकारी मिलों का भी समावेश है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह की मदद दी जा चुकी है, पर इन मिलों में मशीनों की कम और पक्षियों की आवाज़ें अधिक सुनाई देती हैं. इन मिलों में अब तक करोड़ों रुपये का निवेश किया जा चुका है, लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा में काफी कम है. विदर्भ की बाबासाहब केदार, हिंगणा, नागपुर की सूत मिल को 2 करोड़ 27 लाख 94 हजार रुपये, शेषराव वानखेड़े हिंगणा, नागपुर 3 करोड़ 47 लाख 54 हजार रुपये, नागपुर ज़िला गिरणी पाटणसावंगी, नागपुर 1 करोड़ 48 लाख 58 हज़ार रुपये, बाबासाहब नाईक, पुसद 1 करोड़ 43 लाख 22 हज़ार रुपये, इंदिरा सहकारी गिरणी, वर्धा 1 करोड़ 96 लाख 69 हज़ार रुपये, कापूस पणन कर्मचारी गिरणी, अकोला 38 लाख 18 हज़ार रुपये, मुंगसाजी महाराज, चिखली 1 करोड़ 28 लाख 8 हज़ार रुपये, वीर जगदेवराव, बुलढाना 22 लाख 24 हज़ार रुपये, स्व. बापूजीराव देशमुख, वर्धा, 1 करोड़ 91 लाख 70 हज़ार रुपये, प्रियदर्शनी, यवतमाल 2 करोड़ 60 लाख 90 हज़ार रुपये, गजानन सहकारी धामणगांव, अमरावती 87 लाख 16 हज़ार रुपये, संत गाड़गे महाराज, अकोला 20 लाख 20 हज़ार रुपये का कर्ज़ मंजूर किया गया है. विशेष बात यह है कि हर बार इन सूतगिरणियों को घाटे पर बता कर सरकार द्वारा की गई मदद संचालकों द्वारा हजम कर ली जाती है. इसके बाद भी राजनीतिक कारणों से इन सूतगिरणियों की मदद सरकार खुले दिल से करती है.

feedback@chauthiduniya.com

नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी कृति समिति योजना बनाई थी. इस योजना के तहत हर राज्य को अपने क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र ने करोड़ों की निधि उपलब्ध कराई थी.

विरोधी पार्टियों के विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार के सामने ऐसी कौन-सी मजबूरी आ गई थी कि केवल दो वर्षों में बिजली की दरों में 9 बार बढ़ोत्तरी करनी पड़ी.

महाराष्ट्र हलचल

केंद्र सरकार द्वारा इंदू मिल की पूरी 12.5 एकड़ जगह चैत्यभूमि में बनने वाले डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के अंतरराष्ट्रीय स्मारक के लिए देने का निर्णय लेने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, मंत्री नसीम खान आदि ने दादर चैत्यभूमि में स्थित डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवादल की राजीव गांधी भवन में बैठक आयोजित की गई. मुंबई सेवादल के चेयरमैन गोविंद सिंह, जे.पी. तिवारी ने बैठक को संबोधित किया. दायीं ओर बैठक में उपस्थित सेवादल के पदाधिकारी.

पुणे महानगरपालिका वार्ड क्र. 1 धानोरी में स्व. बाबूराव शिंदे मनपा स्कूल क्र. 164 बी और धानोरी गांवठान में व्यायाम शाला की नई इमारत का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया. इस अवसर महापौर मोहनसिंह राजपाल आदि उपस्थित थे.

लोकपाल विधेयक को संसद में मंज़ूर करने को लेकर वरिष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे ने मुंबई स्थित बांद्रा के एमएमआरडीए मैदान में अनशन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए अण्णा हजारे.

कोकण विभागीय राजस्व क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक स्पर्धा 2011-12 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया. समारोह में रत्नागिरि ज़िले के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देते राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात. उनके साथ हैं आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, ठाणे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुमार कुरुंकर, सिंधुदुर्ग के ज़िलाधिकारी वीरेंद्र सिंह, रायगढ़ के ज़िलाधिकारी एच.के. जावले, रत्नागिरि के ज़िलाधिकारी मधुकर गायकवाड़ और मुंबई के ज़िलाधिकारी चंद्रशेखर ओक.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभागीय महिला सम्मेलन मलाड स्थित शंकरबुवा सावली मैदान में आयोजित किया गया. सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार. मंच पर प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़, महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष निवेदिता माने, पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटील, प्रदेश महिला अध्यक्ष विद्या चव्हाण, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, मंत्री लक्ष्मणराव ढोबले, विधायक उषा दराडे आदि.

महाराष्ट्र सरकार के सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2012 का शुभारंभ मुंबई मंत्रालय के परिषद सभागृह में किया गया. इस अवसर पर बोधचिन्ह का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम ख़ान, राज्यमंत्री प्रकाश सोलंकी आदि.

नदियों में बह गए 200 करोड़ रुपये

आलोक मिश्रा

राज्य में जिस तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, उसी गति से पर्यावरण को भी ख़तरा बढ़ता जा रहा है. इसी के साथ जिन शहरों के पास से जो नदियां गुजरती हैं, उनमें भी प्रदूषण की मात्रा तेज़ी से बढ़ती जा रही है. इसके चलते नदियों का जल भी प्रदूषित हो रहा है. लिहाज़ा इन नदियों के अस्तित्व को ही ख़तरा पैदा हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार राज्य की नदियों में बढ़ते प्रदूषण के प्रति ज़रा भी गंभीर दिखाई नहीं देती है. यही कारण है कि राज्य की तीन बड़ी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई करोड़ों की राशि ख़र्च करने के बाद भी नदी में बढ़ रहे प्रदूषण पर कोई कमी नहीं आई. इसका मतलब तो यही हुआ कि उस पर जो राशि ख़र्च की गई वह पानी में बह गई या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई.

दरअसल शहरीकरण के तीव्रगति से हो रहे विस्तार से देश की 14 नदियों के अस्तित्व को ख़तरा पैदा हो गया है. इन 14 नदियों में राज्य की गोदावरी, कृष्णा और तापी नदी भी शामिल हैं. इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी कृति समिति योजना बनाई थी. इस योजना के तहत हर राज्य को अपने क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र ने करोड़ों की निधि उपलब्ध कराई थी. महाराष्ट्र को भी गोदावरी, कृष्णा और तापी नदी की सफ़ाई के लिए केंद्र ने 192 करोड़ 60 लाख रुपये की निधि आवंटित की थी. इस निधि का उपयोग सरकार ने कब, कहां किया, यह तो राज्य सरकार ही जाने. हां, इतना ज़रूर है कि उक्त निधि के उपयोग का असर इन नदियों में नहीं दिखाई दे रहा है. विशेष बात यह है कि इस निधि से शहरों से निकलने वाले गंदे प्रदूषित पानी को रासायनिक क्रिया द्वारा साफ़ करके नदियों में छोड़े जाने की योजना थी. इसके लिए नदी किनारे स्थित शहरों में शुद्धीकरण प्लांट स्थापित किए जाने थे, लेकिन अब तक प्लांट स्थापित नहीं किए गए जबकि पूरी निधि ख़र्च हो गई है. गोदावरी, कृष्णा और तापी नदियों के तट पर स्थित पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, नांदेड़, कराड, कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहरों से सबसे अधिक प्रदूषण होने की बात विशेषज्ञों ने अपनी जांच में ज़ाहिर की है. नदियों में बढ़ते प्रदूषण से नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ ही जैव विविधता को भी ख़तरा पैदा हो गया है.

केंद्र की राष्ट्रीय नदी कृति समिति योजना के तहत कृष्णा नदी के लिए कराड (3.19 करोड़), सांगली (25.55 करोड़), गोदावरी नदी के लिए नासिक (59.28 करोड़), नांदेड़ (12.72 करोड़) हेतु 100 करोड़ 74 लाख रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. राज्य के सात शहरों में 31 प्रकल्पों के लिए 192 करोड़ 60 लाख की निधि केंद्र ने दिया था. इस निधि का उपयोग मुंबई के पवई और कोल्हापुर का रंकाला तालाब में भी उपयोग किया जाना था. केंद्र की निधि के साथ राज्य सरकार के हिस्से की राशि भी शामिल थी. लेकिन क़रीबन 200 करोड़ की निधि ख़र्च करने के बाद भी परिणाम शून्य ही रहा है. जानकारों का कहना है कि उक्त शहरों का जिस गति से विस्तार हो रहा है उससे भी दोगुनी-तिगुनी तीव्रगति से प्रदूषण बढ़ रहा है. इतना ही नहीं राज्य सरकार ने जो भी काम तब कराया है वह भी गुणवत्ता के लिहाज़ से जांच का विषय है. सांगली शहर के बाहर जाने पर कृष्णा नदी में एक साल में बीओडी 6.3 से बढ़कर 9.4 हो गया है. इसी तरह पानी में प्राणवायु (ऑक्सीजन) घुलने की मात्रा (डीओ) 6 से घटकर 5.2 हो गई है. वहीं नासिक शहर में गोदावरी नदी के पानी बीओडी 6.8 से बढ़कर 25.83 हो गया है, जबकि ऑक्सीजन घुलने की मात्रा 4.78 से घट कर 2.27 तक यानी ख़तरनाक स्थिति तक पहुंच गया है. तेज़ी से फैल रहे पुणे शहर से लग कर बहने वाली नदियां मुठा, मुला और भीमा नदियों में भी प्रदूषण की मात्रा ख़तरनाक स्थिति तक पहुंच चुका है. इसलिए इन नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है. जानवर भी यदि इन नदियों का पानी पीता है तो उसके जीवन को भी ख़तरा हो सकता है. इस समस्या के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह लापरवाह है. उसने अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया है. केंद्रीय भूजल मंडल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में तक़रीबन 32.96 अरब घन मीटर पानी के संग्रह में वार्षिक वृद्धि होती है. उसमें से 32.21 अरब घन मीटर पानी की उपलब्धता है. इसके साथ ही 231 में से सात तहसीलों में लिफ्ट एरिगेशन की क्षमता ज़्यादा है, जबकि 23 तहसीलों में स्थिति काफ़ी चिंताजनक है. इस स्थिति में यदि सरकार ने नदियों में फैल रहे प्रदूषण के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करके अभी से उपाय नहीं करती है तो राज्य के कई नदियों व तालाबों का पानी उपयोग के लायक नहीं रह जाएगा. इससे निपटने के लिए सरकार को विशेषज्ञों की सलाह से यथाशीघ्र उपाय योजना करने की सख्त ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

न्याय के इंतज़ार में बीत गई आधी उम्र

किसी ने सच ही कहा है कि न्याय यदि देर से मिले, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन वर्तमान में देश में यही हो रहा है. किस्सा महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर ज़िले का है. यहां के एक मिल कामगार को न्याय मिलने में 22 वर्ष लग गए. एक खून के आरोप में सोलापुर सत्र न्यायालय ने उसे उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी, जिसे मुंबई उच्च न्यायालय ने पलटकर उसे इस आरोप से मुक्त कर दिया है.

देश में ऐसे कई मामले हैं, जिनसे जुड़े लोग न्यायालय की सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं, पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता. किसी का प्रापर्टी को लेकर विवाद है, तो कोई पारिवारिक विवादों के कारण न्यायालय के चक्कर लगा रहा है. किसी की नौकरी का मामला न्यायालय में है तो कोई सरकार और प्रशासन के ख़िलाफ़ न्यायालय से न्याय की गुहार कर रहा है. इनमें से कई मामलों में वर्षों बीत जाने के बाद भी फ़ैसला नहीं हो पाता, तो उससे जुड़े लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सोलापुर में सामने आया है. मामला वर्ष 1989 का है. सोलापुर स्थित वारद चाल के निवासी अप्पाराव कोल्हे का 10 अप्रैल 1989 को 5 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी. इसमें मृतक अप्पाराव का भाई मल्लीनाथ घायल हो गया था. चावड़ी पुलिस ने मामले की जांच कर सोलापुर की नरसी गिरजा मिल में काम करने वाले बालू कोंडिबा ठेंगील सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. बालू ठेंगील ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि चाल मालिक पाटिल और अप्पाराव के बीच शुरू विवाद में वे हमेशा चाल मालिक का पक्ष लेते थे, इसलिए मृतक अप्पाराव की पत्नी भागिरथी ने उन्हें इस मामले में फंसाया है. बालू ने पुलिस से कहा कि जब अप्पाराव का खून हुआ, वे उस समय वहां मौजूद नहीं थे. उस समय वे मिल में काम कर रहे थे. इसे साबित करने के लिए उन्होंने लेबर ऑफिसर विश्वनाथ वडाजे, फोल्डिंग मास्टर नारायण कलसूलकर, जॉबर शिवाजी बोधाले, पे-शीट क्लर्क शंकरय्या चडचंचकर को साक्षीदार बनाया था. सभी ने अपने बयान में कहा था कि जिस दिन खून हुआ, उस दिन बालू सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पूरा दिन मिल में काम कर रहा था. इतना ही नहीं हत्या के दरम्यान यानी शाम 4.30 बजे उसने अपना वेतन लिया था. इतना होने के बाद भी सत्र न्यायालय ने इन सबूतों को खारिज़ कर प्रत्यक्षदर्शी भागीरथी के बयान पर विश्वास किया और बालू को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई. सबसे हैरानी की बात यह है कि भागीरथी के ही बयान पर विश्वास नहीं रख सत्र न्यायालय ने अन्य 4 आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए थे. इस हमले में घायल मल्लीनाथ, मृतक अप्पाराव के ससुर विष्णु खांडेकर व साले ने अपने बयान में कहा था कि जिस समय खून हुआ, वे वहीं थे और उन्होंने बालू को ही खून करते हुए देखा था, लेकिन तीनों बाद में अपने बयान से मुकर गए थे. इसके बाद भी बालू को आरोपी घोषित कर उसे उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई.

बालू ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन वहां भी एक तरह से उसके साथ अन्याय ही हुआ. उनकी अपील 20 वर्षों तक उच्च न्यायालय में प्रलंबित रही. न्यायाधीश विद्यासागर कानडे और न्यायाधीश कमल किशोर तातेड ने अपील को मंजूर कर बालू ठेंगली को निर्दोष मुक्त करने के आदेश दिए. उच्च न्यायालय ने कहा कि बालू के ख़िलाफ़ जो सबूत पेश किए गए हैं, वे उसे आरोपी साबित करने के लिए काफी नहीं हैं. उल्टे जिस समय खून हुआ, वह वहां उपस्थित नहीं था, यह साबित करने के लिए बालू ने जो सबूत दिए हैं, उससे उसकी बात सही साबित होती है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर देश की न्यायालयीन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि किसी व्यक्ति को न्याय हासिल करने में 20-22 वर्षों का समय लग जाता है, तो उस न्याय के क्या मायने? अकेले महाराष्ट्र में ही 27 लाख से अधिक मामले प्रलंबित हैं. वर्ष 2010 में इनमें से भी क़रीब 13 लाख मामले ही सुनवाई के लिए आ पाए और केवल 6.8 फ़ीसदी मामलों में ही न्यायालय अपना निर्णय दे पाया है. ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र सहित देश में ऐसे कितने बालू होंगे, जो न्याय की प्रतीक्षा में हैं. सरकार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द न्यायालयीन प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए ठोस क़दम उठाना चाहिए.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

अब बाला साहब ठाकरे क्या करेंगे?

कभी-कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिन पर विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन हक़ीक़त को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता है. विश्वास इसलिए नहीं होता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की विरासत को ढोने वालों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे देह व्यवसाय जैसे निकृष्ट धंधे में लिप्त हो सकते हैं. दूसरी बात यह है कि शिवसेना हमेशा वेलेन्टाइन डे और फ्रेंडशिप डे आदि का विरोध करती है. उक्त दिनों को मनाने वाले युवक-युवतियों को सबक सिखाने के लिए आक्रामक अभियान चलाती है. लड़के-लड़कियों को सरेआम शर्मसार करने में भी शिवसेना के सैनिकों को गुरेज़ नहीं रहता है. कई बार वे लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी मर्यादा क्या होनी चाहिए. ऐसी भारतीय संस्कृति व हिन्दू रीति-रिवाज़ों को मानने वाली सेना के किसी सिपहसालार के घर के बीयर बार में लड़कियों से देह व्यवसाय कराने की घटना सामने आए तो एकाएक विश्वास नहीं होगा, लेकिन हक़ीक़त तो यही है कि शिवसेना के वरिष्ठ विधायक रामदास कदम की पत्नी के नाम पर चल रहे बीयर बार में पुलिस ने छापा मारा. छापे में पुलिस ने 9 लड़कियों को देह व्यवसाय में लिप्त पाया. इस हक़ीक़त को झुठलाना अब शिवसेना और उनके नेताओं को मुश्किल होगा. आखिर बालासाहब ठाकरे जी आपकी शिवसेना में ये हो क्या रहा है? दूसरों को हिन्दू, हिन्दू संस्कृति और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली आपकी सेना के सिपहसालारों को हो क्या गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने सेना नायकों को सही तरीके से नैतिकता के पाठ का अभ्यास नहीं कराया है? कहीं न कहीं आपकी शिक्षा-दीक्षा में चूक हो गई है. वरना क्या बात है कि विधानसभा के अंदर बार बालाओं के मामले को लेकर हंगामा करने वाले आपके विधायक के बीयर बार में ही बार बालाओं का डांस चल रहा है, देह व्यवसाय कराया जा रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ कि हम करें तो जायज़ और दूसरा करे तो नाजायज़. यह तो सरासर दोहरे चरित्र की राजनीति का फंडा है. कम से कम रामदास कदम जैसे वरिष्ठ नेता से राज्य के लोगों को यह अपेक्षा कतई नहीं थी कि उनकी पत्नी के नाम पर चल रहे बार में यह गोरखधंधा किया जा रहा है. हां, कदम साहब यह जरूर कह सकते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं था. बार का लाइसेंस पत्नी के नाम पर है. उसे चलाने के लिए किसी और को दिया गया है, लेकिन इन तमाम बहानों पर अब कौन विश्वास करेगा? इस घटना से यह बात पुनः सिद्ध हो गई कि हर पार्टी का नेता दोहरा चरित्र जीता है और उसके सारे काम दिखाने और करने के कुछ और होते हैं. समझ में यह नहीं आता है कि रामदास कदम जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि,

जिन्हें पूरे राज्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी तुरंत मिल जाती है, उसे अपने परिवार के बीयर बार में चल रहे अवैध धंधे की जानकारी कैसे नहीं होगी? अब राज्य की जनता के मन में जिज्ञासा यह है कि शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे इस घृणित मामले के उजागर हो जाने के बाद रामदास कदम के ख़िलाफ़ क्या कदम उठाते है? कौन-सा दंड देते हैं? सावली का सच उजागर हो जाने के बाद शिवसेना प्रमुख को या तो दूसरों को नैतिकता का पालन करने की सलाह देना बंद करना होगा या फिर रामदास कदम के ख़िलाफ़ कठोर क़दम उठाना होगा. ताकि लोगों को पता चले कि वे सभी के प्रति एक जैसा मापदंड अपनाते हैं.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

करोड़ों का बिजली घोटाला

सिंचाई, आदर्श, पाटलीपुत्र सोसायटी, अनाज, खेल आदि घोटालों के बाद राज्य में बिजली घोटाला चर्चा में है. आरोप है कि बिजली की ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने और नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव में विद्युत वितरण की ज़िम्मेदारी फ्रेंचाइजी को देने में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है, लेकिन राज्य के उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री अजीत पवार इसे सिरे से ख़ारिज करते हैं. विधानसभा में तो उन्होंने विपक्षी पार्टियों को ही सबूत देने की चुनौती दे डाली. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने से क्यों डर रही है?

पिछले दिनों नागपुर में हुए राज्य विधान मंडल के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान विधानसभा में विरोधी दल के नेता एकनाथराव खड़से ने ऊर्जा विभाग में करोड़ों रुपये का घोटाला होने का आरोप लगाया था. इस पर अजीत पवार ने तिलमिलाकर कहा कि पहले सबूत दें, फिर कार्रवाई होगी. अब सवाल उठता है कि क्या विरोधी दल के नेता खड़से बिना किसी सबूत के आरोप लगा सकते हैं? और यदि उनके पास कुछ सबूतों की कमी है, तो क्या उसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी खड़से की ही है? विपक्षी दलों ने भी विधानसभा में मांग की कि सरकार जांच की शुरुआत करे, वे तभी सबूत देंगे. विरोधी पार्टियों के विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार के सामने ऐसी कौन-सी मजबूरी आ गई थी कि केवल दो वर्षों में बिजली की दरों में 9 बार बढ़ोत्तरी करनी पड़ी. सीएजी की रिपोर्ट में बिजली के काम करने वाले ठेकेदारों को 212 करोड़ रुपये अधिक दिए जाने का खुलासा किया गया है. नागपुर, भिवंडी, जलगांव, औरंगाबाद में विद्युत वितरण और बिल वसूली के लिए निजी कंपनियों को लाया गया. इन निजी कंपनियों में से स्पैनको पर 221 करोड़ और जीटीएल पर 166 करोड़ रुपये का बक़ाया है. इनसे वसूली की हिम्मत वितरण कंपनी नहीं दिखा पा रही है.

कार्यक्षमता पर सवाल उठे

राज्य सरकार ने 2 हज़ार 572 करोड़ 31 लाख रुपये की स्वतंत्र गांवठान फीडर योजना शुरू की. योजना की 80 फ़ीसदी राशि ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडल और 20 फ़ीसदी राशि राज्य सरकार को देनी थी. पहले चरण में 20 ज़िलों के 7 हज़ार 893 गांव और 1 हज़ार 109 देहातों के लिए 1 हज़ार 446 करोड़ रुपये ख़र्च किए जाने थे. दूसरे चरण में 23 ज़िलों के 8 हज़ार 714 गांव और 2 हज़ार 20 देहातों में 1 हज़ार 446 करोड़ रुपये ख़र्च करने का प्रस्ताव था. बाद में राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 8 हज़ार 918 करोड़ 15 लाख रुपये की योजना बनाई. इन योजनाओं के अधिकांश काम अंतिम चरण में हैं, लेकिन इनमें लगाई गई सामग्री की क्वालिटी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. काम के पहले ही पूरी राशि उठाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं. कई विधायकों का आरोप है कि इसमें करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है, लेकिन पवार ख़ुद विपक्षी दलों से ही इसके सबूत मांग रहे हैं.

सभी आरोप ख़ारिज किए

अजीत पवार की मानें, तो ऊर्जा विभाग में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है. उनके अनुसार भुसावल की दो यूनिट में से मार्च तक 1000 मेगावॉट, खापरखेड़ा के एक यूनिट से दिसंबर तक 500 मेगावॉट, मौदा से अक्टूबर तक 185 मेगावॉट और अन्य स्थानों से दिसंबर 2012 तक 5980 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली राज्य सरकार को मिलने लगेगी. उन्होंने कहा कि इसके आधार पर वे कह सकते हैं कि दिसंबर 2012 तक राज्य लोडशेडिंग मुक्त हो जाएगा. पमर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जब दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो उनका एक ही नारा था, दिसंबर 2012 में राज्य लोडशेडिंग से मुक्त हो जाएगा. अब इस नारे को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने लपक लिया है. पिछले दिनों नागपुर में हुए राज्य विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में उन्होंने आंकड़ों के साथ इस दावे को पुनः दोहराया. आंकड़ों की यी जादूगरी क्या दिसंबर 2012 में लोडशेडिंग ख़त्म होने का चमत्कार कर पाएगी? राज्य में वर्तमान में बिजली की ज़रूरत लगभग 14 हज़ार मेगावॉट है, जबकि कभी दूसरे राज्यों को बिजली बेचने वाले महाराष्ट्र राज्य में बिजली निर्माण लगभग साढ़े 5 हज़ार मेगावॉट का है.

राज्य सरकार निजी क्षेत्र से डेढ़ से दो हज़ार मेगावॉट बिजली ख़रीदती है. इसके अलावा राज्य को केंद्र के कोटे से लगभग 5 हज़ार मेगावॉट बिजली मिलती है. फिर भी 2 से ढाई हज़ार मेगावॉट की कमी हमेशा रहती है. यह तब है जब बिजली की मांग कम होती है. बिजली की मांग बढ़ने पर इसमें भी बढ़ोत्तरी हो जाती है और इसके साथ-साथ लोडशेडिंग में भी. जानकारों का मानना है कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को अपना बिजली उत्पादन 10 हज़ार मेगावॉट से ऊपर ले जाना होगा, तो क्या दिसंबर 2012 यानी एक वर्ष में राज्य सरकार इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी? पिछले 8-9 वर्षों से सरकार इस दावे को बार-बार दोहरा रही है. इससे पहले हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में लोडशेडिंग एक बड़ा मुद्दा था. उस दौरान भी सरकार ने पूरी ताक़त से आने वाले तीन वर्षों में राज्य को लोडशेडिंग से मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन वे तीन वर्ष भी गए और दूसरा चुनाव भी आ गया, किंतु लोडशेडिंग बंद नहीं हुई. पिछले चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने इसी मुद्दे को आगे कर लोडशेडिंग ख़त्म करने के लिए वर्ष 2012 की नई समय सीमा दे दी थी. वे गए और बाद में अजीत पवार उपमुख्यमंत्री बने. उन्होंने वर्ष 2012 में दिसंबर इस विशेषण को जोड़ दिया. उल्लेखनीय है कि पवार ख़ुद ऊर्जा मंत्री हैं. इसके साथ उनके पास वित्त मंत्रालय भी है. ऐसे में उनके दावे को सिरे से ख़ारिज नहीं किया जा सकता. किंतु यदि वे अपने ही ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली पर नज़र दौड़ाएं, तो उन्हें सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

दादा को चीन पर भरोसा नहीं

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी बिजली प्रकल्पों को पूरा करने के लिए लगने वाली मशीनों की आपूर्ति देश में केवल भेल कंपनी करती है. उस पर सभी राज्यों के ऑर्डर पूरे करने का दबाव होता है, इसलिए मशीनों के मिलने में वक़्त लगने के कारण प्रकल्पों को पूरा करने में देरी हो रही है. उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां चीन की कंपनियों से मशीनें ख़रीदती हैं. ऐसे में उनके प्रकल्प जल्दी तैयार हो जाते हैं. किंतु जांच में पाया गया है कि उन मशीनों की क्वालिटी भेल की मशीनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी की है. इसलिए राज्य सरकार ने चीन की कंपनियों से मशीनें नहीं ख़रीदने का निर्णय लिया है.

पवार भी नहीं कर पाए वसूली

राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को दबंग कहा जाता है. प्रशासन पर उनकी कितनी पकड़ है, यह सभी जानते हैं, लेकिन उनकी यह दबंगता केवल सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित है. निजी कंपनियों के मामले में वे भी अन्य नेताओं की तरह कमज़ोर साबित हो रहे हैं. ग़ौरतलब है कि राज्य विधान मंडल के शीतकालीन अधिवेशन के आख़िरी दिन ऊर्जा विषय पर चर्चा हुई थी. इसमें विपक्षी पार्टियों ने नागपुर और औरंगाबाद शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था संभाल रही फ्रेंचाइजी स्पैन को एवं जीटीएल कंपनी पर क्रमशः 221 और 166 करोड़ रुपये बक़ाया होने का मुद्दा उठाया था. इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि दोनों कंपनियों से बक़ाया राशि 31 दिसंबर, 2011 तक वसूल कर ली जाएगी, लेकिन इस संबंध में जब महावितरण कंपनी से संपर्क किया गया, तो जनवरी के पहले सप्ताह तक दोनों कंपनियों को बक़ाया राशि का भुगतान नहीं किया था.

महाराष्ट्र हलचल

विदर्भ हॉकी संगठन की ओर से नागपुर शहर में सीनियर डिवजन हॉकी स्पर्धा आयोजित की गई. अमरावती रोड पर वीएचए ग्राउंड पर खेली गई स्पर्धा के एक मैच में शहर पुलिस की टीम ने अनुग्रह स्पोर्टिंग क्लब को 16-0 से मात दी.

नागपुर शहर के भाडेवाड़ी में स्थित डंपिंग यार्ड की बदबू को ख़त्म करने के लिए प्रशासन से जल्द क़दम उठाने की मांग को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रिंगरोड टी-प्वाइंट में श्रृंखलाबद्ध अनशन किया.

प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट और शोध प्रतिष्ठान की ओर से अमरावती शहर में सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया. कार्यक्रम में फिल्म कलाकार गुलशन ग्रोवर, महिमा चौधरी, नृत्य निर्देशक बॉबी ख़ान के साथ पूर्व विधायक सुलभाताई खोडके, महापौर एड. किशोर खेलके, विजय भैसे, अविनाश मार्डिकर, चेतन पवार, प्रशांत डवरे, प्रभु झांबानी, ज़िलाधिकारी राहुल महिवाल आदि उपस्थित थे.

विदर्भ में ख़रीफ़ की फ़सल निकलते ही जगह-जगह बैलों की दौड़ (शंकरपट) का आयोजन किया जाता है. यह जनवरी माह के अंत तक चलता है. चंद्रपुर ज़िले में ऐसी ही एक स्पर्धा में हिस्सा लेते प्रतिभागी.

घरकुल की प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किए गए बीपीएल धारकों का जनता दरबार यवतमाल ज़िले के घटंजी स्थित नगरपालिका सांस्कृतिक सभागृह में आयोजित किया गया. दरबार में ज़िला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक ठाकरे ने समस्या को जल्द हल करने के लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजने की जानकारी दी.

वर्धा में बच्छराज धर्मशाला में विदर्भ अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का तृतीय अधिवेशन आयोजित किया गया. अधिवेशन में शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के कार्याध्यक्ष गजानन पाठक (पुणे), महासचिव रावसाहब त्रिभुवन (जलगांव), प्रकाश म्हस्के (पुणे), महासंघ के प्रतिनिधि सुरेश पवार, मारोती धोतरे (सांगली) आदि उपस्थित थे.

गड़चिरोली ज़िले के शिवाजी शिक्षण संस्था के स्वर्ण महोत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया.

राज्य सरकार यहां नल से शुद्ध पानी की जलापूर्ति करना तो दूर, वह केवल कागज़ी घोड़े दौड़ा कर जनता को बेवकूफ बनाने में लगी है.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

विदर्भ

पानी के बदले ज़हर पी रहे हैं हज़ारों परिवार

मयूर रंगारी

विदर्भ के अमरावती, बुलढाना,अकोला, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर और भंडारा ज़िलों के सैकड़ों गांवों में लाखों लोग रोज़ जहरीला पानी पीने के लिए मज़बूर हैं. स्थिति यह है कि इससे सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. वहीं हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं, जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. अमरावती, अकोला, वाशिम एवं बुलढाना ज़िलों के लोगों की खारे पानी से और यवतमाल, चंद्रपुर और भंडारा ज़िलों के लोगों की फ्लोराइड युक्त पानी के कारण ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है. यहां पाए जाने वाले भूजल स्तर में कई घातक रसायन तय मात्रा से अधिक पाए गए हैं. उधर, राज्य सरकार यहां नल से शुद्ध पानी की जलापूर्ति करना तो दूर, वह केवल कागज़ी घोड़े दौड़ा कर जनता को बेवकूफ बनाने में लगी है. जलापूर्ति की सुविधा नहीं होने से लोगों को शुद्ध पानी 15 से 20 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार अमरावती ज़िले की 14 में से 6 तहसीलों के 355 गांव, अकोला ज़िले की 7 में से 5 तहसीलों के 373 गांव और बुलढाना ज़िले की 13 में से 5 तहसील के 166 गांवों (कुल 894) गांव खारे पानी पट्टे में आते हैं. इसका कुल क्षेत्रफल 4692 चौरस किलोमीटर है. राज्य सरकार के अनुसार वाशिम व यवतमाल ज़िले का कोई भी गांव खारे पानी पट्टे में शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दिनों राज्य विधानमंडल के नागपुर में हुए शीतसत्र के दौरान विधायक डॉ. संजय कुटे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी. उन्होंने बताया कि अमरावती विभाग के बुलढाना, अकोला, वाशिम, अमरावती और यवतमाल ज़िलों के एक हज़ार से भी अधिक गांवों में पाए जाने वाले भूजल में कैडमियम, लेड, मैग्नेशियम, मरक्यूरी जैसे शरीर के लिए घातक रसायन मिले हैं. अकेले बुलढाना ज़िले के शेगांव, जलगांव जामोद व संग्रामपुर तहसील के 200 गांव इस खारे पानी पट्टे में

आते हैं. नल से शुद्ध जलापूर्ति की सुविधाएं नहीं होने से लोगों को मजबूरन भूजल पर ही निर्भर रहना पड़ता है. इसके कारण यहां किडनी ख़राब होने के मामले तेज़ी से सामने आ रहे हैं. इसके अलावा पेट से संबंधित गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं. राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहां दूषित पानी पीने से पिछले तीन वर्षों में बुलढाना ज़िले में ही 112 मरीज़ों की मौत हो गई है, लेकिन जानकारी है कि उपराक्त ज़िलों में दो सौ से अधिक लोगों की किडनी ख़राब होने से मौत हो गई है.

मंत्रालय से वापस हो जाती हैं फाइलें

यह मुद्दा इतना गंभीर होने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से खारे पानी पट्टे में शामिल सैकड़ों गांवों में शुद्ध पानी की जलापूर्ति के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाया जा रहा है. इन क्षेत्रों के विधायकों ने विधानसभा में आरोप लगाया कि मुंबई मंत्रालय में बैठने वाले अधिकारी और कुछ मंत्री जानबूझकर यहां की जलापूर्ति योजनाओं को समय के अंदर पूरा नहीं कर रहे. छोटे–छोटे कारण बताकर मंत्रालय से जलापूर्ति योजनाओं की फाइलें वापस भेजी जाती हैं. समय पर उपाय योजनाएं नहीं करने से खारे पानी का पट्टा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में जो गांव पहले इससे प्रभावित नहीं थे, आज वहां के पानी में भी घातक रसायन पाए जा रहे हैं. यदि ऐसा ही चलता रहा तो मरने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है.

मंत्री ने भी माना जानकारी सही है

राज्य सरकार के जलापूर्ति मंत्री लक्ष्मणराव ढोबले ने भी विधानसभा में माना कि खारे पानी के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हैं और इससे कई लोगों की किडनी ख़राब होने के कारण मौत हो गई है. ऐसा होने के बावजूद इन क्षेत्रों के लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार का रवैया उदासीनतापूर्ण है. राज्य सरकार द्वारा जलगांव जामोद व संग्रामपुर तहसील में 127 स्थानों से पानी के नमूने एकत्र किए गए, जिनकी रासायनिक जांच फूड हाईजीन एंड हेल्थ लेबोटरीज, पुणे में की गई. जांच में 8 पानी के नमूनों में मरक्यूरी , एक में लेड, 2 में कॉपर, 43 में कैडमियम और 7 नमूनों में कैलशियम की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई. यानी 61 नमूने दूषित पाए जाने की रिपोर्ट खुद राज्य सरकार ने दी है. बताया जाता है कि बुलढाना ज़िले के तीन तहसीलों में 3 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए. इनमें लगभग 3 हज़ार लोगों को किडनी की बीमारी होने के तथ्य सामने आए हैं. इतने बड़े पैमाने में लोगों को किडनी की बीमारी होने की बात खुद राज्य सरकार द्वारा माने जाने के बाद भी उक्त ज़िलों के सरकारी अस्पतालों में इसके उपचार से संबंधित सुविधाएं नहीं हैं. डायलिसिस और लेप्रोस्कोपी मशीन इन ज़िलों के तहसील स्तरीय अस्पतालों में नहीं हैं. ऐसे में उपचार के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें निजी अस्पतालों में जाकर इलाज़ कराना पड़ता है.

141 गांवों को पानी, शेष गांवो का क्या होगा

राज्य सरकार के जलापूर्ति मंत्री लक्ष्मणराव ढोबले ने बताया कि वान बांध से बुलढाना ज़िले की जलगांव जामोद और संग्रामपुर तहसील के 141 गांवों के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था आगामी दो वर्षों में की जाएगी. ग़ौरतलब है कि यह योजना पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लटकी पड़ी है. इसे पूरा करने में कम से कम 3 वर्ष लगेंगे, लेकिन सरकार इसे दो वर्षों में पूरा करने की बात कर रही हैं. इसे पूरा करने के लिए संबंधित गांवों की ग्राम पंचायतों को ख़र्च की 10 फ़ीसदी राशि देनी होगी. हालांकि सरकार ने इसमें कमी लाकर 7 से 8 फ़ीसदी करने का वादा किया है, लेकिन अनुमान है कि इसके बावजूद यह राशि 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत इतनी अधिक राशि कहां से लाएगी? सरकार 141 गांवों को तो जलापूर्ति करने की बात करती है, लेकिन बाकी बचे सैकड़ों गांवों के लिए आखिर उसने क्या उपाय योजना बनाई है, इसका खुलासा नहीं करती. इसके अलावा सरकार ने इन क्षेत्रों में पानी की जांच के लिए 18 लैब बनाने के लिए 18 लाख रुपये देने की भी घोषणा की है, लेकिन सवाल यह है कि लैब में पानी टेस्ट करने के बाद क्या होगा? यदि पानी दूषित पाया जाता है, तो वहां कितने दिनों में जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी? इसका कोई नियोजन राज्य सरकार के पास नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

लाइलाज़ है फ्लोरोसिस बीमारी

भूगर्भ में पाए जाने वाले टोपाज, एपेटाइट, फ्लोराइड, बैराइट, कैल्साइट खनिजों का पानी से संपर्क होने पर वे उसमें घुल जाते हैं. इससे पानी में फ्लोराइड घुलता है. फ्लोराइड की मात्रा पाए जाने वाले खनिज ज़मीन में काफी नीचे होते हैं. ऐसे में कुएं की अपेक्षा बोरवेल में फ्लोराइड युक्त पानी अधिक पाया जाता है. यह पानी पीने से होने वाली फ्लोरोसिस बीमारी लाइलाज़ है. यवमताल, चंद्रपुर और भंडारा ज़िले के प्रभावित गांवों में इस बीमारी से हज़ारों मरीज़ ग्रसित हैं. यह बीमारी वर्ष 1930 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तहसील में किसानों ने खोजी थी. उस समय फ्लोराइड युक्त पानी पीने से जानवरों की हड्डियां कमज़ोर होने के प्रमाण सामने आए थे.

फ्लोराइड ने बनाया समय से पहले बूढ़ा

विदर्भ के यवतमाल, चंद्रपुर और भंडारा ज़िलों के किसी गांव से गुजरते समय यदि आपको किसी व्यक्ति की मुड़ी हुईं हड्डियां नज़र आए तो चौंकिएगा मत. यह किस्मत खुद सरकार ने इनके लिए लिखी है. इन गांवों के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा तय मानक से कहीं अधिक पाई गई है. यहां शुद्ध जलापूर्ति की सुविधा नहीं होने से हज़ारों लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए विवश हैं, जिससे लाइलाज़ फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है. इससे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं. वहीं हज़ारों लोगों की स्थिति यह है कि वे समय से पहले ही बूढ़े हो गए हैं. तय मानक के अनुसार पानी में फ्लोराइड का प्रमाण 1.3 पी.पी.एम. तक होना चाहिए, लेकिन यवतमाल, चंद्रपुर और भंडारा ज़िलों के सैकड़ों गांवों के भूजल में फ्लोराइड का प्रमाण 18 पी.पी.एम. है. विशेष बात यह है कि खारे पानी को स्वाद से पहचाना जा सकता है, लेकिन अधिक फ्लोराइड युक्त पानी की पहचान केवल जांच से ही हो पाती है, क्योंकि इसमें रंग, स्वाद, गंध नहीं होता. शरीर को फ्लोराइड की ज़रूरत होती है. यह पानी और खाद्य पदार्थ के माध्यम से शरीर को मिलता है, पर इसका प्रमाण अधिक होने पर यह नुक़सान पहुंचाने लगता है. इसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं. दांत, हाथ और पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं. त्वचारोग, वृद्धत्व की बीमारियां होती हैं. फ्लोराइड युक्त पानी से लोगों को बचाने का एकमात्र उपाय इन गांवों में शुद्ध जलापूर्ति करना है, लेकिन इस संबंध में कई बार राज्य सरकार के पास मांग करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है. शुद्ध जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं होने से लोग अपने घरों में बोरवेल लगवाते हैं. उसी का पानी पीते हैं. ऐसे में रोज़ाना यह दूषित पानी उनके शरीर में जा रहा है. इन गांवों के आसपास से नदियां प्रवाहित होती हैं. कई बड़े तालाब यहां हैं, जिसके जल को शुद्ध कर गांवों में जलापूर्ति की जा सकती है, लेकिन सरकार केवल घोषणाओं के अलावा कोई क़दम नहीं उठा रही है. यवतमाल ज़िले के लगभग 454 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी पाया गया है. ज़िले की सभी 16 तहसीलें इससे बाधित हैं. राज्य सरकार ने ज़िले के लगभग 1200 कुओं और बोरवेल की जांच कराई थी, जिसमें सभी का पानी दूषित पाया गया था. इसके बावजूद अब तक प्रशासन ने ज़िले में केवल 24 स्थानों पर फ्लोराइड रिमूवल मशीनें लगाई हैं. हैरत की बात यह है कि सैकड़ों स्थानों पर इन मशीनों को लगाने की मांग हो रही है. दूसरी ओर प्रशासन की मानें तो उसके पास केवल 11 स्थानों पर मशीनें लगाने का प्रस्ताव आया है. इससे स्पष्ट होता है कि सरकार व प्रशासन समस्या के प्रति कितने गंभीर हैं.

फ्लोराइड ग्रस्त गांवों में पहले प्रशासन की ओर से टैंकर से जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन भारत निर्माण योजना के तहत जलापूर्ति के कामों को किए जाने से प्रशासन ने टैंकर से जलापूर्ति रोक दी है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि अभी भी कई गांवों में जलापूर्ति के काम अधूरे हैं. जहां काम हुआ भी है, वहां अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है. ऐसे में इन गांवों में टैंकर से होने वाली जलापूर्ति रोक देने से लोगों को मजबूरन पुनः फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है.

फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हज़ारों लोगों की हड्डियां मुड़ गई हैं. ऐसे में यहां के लड़के–लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण यह सामाजिक समस्या भी बन गई है. साथ ही दूषित पानी मवेशियों को भी दिया जाता है, जिसके कारण मवेशियों की हड्डियां भी कमज़ोर होने की बात सामने आई है, इससे ग्रामीणों को आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है. समस्या का हल निकालने के लिए कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इन गांवों के लोगों के शरीर में कैलशियम की मात्रा बढ़ाने के उपाय व सुझाव सरकार को दिए थे. मसलन दूध अधिक पीने और सीताफल जैसे फल जिनसे कैलशियम की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलेगी, उनके पौधे संबंधित गांवों में लगाने की मांग की गई थी पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है. पहले खाने में इमली का उपयोग अधिक होता था, जिससे फ्लोराइड की मात्रा शरीर में कम करने में मदद मिलती थी, लेकिन समय के साथ इमली की जगह टमाटर ने ले ली. टमाटर में यह गुण नहीं पाया जाता पर इसकी जनजागृति करने का काम भी सरकार नहीं कर रही है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 16 जनवरी–22 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड–बिहार में हो सबका मकान

SANJEEVANI BUILDCON

3rd & 4th floor, GEL Church Complex, Main Road, Ranchi, Customer Care No. - 0651-2331429

Sanjeevani Dynasty-I
PLOT-13 LAC, DUPLEX-25 LAC
Near Ranchi College

Sanjeevani Dynasty-II
PLOT-10 LAC, DUPLEX-22 LAC
Booty More

Future City (BIT)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Namkom)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Pithoria)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Sanjeevani Mega Township
PLOT-3.5 LAC, BUNGLOW-09 LAC
Hazaribagh

मिला रुपय्या, ख़र्चा चवन्नी

फिर क्यों पैसों का रोना

बिहार सरकार के कुछ विभाग नौ माह बीत जाने के बावजूद योजना बजट की केवल एक से पांच प्रतिशत राशि ही ख़र्च कर पाए तो इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी. क्या इस पैसे के सदुपयोग के लिए भी केंद्र सरकार की इजाज़त की ज़रूरत है? इस बात की गारंटी कौन देगा कि बचे हुए तीन महीने में सारी राशि सही तरीके से ख़र्च हो जाएगी और मार्च लूट नहीं होगा. क्या सरकार के इन विभागों के पास पूरे साल काम करने का कोई ब्ल्यू प्रिंट नहीं था और सारी कवायद हवा में चल रही थी?

सरोज सिंह

बिहार सरकार हमेशा पैसे का रोना रोते रहती है, पर जो पैसा है और केंद्रीय योजनाओं के समय सीमा से क्रियान्वयन से जो पैसा मिल सकता है इसकी दुर्दशा देखकर लगता है कि नीतीश सरकार महज़ बनावटी आंसू गिरा रही है. सरकार के आंकड़े बताते हैं कि योजना बजट में अब तक दस हज़ार करोड़ ही खर्च हो पाए हैं. सरकार को बचे हुए तीन महीने में 14 हज़ार करोड़ खर्च करने की चुनौती है. अब बस अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है. या तो पैसे लौटेंगे या फिर ख़र्च के नाम पर ज़्यादातर पैसे का बंदरबांट होगा यानी मार्च लूट. हालांकि मुख्यसचिव नवीन कुमार ने अधिकारियों को विकास कार्य पर होने वाले ख़र्च में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है.

पिछले दिनों योजना आयोग के पूर्व सचिव व सलाहकार एनसी सक्सेना ने मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान और एनआरचएच जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा ख़र्च करने में बिहार सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कारण यह सूबा 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपये का अनुदान पाने में पीछे रह गया है. सुशील मोदी की उपस्थिति में सक्सेना के इस ख़ुलासे से हड़कंप मच गया. अगले दिन पूरी सरकार बचाव में उतर आई.

सक्सेना ने कहा कि बिहार सरकार यदि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि को समुचित ढंग से ख़र्च करे तो इसे 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकते हैं. देश के प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अच्छा प्रदर्शन कर केंद्र प्रयोजित योजनाओं में बिहार से अधिक राशि प्राप्त कर रहे हैं. इसका कारण है कि बिहार में ख़र्च, पारदर्शिता और नियंत्रण के लिए समुचित प्रशासनिक तंत्र नहीं है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत बिहार को बीते वर्ष 780 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि हिस्सा 1300 करोड़ रुपये होना चाहिए था. ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने मिड डे मील योजना का सौ फ़ीसदी अनुदान ख़र्च किया, लेकिन बिहार 60 फ़ीसदी ही ख़र्च कर पाया. सर्वशिक्षा अभियान में भी राज्य सरकार बजट का 52 फ़ीसदी ही ख़र्च कर पाई. केरल जैसे राज्यों की जनसंख्या कम रहने के कारण वित्त अयोग से इन्हें मिलने वाला पैसा पर्याप्त होता है. आयोग 1971 की जनसंख्या के आधार पर बिहार को पैसा देता है. राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए कि 1991 या 2001 के आधार पर वित्तीय मदद की जाए, इससे ग़रीब राज्य होने के बावजूद राज्य को अच्छी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में समन्वित बाल विकास परियोजना के सुपरवाइज़र के 93 फ़ीसदी पद रिक्त हैं. ऐसे ही कई अन्य मामलों में बिहार में शिक्षकों चिकित्सकों की भी भर्तियां नहीं हुई हैं. बिहार में बच्चों का नामांकन बढ़ा है लेकिन छात्रों की उपस्थिति अब भी एक बड़ी समस्या है. उन्होंने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर कहा कि बिहार का जीडीपी अब भी देश के सबसे अधिक जीडीपी वाले राज्य महाराष्ट्र का पांचवां हिस्सा है. कृषि की दुर्दशा इस बात से झलकती है कि वर्ष 2000–01 में उत्पादन एक करोड़ 14 लाख टन था और वर्ष 2008–09 में यह एक करोड़ 17 लाख टन ही रहा. अनाज इत्पादन में बिहार में एक ठहराव की प्रवृति देखी गयी है. उन्होंने कहा कि बिहार को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में स्वास्थ्य की दिशा में अपनाये जा रहे बेहतर उपायों को आजमाना चाहिए. धान की खरीद के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मॉडल का अनुकरण करना चाहिए. बिहार में पीडीएस व्यवस्था में लीकेज अधिक है. सक्सेना के इस ख़ुलासे के बाद सरकार हरकत में आई.

राज्य सरकार ने मनरेगा में ख़र्च को लेकर योजना आयोग के सलाहकार डॉ. एन.सी. सक्सेना के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि डॉ. सक्सेना द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट सच्चाई से परे है. केंद्र सरकार के लगातार असहयोग के बावजूद बिहार मनरेगा के कार्यान्वयन में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है. मनरेगा की ऑडिट को समय सीमा के भीतर कराना अनिवार्य किया गया है. राज्य स्तर पर राशि उपलब्ध कराने के लिए विशेष कोष बनाया गया है. इस वर्ष कॉर्पस कोष से भी 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं. मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ग्रामीण ग़रीबी सबसे अधिक है. इसमें मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी पांच राज्यों में मनरेगा में भगीदारी और ख़र्च एक ही तरह है. वित्तीय वर्ष कॉर्पस 2010–11 में बिहार ने 2664 करोड़ रुपये ख़र्च किये हैं. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने 631 करोड़, महाराष्ट्र ने 358 करोड़, मध्य प्रदेश ने 3637 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 2532 करोड़ और उड़ीसा ने 1533 करोड़ रुपये ख़र्च किये. मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार अक्सर वित्तीय वर्ष के अंत में राशि विमुक्त करती है. वित्तीय वर्ष 2008–09 2009–10 और 2010–11 के अंत में क्रमश: 30 प्रतिशत 37 प्रशित और 29 प्रतिशत राशि दी गयी. इस संबंधित वित्तीय वर्ष में राशि का पूर्ण उपयोग किया जाना संभव नहीं हो पाता है. दूसरी तरफ सुशील मोदी ने अलग राग अलापते हुए कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों में अपनी योजनाओं की संख्या कम करनी चाहिए. केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 147 से घटाकर 30 कर देनी चाहिए. इससे राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना तैयार कर सकते हैं. चतुर्वेदी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को राज्यों में अपनी योजना कम करने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में काफी अधिक राशि राज्यांश के रूप में देनी पड़ती है. बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को राज्यांश उपलब्ध कराने की बाध्यता होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि विभागवार ख़र्च के प्रतिशत का जो आंकड़ा आया है वह सक्सेना के विचारों को ही सत्यापित करता है. यह सरकार केवल झूठे वादे कर रही है. सरकार की मंशा बस लूट की है. अब सवाल उठता है कि रास्ता निकलेगा कैसे. केंद्रीय योजनाएं कम करने से क्या विकास की गाड़ी तेज़ी से बढ़ेगी या फिर कुशल वित्तीय प्रबंधन और काम करने की इच्छाशक्ति चीजों को आगे ले जाएगी. अगर बिहार के सरकार के कुछ विभाग नौ माह बीत जाने के बावजूद केवल एक से पांच प्रतिषत राशि ही ख़र्च कर पाए तो इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी. क्या इस पैसे के सदुपयोग के लिए भी केंद्र सरकार की इजाज़त की ज़रूरत है. इस बात की गारंटी कौन देगा कि बचे हुए तीन महीने में सारी राशि सही तरीके से ख़र्च हो जाएगी. क्या सरकार के इन विभागों के पास पूरे साल काम करने का कोई ब्ल्यू प्रिंट नहीं था और सारी कवायद हवा में चल रही थी अब जब तीन महीने बचे हैं तो मारा मारी मची है.

feedback@chauthiduniya.com

सक्सेना ने कहा कि बिहार सरकार यदि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि को समुचित ढंग से ख़र्च करे तो इसे 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकते हैं. देश के प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अच्छा प्रदर्शन कर केंद्र प्रयोजित योजनाओं में बिहार से अधिक राशि प्राप्त कर रहे हैं. इसका कारण है कि बिहार में ख़र्च, पारदर्शिता और नियंत्रण के लिए समुचित प्रशासनिक तंत्र नहीं है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत बिहार को बीते वर्ष 780 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि हिस्सा 1300 करोड़ रुपये होना चाहिए था.

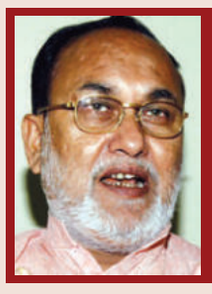

“विभागवार ख़र्च के प्रतिशत का जो आंकड़ा आया है, वह सक्सेना के विचारों को ही सत्यापित करता है. यह सरकार केवल झूठे वादे कर रही है. सरकार की मंशा बस लूट की है.– अब्दुल बारी सिद्दीकी, नेता प्रतिपक्ष”

“डॉ. सक्सेना द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट सच्चाई से परे है. केंद्र सरकार के लगातार असहयोग के बावजूद बिहार मनरेगा के कार्यान्वयन में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है.– नीतीश मिश्रा”

नीतीश कुमार ने कहा कि बयान देने से पहले ज़मीनी सच्चाई का आकलन ज़रूर कर लीजिए। पीछा होना है कि इस माह का वेतन न देने वाले विधायकों की भी सार्वजनिक तौर पर क्लास लगाई गई।

कुछ कर्मचारी तो अवैध प्रोन्नति का लाभ लेकर रिटायर्ड हो गये तो कई दूसरे ज़िलों में स्थानांतरित हो गए।

राजगीर में कुछ खट्टा, कुछ मीठा

कुमार प्रशांत

पूर्णिया स्वास्थ्य विभाग
अवैध प्रोन्नति पर चांदी काट रहे हैं

नीरज कुमार सिंह

ग़रीबों को जॉब कार्ड का इंतज़ार

शुभम रानी चौहान

महिलाएं खान-पान पर ध्यान रखें: विनीता

डॉ. विनीता वर्मा

ठंड में सर्दी-खुकाम से बचने के क्या उपाय हैं?

ज़्यादातर महिलाएं मोटापे से परेशान रहती हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं?

कब्ज़ से ज़्यादातर लोग प्रसित हैं, क्या करने की आवश्यकता है?

प्रस्तुति अमीषा कर्ण

एक नज़र

कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन

कवि सम्मेलन आयोजित

मगध वि.वि. में भारी अराजकता

सीमांचल में भाजपा का जनाधार बढ़ा

प्रो. अरुण कुमार सम्मानित

सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सामग्री वितरित

विधायक पर दुरुपयोग का आरोप

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बंदी से आक्रोश

पुण्यतिथि पर ग़रीबों में कंबल बंटे

सारण एक नज़र

प्रधानमंत्री का पुतला फूंका

जयंती समारोह सह स्थापना दिवस सम्पन्न

गायत्री महायज्ञ से भक्तिमय हुआ वातावरण

सुशासन में आमजन का चलना मुश्किल

निर्धनों के बीच वस्त्र वितरण

कॉलेज निरीक्षक को हटाने की मांग

दहियावां क्लब हुआ विजयी

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी

सीवान में करोड़ों की दवाएं बेकार

दस प्रधानाध्यापकों पर गिर सकती है गाज

गोपालगंज में सूखी पड़ी नहरें

प्रस्तुति- शुभम रानी चौहान, मनीष कुमार कश्यप

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
Contact : 9386595926, 9334115955

कुल मिलाकर जिप अध्यक्ष मंजू देवी के ख़िलाफ़ चारों तरफ मामला बनता ही नज़र आ रहा है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

प्रभारी कुलपति बहुत बिज़ी है

सुनील सौरभ

बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में ख्यात मगध विवि की स्थिति पिछले डेढ़ वर्षों से अराजक बनी हुई है. तीन वर्षों तक मगध विवि के कुलपति रहने के बाद पांडेय के हटते ही यहां का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक माहौल शिथिल होने लगा. प्रो. अरविंद कुमार कुलपति बनकर आए लेकिन वह राजभवन, बिहार सरकार के बीच झगड़े तथा पटना उच्च न्यायालय के आदेशों–निर्देशों के बीच एक साल तक फंसे रहे. अंतत: हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें हटना पड़ा. प्रभारी कुलपति के रूप में बी.एन. मंडल विवि मधेपुरा के कुलपति प्रो. अरुण कुमार को यहां का प्रभार मिला. तब से मगध विवि में अराजकता का माहौल और बढ़ गया है. मगध विवि का प्रभार मिलते ही अरुण कुमार यहां विशेष रुचि लेने लगे. लोगों को लगा मगध विवि में कुछ अच्छे कार्य होंगे. लेकिन सब बेकार साबित हुआ. हाई कोर्ट के आदेश से रद्द की गई प्राचार्य की बहाली को पुन: करने के आदेश के बाद प्रभारी कुलपति ने आनन–फानन में प्राचार्यों की बहाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी. सारी प्रक्रियाएं पूरी की गईं, लेकिन किसी कारणवश प्राचार्यों की बहाली नहीं हो सकी. बताया जाता है कि इसमें ढेर सारी अनियमितता की शिकायत मिलने पर बहाली को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. बताया जाता है कि मगध विवि में छात्रों से आने वाली बड़ी राशि को देखकर ही हर किसी कुलपति का मन डोल जाता है. बड़ी राशि को देखकर ही राशि को दूसरे मद में खर्च दिखाकर निकालने का प्रयास किया जाता है. मगध विवि के इतिहास में संभवत: पहली बार ऐसा हुआ कि परीक्षा विभाग के पास परीक्षा आयोजित करने के लिए राशि का अभाव हो गया. कारण बताया गया यहां की राशि को दूसरे मदों में खर्च कर देने के आदेश ने मगध विवि के परीक्षा विभाग के खजाने को ही खाली कर दिया. नतीजा हुआ कि परीक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजित करने में हाथ खड़े कर दिये. मज़ेदार बात तो यह है कि इस विवि के पटना स्थित शाखा कार्यालय में करोड़ों रुपये पड़े हैं, लेकिन यह राशि परीक्षा विभाग को नहीं दी जा रही है. जबकि इस राशि पर परीक्षा विभाग का ही अधिकार बनता है. वहीं दूसरी ओर मगध विवि के कुलसचिव को प्रतिदिन दस हजार रुपये ख़र्च करने के अधिकार पर भी प्रभारी कुलपति ने रोक लगा दी. फलत: प्रभारी कुलपति के न रहने पर रुटीन कार्य भी रुक सा गया है. प्रभारी कुलपति के इस आदेश से विवि कर्मियों का अधिकांश कार्य रुक गया है, जिससे अंदर ही अंदर आक्रोश पनप रहा है. लेकिन खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है. प्रभारी कुलपति महीने में कुछ दिन ही मगध विवि मुख्यालय आ पाते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को पटना में रहकर ही फाइल मंगवा कर निबटाते हैं. संचिकाएं कुलपति कार्यालय में जाकर अटक जा रही है या फिर डिस्कस लिखकर फाइल को अटका दिया जा रहा है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विवि कर्मियों को नौकरी नहीं मिल रही है. वहीं दूसरी ओर कुलसचिव के फ़र्ज़ी हस्ताक्षर से कॉलेजों में बहाली हो जा रही है. अंगीभूत कालेजों के प्राचार्य, बर्सर को किसी कारण निलंबित कर दिया जा रहा है, फिर इन्हें तुरंत निलंबन मुक्त भी कर दिया जा रहा है. इसमें भी डील की बात कही जा रही है. इसी प्रकार बी.एड. कॉलेजों के मान्यता के मामले में भी विवि संदेह के घेरे में है. कभी मान्यता मिल जाती है तो कभी रुक भी जाती हैं, जिससे कि बी.एड. कालेजों के संचालक विवि दौड़ें. छात्रों के भविष्य की चिंता विवि को नहीं नजर आती. बताया जाता है कि प्रभारी मुखिया के तानाशाही रवैए से मगध विवि में पूरी तरह अराजक माहौल कायम कर दिया है. फ़िलहाल मगध विवि में सभी कार्य अनिश्चित से हो गए हैं. मगध विवि की शान में चार–चांद लगाने वाली योजना कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी अधर में लटक गया है. इसके निर्माण से मगध विवि को प्रति वर्ष 1 करोड़ 60 लाख रुपया प्रति वर्ष मिलना था. एग्रीमेंट के रूप में 5 करोड़ रुपये मिलने तय थे. प्रभारी कुलपति को यहां के विकास से लगता है कोई मतलब ही नहीं है. पिछले छह महीने से मगध विवि के कुलपति के प्रभार के रूप में लेकर चल रहे अरुण कुमार ने मगध विवि की गरिमा को बढ़ाने का कोई यादगार कार्य नहीं किया है. हां यहां की आंतरिक राजनीति को सक्रिय जरूर कर दिया है जिससे मगध विवि खोखला होता जा है. इन सारी खामियों पर मगध विवि के प्रभारी कुलपति डॉ. अरुण कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो प्रभारी कुलपति यह कहते हुए बात करने से इनकार करते रहे कि बहुत थके हुए हैं या फिर मीटिंग कर रहे हैं. बाद में बात करेंगे. लेकिन उनसे बाद में भी बात नहीं हो सकी. कुल मिलाकर मामला भगवान भरोसे है.

feedback@chauthiduniya.com

संकट में ज़िला परिषद अध्यक्ष

मोतिहारी

जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व जिप अध्यक्ष श्रीमति देवी ने उप समितियों के गठन में सभी सामाज के लोगों को शामिल करने का आश्वासन दिया था और इसी शर्त पर उन्हें सर्वाधिक वोट भी मिले थे. पूर्वी चम्पारण ज़िले में आठ दलित व आठ मुस्लिम समाज से पार्षद चुने गये हैं और उप समितियों के गठन में उन्हें शामिल नही किया गया है.

ज़िला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. उप समितियों के गठन में दलितों व मुस्लिमों की हुई उपेक्षा का मामला अभी सुर्खियों में ही था और क़रीब तीन दर्जन पार्षद जिप अध्यक्ष श्रीमति देवी के ख़िलाफ़ गोलबन्द हुए थे तो दूसरी तरफ केसरिया के विधायक सचिंद्र सिंह ने ज़िला बीस सूत्री की बैठक में सोलर लाइट की खरीददारी में हुई गड़बड़ियों का मामला उठाकर जिप अध्यक्ष के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी. बताया जा रहा है कि जिला परिषद् अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व जिप अध्यक्ष श्रीमति देवी ने उप समितियों के गठन में सभी सामाज के लोगों को शामिल करने का आश्वासन दिया था और इसी शर्त पर उन्हें सर्वाधिक वोट भी मिले थे. पूर्वी चम्पारण ज़िले में आठ दलित व आठ मुस्लिम समाज से पार्षद चुने गये हैं और उप समितियों के गठन में उन्हें शामिल नही किया गया है. दलित व मुस्लिम समाज के पार्षदों की लड़ाई लड़ने वाले जदयू नेता अब्दुल हमीद कैप्टन ने बताया कि जिप अध्यक्ष श्रीमति देवी ने पार्षदों के साथ विश्वासघात किया है और उनकी उपेक्षा की है. स्थानीय होटल में लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए पार्षदों की बैठक भी हुई, जिसमें शारदा देवी, ज्ञान्ती देवी, रसिदा खातून, ज्योति सिंह, पूनम देवी, रूबैदा खातुन, रूही खातून, सगीरा खातून, शबनम खातून, गुडिया खातून व सुनील कुमार समेत करीब ढाई दर्जन पार्षद शामिल हुए और जिप अध्यक्ष द्वारा की गई गड़बड़ी के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया गया. उधर बीती 22 दिसम्बर को स्थानीय राधाकृष्णन भवन के सभागार में हुई जिला बीस सूत्री की बैठक में केसरिया के विधायक सचिंद्र सिंह ने घटिया सोलर की खरीददारी करने का मामला उठाया, जिसे प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने गंभीरता से लेते हुए ज़िलाधिकारी अभिजीत सिन्हा को जांच करने का निर्देश दिया. विधायक श्री सिंह ने सदन को अवगत कराया था कि ज़िले की सभी पंचायतों में घटिया सोलर लाइट लगाई गई है और उक्त लाइट लगने के साथ ही खराब हो गई. विधायक ने ज़िला परिषद की क्रय समिति को भी कटघेरे में खड़ा कर दिया और बताया कि लोकल कंपनी का सोलर लगाया गया है और अधिक राशि दर्शाई गई है. कुल मिलाकर जिप अध्यक्ष मंजू देवी के ख़िलाफ़ चारों तरफ मामला बनता ही नज़र आ रहा है. उधर, जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी ने उप समितियों के गठन में लगे आरोप को बे बुनियाद बताया है और कहा है कि योग्य पार्षदों को स्थान दिया गया है. सोलर लाइट के मामले में उन्होंने बताया कि कहीं कोई गड़बड़ी नही हुई है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी.

इन्तेजारुल हक
feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

We Impart:-
POST GRADUAGE COURSES:
MPT Master of Physiotherapy
MOT Master of Occupational Therapy
MPO Master of Prosthetic & Orthotic
MASLP Master of audiology speech & Language Pathology
BPT Bachelor of Physiotherapy
BOT Bachelor of Occupational Therapy
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
BASLP Bachelor of Audiology Speech & Language Pathology
BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
B.Ed. (Special Education)
B.Opht. Bachelor of Ophthalmology

मेधावी छात्र-छात्राओं के लिये निःशुल्क शिक्षा
बिहार प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संस्थान प्रबंधन ने अपने शैक्षणिक सत्र-२०१२-१३ में, सभी डिग्री पाठ्यक्रमों के तीन-तीन स्थानों के लिए (कुल २१) तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पाँच-पाँच स्थानों कुल ३० पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस हेतु आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तारीख ३१ जनवरी २०१२ तथा मेधा परीक्षा की तिथि १२ फरवरी निर्धारित की गई है।
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि ३१ जनवरी २०१२
मेधा परीक्षा १२ फरवरी २०१२
1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

DIPLOMA COURSES:
DPT Diploma in Physiotherapy
DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
DMLT Diploma in Medical Lab.
D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
DHM Diploma in Hospital Management
DOTA Diploma in Operation Theather Assistant
DECG Diploma in E.C.G.
certificate courses:
CMD Certificate in Medical Dressing
Foundation Course for Teachers in Disability

Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-and DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2
Eligibility:- For Post Graduate Courses- Degree in the same, 10+2 with science for under Grtaduate & diploma Courses For B.Ed. Degree in any Subjecty.

Registration for Admission into Academic session 2012-2013 going on.
फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email.iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org
डा.अनिल सुलभ निदेशक-प्रमुख

Triveni Infratech
Developing India...
Triveni Infratech
A COMPLETE TOWNSHIP.....
0.5 km From Booty More, Ranchi
READY TO SHIFT
ON GOING PROJECTS
TRIVENIPURAM
Upcoming Projects
Arunoday-Argora Ashok Ashram Road, Ranchi
Triveni Spring-Namkum, Khijri, Ranchi
Triveni Sun City - Sidrol, Ranchi - Tata Road, Ranchi
Triveni Twin City - Bokaro - Dhanbad Road, Bokaro
Triveni Enclave (Dhanbad)
READY TO SHIFT
Our Accomplishments

OM SHANTI TOWER	- Residential	- Old commissioner Compound
SHANTI NIKETAN	- Residential	- Burdhwan Copound, Lalpur
SUSHILA ENCLAVE	- Residential	- Harmu, Ranchi
ANAND BHAWAN	- Residential	- Bariatu Ranchi
BANWARI COMPLEX	- Res.&Commercial	- Upper Bazar, Ranchi
SRI KAUSHAL TOWERS	- Commercial	- Bariatu Ranchi
BRINDAVAN	- Residential	- Morabadi, Ranchi
BADSHAH PALACE	- Res.&Commercial	- Main Road, Ranchi
MADHUKAR REGENCY	- Res.&Commercial	- Shrahanand Road, Ranchi
SHANTI ENCLAVE	- Residential	- Ashok Nagar, Ranchi

EXCITING FACILITIES : * Playgound * Marriage Hall * Dispensary * Jogging Track * Modern Shopping* Garden
* 24 HRS. POWER & WATER FACILITY * ROUND-O-CLOCK SECURITIES * CHARMING ATMOSPHERE
Keshri Heights (Jamshedpur)
Triveni Infratech Pvt. Ltd.
"Divine House" Club Road, Ranchi-01 (jharkhand)
Contact : 91 - 9386852819, 9334714082,9835569900, 9386852791, 0651-2331860
Email : sritriveni@gmail.com, Website : www. triveniinfratech.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 16 जनवरी-22 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

राहुल गांधी

सिर्फ़ चुनाव प्रचार में आगे चल रहे हैं

कांग्रेस के युवराज प्रचार के मामले में तो अव्वल दिख रहे हैं, लेकिन उनकी अभी असली परीक्षा होना बाक़ी है. समाजवादी पार्टी गुटों में बंट गई, जो चाहता है उन पर दबाव बनाकर काम करवा लेता है. पार्टी में गुटबाज़ी चरम पर है, जिनको टिकट मिल गया है, वे भीतरघात से परेशान हैं, जिनको नहीं मिला वह बग़ावत पर उतारू हो गए हैं. पैसे और स्टार प्रचारकों की कमी भी सपा के आड़े आ रही है. सपा पांच साल से सत्ता से बाहर है, उसकी आय का स्त्रोत कोई रह नहीं गया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेता सड़क पर पैर रखने से कतराते हैं, तो बड़े नेता केंद्र की राजनीति में उलझे हैं. उसके सामने प्रचार करने वाले नेताओं की कमी आ गई है.

अजय कुमार

एक माह का समय बचा है, लेकिन चुनाव प्रचार में वो तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए. मात्र राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं, जो प्रचार के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं. कांग्रेस में राहुल के अलावा कोई दूसरा नेता मैदान में नहीं दिख रहा है. कांग्रेस के जो नेता प्रचार में दिखते भी हैं तो वे राहुल के साथ ही होते हैं. बसपा सुप्रीमो ने तो प्रचार अभियान अभी शुरू ही नहीं किया है, वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव प्रचार से अधिक मेल-मुलाक़ातों पर ज़ोर दे रहे हैं. प्रचार के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी की तरफ़ से मोर्चा संभाले हैं. उनका क्रांति रथ ख़ूब दौड़ा. भाजपा की बात की जाए तो पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता तो छोटी-छोटी सभाएं करते दिख जाते हैं, लेकिन पार्टी में आपसी तालमेल की कमी के कारण मतदाताओं का ध्यान वे उस हिसाब से अपनी तरफ़ नहीं खींच पा रहे हैं जैसा खींचना चाहिए. भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने अभी तक चुनाव की कमान नहीं संभाली है. कहा जा रहा है कि भाजपा की केंद्रीय टीम 20 जनवरी के बाद मोर्चा खोलेगी. इस बार एक और ख़ास बात दिखाई पड़ रही है, बसपा को छोड़कर किसी भी दल ने अपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है.

कांग्रेस के युवराज प्रचार के मामले में तो अव्वल दिख रहे हैं, लेकिन उनकी अभी असली परीक्षा होना बाक़ी है. अभी तो वह तीर चला रहे हैं और विरोधी नेता निशाना बन रहे हैं, लेकिन जब राहुल की मुख़ालफ़त करने वाले दिग्गज नेता चुनावी जंग में अपने तरकश से तीर निकालेंगे तब राहुल की असली परीक्षा होगी. तब पता चलेगा कि वह कितने पानी में हैं. वैसे भी राहुल की विरोधाभासी बातें लोगों की समझ में नहीं आ रही है. वह लगातार जनसभाएं कर रहे हैं. पांच साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देने की बात भी करते हैं, लेकिन साथ में यह भी जोड़ देते हैं कि वह वोट मांगने नहीं आए हैं, उन्हें तो प्रदेश की चिंता है. अब कोई उन्हें कैसे समझाए कि बिना वोट पाए वह अगर कुछ कर पाते तो अभी तक क्यों नहीं किया. वहीं जब बात आती है कांग्रेस के भ्रष्टाचार की तो वह अपनी आंखे बंद कर लेते हैं. लगता है कि कांग्रेस के युवराज बसपा की सत्ताजनित नाराज़गी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं. इसीलिए वह अन्य दलों के मुक़ाबले बसपा पर ज़ोरदार हमला कर रहे हैं. राहुल के लगातार हमलों से बसपा को बल मिल रहा है. उसका प्रचार अपने आप हो रहा है. वहीं कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी को बसपा सुप्रीमो पर निशाना साधना महंगा भी पड़ सकता है. ऐसी सोच कुछ राजनीतिक पंडितों की व्यर्थ नहीं है. दलितों को लुभाने के लिए उनके घरों पर दस्तक देने वाले राहुल गांधी जाने अनजाने मायावती पर हमला करके दलित समाज से दूरी ही बढ़ा रहे हैं. आज भी दलितों के बीच मायावती की छवि रहनुमाओं जैसी है. दलित उन्हें अपना मसीहा मानते हैं. मायावती पर हमलावर युवराज को समझना चाहिए कि समय रहते उन्होंने अपना घर दुरुस्त नहीं किया तो उनका मिशन 2012 अधूरा रह सकता है. कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में असंतुष्टों का हंगामा आम होता जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, कांग्रेस बचाओ के नारें लिखी तख्तियां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रांगण में लहराई जाती हों तो विरोध के स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. यह सब तब हो रहा है, जब राहुल गांधी कई बार ऐसे विरोध-प्रदर्शन करने वालों को नसीहत दे चुके हैं. बहरहाल, राहुल गांधी के बसपा पर हमले की बात की जाए तो कांग्रेस के युवराज ऐसा करके एक तरह से बसपा की चुनावी रणनीति को ही अमली जामा पहना रहे हैं. बसपा जानती है कि उसे असली ख़तरा कांग्रेस से नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी से है. वह सोची-समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को आगे दिखाकर सपा की कमर तोड़ने का काम कर रही है. राहुल बसपा सरकार पर भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा आरोप गंभीरता से नहीं लगा रहे हैं, यह बसपा के लिए फ़ायदे का सौदा है.

बसपा जानती है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा राहुल उठा तो रहे हैं, लेकिन जब उनकी ही सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है तो फिर बसपा को ही अकेले दोषी कैसे क़रार दिया जा सकता है. एक तथ्य और भी है. देर से ही सही मुख्यमंत्री मायावती तो भ्रष्टाचार में फंसे अपने मंत्रियों को धड़ाधड़ हटा रही हैं, विधायकों के टिकट काट रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भ्रष्ट मंत्रियों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं. भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनका जवाब राहुल गांधी को देर-सवेर देना ही होगा. कांग्रेस का भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लचीला रुख़ और लोकसभा तथा राज्यसभा में कथित रूप से मज़बूत लोकपाल के नाम पर नौटंकीबाज़ी लोगों के गले नहीं उतर रही है.

जहां तक बात सपा की है, तो सपा भी इस बात से अनजान नहीं है कि वह कांग्रेस के चलते मुख्य मुक़ाबले में होते हुए भी मुक़ाबले से दूर दिखाई दे रही है. राहुल गांधी के कारण समाजवादी पार्टी को बेहद नुक़सान हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना मुंह सिले हुए है. उसका सारा ध्यान चुनाव के बाद की तस्वीर पर लगा हुआ है. इसका नुक़सान उसे उठाना पड़ सकता है. सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के युवराज की तेज़ी पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि बसपा और कांग्रेस मिले हुए हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए वह बसपा से लड़ाई का नाटक कर रहे हैं. वैसे राहुल के अलावा भी सपा की दुश्वारियां कम नहीं हैं. कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण का कार्ड खेलकर सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है. तो दूसरी तरफ़ नेताजी की पकड़ पार्टी पर ढीली क्या पड़ी, पार्टी गुटों में बंट गई, जो चाहता है उन पर दबाव बनाकर काम करवा लेता है. पार्टी में गुटबाज़ी चरम पर है, जिनको टिकट मिल गया है, वे भीतरघात से परेशान हैं, जिनको नहीं मिला वह बग़ावत पर उतारू हो गए हैं. पैसे और स्टार प्रचारकों की कमी भी सपा के आड़े आ रही है. सपा पांच साल से सत्ता से बाहर है, उसकी आय का स्त्रोत कोई रह नहीं गया है. पैसे की तंगी ने पार्टी को प्रचार के मामले में पीछे कर दिया है. बसपा और कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है. बसपा की प्रदेश में तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार है, वहीं भाजपा अपने ख़र्चों को पूरा करने के लिए भाजपा शासित राज्यों से मदद ले रही है.

भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव का माहौल अनुकूल है. मतदाता उसकी तरफ़ उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है, लेकिन भाजपा के नेता हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. पार्टी के प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेता सड़क पर पैर रखने से कतराते हैं, तो बड़े नेता केंद्र की राजनीति में उलझे हैं. भाजपा ने राजनाथ सिंह को छोड़कर क़रीब-क़रीब अपने सभी दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है. इसके चलते भाजपा के सामने प्रचार करने वाले नेताओं की कमी आ गई है. भाजपा के दिग्गज पार्टी का भला करने से अधिक अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं. वैसे, भाजपा भी नए-नए प्रयोग कर रही है. वह बदली रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने की बात कर रही है. चुनाव प्रबंधन के लिए पार्टी ने छह प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर को केंद्र बनाया है. इन केंद्रों को हाईटेक संचार सुविधाओं से लैस किया जाएगा. लखनऊ की बजाय उक्त केंद्रों से पार्टी चुनाव अभियान चलाएगी. इसके अलावा पार्टी बूथ स्तर पर मज़बूती के लिए भी प्रयासरत है. 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों के लिए पार्टी विजय वाहिनी सेना का गठन करने के अभियान में लगी है. भीतरघात को रोकने के लिए दूसरे राज्यों से भी कार्यकर्ताओं और नेताओं का सहारा लिया जा रहा है. मिशन 2012 के लिए सभी बिगुल बजाए हुए हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि भाजपा द्वारा सभी सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद जनवरी के अंत तक स्थिति कुछ साफ़ हो पाएगी. तब तक सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक भी मैदान में होंगे. बसपा-सपा-कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई को कुकुरमुत्तों की तरह उग आए छोटे-छोटे दल और भी रोमांचक बना सकते हैं.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

प्रियंका अमेठी-रायबरेली में प्रचार करेंगी

अमेठी और रायबरेली में फिर प्रियंका दिखाई देंगी. लोकसभा चुनाव के समय जहां प्रियंका ने मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार किया था, वहीं अब वह अपनी मां और भाई की साख़ बचाने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं में वोट मांगेंगी. सीधे तौर पर वह सोनिया-राहुल के लिए वोट नहीं मांगेंगी, लेकिन इसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फ़ायदा सोनिया और राहुल को होगा. कांग्रेस की तरफ़ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की बढ़ती मांग के मद्देनज़र कांग्रेस आलाकमान को यह फ़ैसला लेना पड़ रहा है. प्रियंका के प्रचार किए जाने की ख़बर की पुष्टि इस बात से भी होती है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कार पास जारी करने के लिए उनका भी नाम दिया है. कार पास जारी करने के लिए जिन नेताओं के नाम चुनाव आयोग को दिए हैं, उनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आदि के साथ प्रियंका का नाम भी शामिल है. इस ख़बर से उन कांग्रेसी उम्मीदवारों में ख़ुशी की लहर दोड़ गई है जो उन्हें अपने यहां बुलाने के लिए आलाकमान को लिख चुके थे. कांग्रेस के भीतरखाने से जो ख़बर आ रही है, उसके अनुसार प्रियंका को प्रचार में उतारने का फ़ैसला काफ़ी सोच-समझ कर लिया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यदि प्रियंका विधानसभा चुनाव में प्रचार करने का फ़ैसला करती हैं तो ऐन मौक़े पर व्यवस्था करने में कोई दिक्क़त न आए. प्रियंका अपनी मां सोनिया और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी में आने वाले विधानसभा सीटों के लिए प्रचार में उतर सकती हैं. उनके लिए प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से प्रचार का आग्रह आ रहा है. प्रियंका को चुनाव मैदान मे उतारने का जो कारण बताया जा रहा है उसके अनुसार सोनिया-राहुल की व्यस्तता है. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी प्रदेश भर में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त रहेंगे और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी पार्टी के प्रचार के लिए वक़्त देना पड़ेगा. ऐसे में वह अपने संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे. किसी अनहोनी से बचने के लिए ही प्रियंका को अमेठी और रायबरेली में पार्टी के प्रचार की कमान सौंपी जा रही है. वैसे भी उनका इन क्षेत्रों में आना जाना रहता है, जिससे यहां वह काफ़ी लोकप्रिय हैं. प्रियंका के प्रचार अभियान में उतरने से अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की स्थिति में सुधार आ सकता है.

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

feedback@chauthiduniya.com

रामवीर ने लोकायुक्त पर हाथरस की एक जनसभा के दौरान जमकर ज़हर उगला. मंत्रीजी ख़फ़ा थे कि उनके ख़िलाफ़ लोकायुक्त जांच क्यों कर रहे हैं, जबकि वह लोकायुक्त के मित्र हैं.

आजकल 13 माल एवेन्यू में मायावती का अधिकांश समय गुजरता है. वह चुनाव की सभी तैयारियों का संचालन यहीं से कर रही हैं.

भाजपा-बसपा में होगी कांटे की टक्कर

इस बार के चुनाव में भाजपा ने जगन गर्ग पर विश्वास जताया है तो बसपा ने राजेश अग्रवाल को टिकट दिया है. कांग्रेस ने सुमित विभव और सपा ने अभिनव शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है. परिसीमन के बाद इस प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर लगभग साढ़े तीन लाख मतदाता हैं.

श्रीनिवास गुप्ता

आगरा उत्तरी विधानसभा क्षेत्र भाजपा के दावेदारी के लिए जाना जाता है. पिछले सात विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा ने जीत का परचम लहराया है. नए परिसीमन के बाद इस विधानसभा क्षेत्र से शहर के कई इलाक़े जुड़ गए हैं. कई ऐसे इलाक़े भी है जिन्हें इस क्षेत्र से अलग करके दूसरे विधानसभा में जोड़ दिया गया है. परिसीमन से पूर्व उत्तरी विधानसभा का नाम आगरा पूर्वी हुआ करता था. वैश्य जाति बहुल सीट पर यहां पिछले 22 सालों से भाजपा का क़ब्ज़ा रह चुका है. यहां से भाजपा के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश विकल चार बार चुने जा चुके हैं. निर्वतमान विधायक जगन गर्ग तीन बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तरी क्षेत्र से मुख्य संघर्ष भाजपा और बसपा के बीच हुआ था.

भाजपा विधायक जगन गर्ग को लगभग पचास हज़ार वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रही बसपा को लगभग पैंतीस हज़ार मत मिल पाए थे. कांग्रेस तीसरे व सपा चौथे स्थान पर रही थी. इस बार भाजपा ने जगन गर्ग पर विश्वास जताया है. बसपा ने राजेश अग्रवाल को टिकट दिया है. कांग्रेस ने सुमित विभव और सपा ने अभिनव शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है. नए परिसीमन के बाद इस प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर लगभग साढ़े तीन लाख मतदाता है. शहर का मुख्य व्यापारिक क्षेत्र होने के कारण यह सीट महत्वपूर्ण मानी जाती है. व्यापारियों के पुरजोर समर्थन से पिछले दो दशक से भी ज़्यादा समय से भाजपा का क़ब्ज़ा रहा है. इस दौरान पिछले सात विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी ही जीतते आ रहे हैं. इस बार भी भाजपा को पहले स्थान पर माना जा रहा है. बसपा के राजेश अग्रवाल को वैश्य होने का लाभ मिल सकता है, बसपा का वोट उन्हें मिलना तय है. फिलहाल भाजपा को सीधी टक्कर वही दे रहे हैं. कांग्रेस से टिकट पाए सुमित विभव भी वैश्य जाति का वोट खींचने में सक्षम होंगे. कांग्रेस पार्टी का लाभ उन्हे मिलेगा फिर भी वे पहले दो स्थानों पर मतदाताओं की पंसद नहीं बन पा रहे हैं. समाजवादी पार्टी ने युवा प्रत्याशी अभिनव शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है. भाजपा, बसपा और कांग्रेस से वैश्य प्रत्याशी होने के कारण इस जाति के वोट बंट सकते हैं. इसका लाभ सपा प्रत्याशी को मिल सकता है, यही सोचकर सपा ने उन्हें टिकट दिया है. लेकिन उत्तरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी पिछले कई विधानसभा चुनावो में तीसरे और चौथे स्थान से आगे नहीं बढ़ सकी. इस बार भी सपा का चौथे स्थान पर ही रहने की संभावना है. भाजपा के जगन प्रसाद गर्ग को इस बार आगरा दक्षिण सीट से लड़ाया जा रहा था.

आख़िरकार, पार्टी आलाकमान ने फ़ैसला किया कि वे उत्तरी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे. इस सीट पर भाजपा और बसपा के बीच मतों का अंतर अपेक्षाकृत कम होता जा रहा है. परिसीमन के बाद भाजपा के वोट बढ़ गए हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वोट बसपा के बढ़े हैं. पिछले पांच सालों में बसपा ने व्यापारियों में अपनी अच्छी छवि बना ली है. बसपा के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल से क्षेत्रिय जनता काफ़ी कम परिचित है. इसका लाभ भाजपा प्रत्याशी को अवश्य मिल सकता है. भाजपा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसके प्रत्याशी की छवि अच्छी है. उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में व्यापारी वर्ग में पंजाबियों की संख्या तादाद में है. यह वर्ग भाजपा प्रत्याशी से ज़्यादा खुश नही हैं. उनकी संख्या लगभग 20 हज़ार है. पंजाबी वोट साफ़तौर पर सपा और कांग्रेस के साथ नहीं है. भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए उसके पास बसपा ही विकल्प है. अगर ऐसा हो गया तो उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा नया इतिहास बनाने में कामयाब भी हो सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

नदवा की चौखट पर पहुंची सियासत

दारूल उलूम नदवातुल उलेमा(नदवा)को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है. क़रीब 113 वर्ष का इतिहस समेटे नदवा कॉलेज की शोहरत सात समुद्र पार तक फैली है. पिछले दिनों यहां के एक प्रोफेसर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी के सदस्य मौलाना सलमान नदवी ने यहां की परंपरा से हटकर राजनीतिक चोला पहन लिया था. वह आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में कूदने वाले इत्तेहाद फ्रंट के अध्यक्ष बन गए थे. इसकी घोषणा लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेस के माध्यम से की गई. नदवा के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब यहां के किसी शिक्षक ने राजनीतिक दल की कमान संभाली हो. अभी तक नदवा का आशीर्वाद लेने के लिए विभिन्न दलों के नेता इसकी चौखट पर आकर माथा टेकते थे, लेकिन अब नदवा का ही एक शिक्षक वोटों के लिए मतदाताओं की चौखट पर दस्तक देगा. नदवा के प्रबंधतंत्र ने सलमान नदवी के राजनीति में प्रवेश करने को उनकी निजी बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की. कहा जा रहा है कि नदवा के राजनीतिक दल की कमान संभालने से नदवा का राजनीतिकरण नहीं होगा, लेकिन हक़ीक़त यही है कि राजनीति नदवा के भीतर भले ही न पहुंच पाए, लेकिन चौखट तक तो पहुंच ही गई है. चुनावी मौसम में छोटे-छोटे दलों से मिलकर बने इत्तेहाद फ्रंट में पीस पार्टी, अपना दल, बुंदेलखंड कांग्रेस, इंडियन नेशनल लीग, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी, ऑल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जय भारत समानता पार्टी, भारतीय लोकहित पार्टी, कौमी एकता दल, भारतीय जनसेवा पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, लेबर पार्टी व जनसत्ता पार्टी शामिल है. नए मोर्चे के नेताओं ने दावा किया है कि वह मुस्लिम वोटों के बुनियादी आधार के साथ महा-दलित व अति-पिछडा की वंचित बिरादरियों को गोलबंद करेंगे. हालांकि मोर्चे में शामिल दलों के बीच सीटों के तालमेल पर अभी कसमकस बनी हुई है. इसलिए सीटों के बंटवारे के फ़ार्मूले का कोई ख़ुलासा भी नहीं हुआ. मोटे तौर पर यह तय हुआ है. मोर्चा सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेगा और जिस क्षेत्र में जो दल या पार्टी ताक़तवर होगी, वहां की सीट पर बंटवारे में उसका दावा मजबूत रहेगा. अगर विवाद हुआ तो इसका निपटारा मौलाना सलमान नदवी अपने स्तर पर इलाक़े से मंगवाई गई रिपोर्ट के आधार पर करेंगे, जो सभी को मंज़ूर होगा. पीस पार्टी के डॉ. अयूब, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, इंडियन नेशनल लीग के मो. सुलेमान, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के अरशद खां, इंडियन जस्टिस पार्टी के डॉ. उदितराज, ऑल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हंसराज गौड़, जय भारत समानता पार्टी के हेमंत कुशवाहा, भारतीय लोकहित पार्टी के राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, कौमी एकता दल के अफजाल अंसारी, भारतीय जनसेवा पार्टी के मुर्तजा अली सिद्दीकी, भारतीय समाज पार्टी के ओमप्रकाश राजभर, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के ठाकुर भगवान सिंह, लेबर पार्टी के डॉ. भरत सिंह बघेल और जनसत्ता पार्टी के डॉ. कर्ण सिंह मोर्चे को ताक़त प्रदान कर रहे हैं. पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ अयूब ने दावा किया कि इस बार यूपी में यही मोर्चा सरकार बनाने जा रहा है. 13 छोटे-छोटे दलों से मिलकर गठित इत्तेहाद फ्रंट मुस्लिम मतों को फ्रंट से जोड़ने में कितना कामयाब होगा इसका अंदाज़ा अभी लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ्रंट के गठन से सपा-बसपा और कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है. इत्तेहाद फ्रंट के गठन से सपा, बसपा और कांग्रेस को करारा झटका लगा है जो अपने-अपने हिसाब से मुसलमानों को रिझाने में जुटे थे. मुसलमानों को रिझाने के लिए कांग्रेस गठबंधन की केंद्र सरकार ने मुसलमानों के आरक्षण की पासा फेंक चुकी है. कांग्रेस आरक्षण की घोषणा करके चुनावी लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, वहीं सपा और बसपा प्रदेश के मुस्लिम समुदाय को यह संदेश देने में लगे हैं कि उनके दबाव में केंद्र सकरार ने यह फ़ैसला लिया है. इत्तेहाद फ्रंट के गठन से इन तीनों ही दलों को करारा झटका लगा है हालांकि सपा और कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि मुस्लिम समुदाय बसपा सरकार से असंतुष्ट होने के कारण उन्हीं को अपना समर्थन देगा.

अपना दल की सुप्रिया पटेल का स्वागत

फ्रंट के गठन के बाद सपा व कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी बढ़ने के कई कारण दिखाई दे रहे हैं. फ्रंट में शामिल अधिकांश छोटे दलों का जनाधार मुस्लिम वोट बैंक पर ही आधरित है. मुस्लिम धर्मगुरू सैय्यद हुसैनी सलमान नदवी को मोर्चे का नेतृत्व सौंपकर फ्रंट के नेताओं ने यह भी संदेश देने का प्रयास किया कि फ्रंट का गठन मुस्लिम समस्याओं के निराकरण के लिए ही किया गया है. मौलाना धर्मगुरू के फ्रंट से जुड़ने से मुस्लिम समुदाय के एक बड़े तबके का समर्थन फ्रंट को मिलना लगभग तय माना जा रहा है. वैसे सत्ता के गलियारों में चर्चा यह भी छिड़ी है बसपा के इशारे पर उक्त फ्रंट का गठन किया गया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को नुक़सान पहुंचाया जा सके. फ्रंट के गठन को मायावती की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि हाल ही में फ्रंट शामिल एक घटक दल के अध्यक्ष व उनके कुछ पदाधिकारी पंचम तल पर बैठने वाले एक अधिकारी से मिले थे और उन्हें बताया गया था कि बसपा को इससे फ़ायदा होगा. फ्रंट के गठन से सपा और कांग्रेस की ओर बढ़े मुस्लिम मतों के रूझान को रोकने में सफ़लता मिलेगी जिसका सीधा लाभ बसपा को मिलेगा. कहा तो यहां तक जाता है कि इस बात की जानकारी बहनजी को भी दी गई. उन्हें यह सुझाव काफ़ी फ़ायदेमंद लगा और उन्होंने इसके गठन के साथ ही सहयोग का भी आश्वासन भी दिया.

इत्तेहाद फ्रंट के गठन के समय इससे जुड़े नेताओं ने हालांकि काफ़ी बढ़ चढ़कर वायदे किए, लेकिन जनता उसके वायदों पर कितना विश्वास करेगी इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि छोटे दलों द्वारा गठित फ्रंट का अनुभव प्रदेश की जनता के लिए कभी अच्छा नहीं रहा. जिस तरह से इत्तेहाद फ्रंट का गठन किया गया है उसी तर्ज पर 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व में जनमोर्चा का गठन किया था. सांसद राजबब्बर को जनमोर्चा का संयोजक नियुक्त किया गया था. इस मोर्चे ने अपनी ताक़त दिखाने के लिए लखनऊ में विशाल रैली का भी आयोजन किया था जिसमें जनमोर्चा से जुड़े सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. इस समय रैली में जुटी भीड़ को देखकर चौतरफा कहा जाने लगा कि सचमुच यह रैली सत्ता परितर्वन की रैली साबित होगी. लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर टिकट बंटवारे को लेकर मोर्चे में बिखराव शुरू हो गया. छोटे छोटे दलों के नेताओं ने जिस तरह से टिकटों के बंटवारे में अपनी शर्त रखी वह किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए मानना संभव नहीं था. फलस्वरूप मोर्चा बिखर गया और सभी दल अलग-अलग चुनाव मैदान में उतरे. इस चुनाव में सिर्फ़ जनमोर्चा को एक सीट मिली बाक़ी दल अपना खाता खोलने में भी सफ़ल नहीं हो सके. बात मौजूदा हालात की कि जाए तो इत्तेहाद फ्रंट के गठन से कुछ माह पूर्व भी छोटे दलों की सक्रियता देखने को मिली थी. तब चौधरी अजित सिंह और पीस पार्टी के डॉ. अयूब आदि ने एक सियासी कुनबा जोड़ा था. कहा गया कि वह लोग ग़ैर भाजपा-बसपा दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे. अजित ने इस कांग्रेस से हाथ मिलाकर तोड़ दिया तो पीस पार्टी, अपना दल और बुंदेलखंड कांग्रेस ने कुछ और छोटे दलों जनसंघर्ष मोर्चा, उलेमा काउंसिल लोकतांत्रिक समाज पार्टी, जस्टिस सच्चर की सोशलिस्ट पार्टी को साथ लेकर मोर्चा संभाल लिया. यह मोर्चा कुछ हफ्ते भी नहीं चल पाया. पीस पार्टी और अपना दल लखनऊ में इत्तेहाद फ्रंट का हिस्सा बन गए. अब बचे दल माकपा की तरफ़ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं. उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष आमिर रुश्दी मुस्लिम वोटों के सहारे पूर्वांचल के ज़िलों आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी आदि क्षेत्रों में अपना जनाधार मजबूत करने में लगे हैं. रुश्दी को नदवा के प्रोफेसर सलमान नदवी का पीस पार्टी से हाथ मिलाना रास नहीं आ रहा है. उधर पसमांदा मुस्लिम समाज के नेतागण सपा से दोस्ती के चक्कर में हैं. हालांकि वह कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में उभर रहे राजनीतिक दलों में पीस पार्टी ने अपनी अल पहचान बना ली है. पिछले वर्ष हुए तीन विधानसभा उपचुनाव में पीस पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. पीस पार्टी की तरफ़ मतदाताओं के रूझान को देखते हुए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब को मुसलमानों का नेता माना जाने लगा. गठजोड़ के सहारे सत्ता के क़रीब पहुंचने को लालयित डॉ. अयूब ने इत्तेहाद फ्रंट बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इत्तेहाद फ्रंट में डॉ. अयूब का जिस तरह से महिमामंडन किया गया, इससे स्पष्ट है कि इस फ्रंट की निगाह मुस्लिम मतों पर है. इत्तेहाद फ्रंट को लेकर कौमी एकता दल के संस्थापक तथा मऊ के निर्दलीय विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की सक्रियता से भी स्पष्ट है कि इत्तेहाद फ्रंट सिर्फ़ मुस्लिम मतों के सहारे आगे बढ़ना चाहता है. इस सच्चाई से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पूर्वांचल में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अयूब, कौमी एकता दल के संस्थापक अफजाल अंसारी व उनके छोटे भाई एवं निर्दलीय विधायक मुख्तार अंसारी का मुस्लिम बिरादरी पर काफ़ी असर है. वह मुस्लिम मतों को काफ़ी हद तक इस फ्रंट से जोड़ने में सफ़ल हो सकते हैं हालांकि बुंदेलखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजा बुंदेला की गैर हाजिरी ने फ्रंट में दरार के संकेत भी दे दिए. राजा बुंदेला कहते हैं कि वह पीस पार्टी के साथ तो बने रहना चाहते हैं लेकिन इत्तेहाद फ्रंट से वह दूरी बनाए हुए हैं. अगर पीस पार्टी से बात बिगड़ गई तो बुंदेला अकेले चुनाव लड़ने की बात से भी इंकार नहीं करते हैं.

अजय कुमार, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रोफेसर के फ़ैसले से हैरान नदवा

इत्तेहाद फ्रंट एक ऐसा मोर्चा है, जिसमें दूल्हे का ही पता नहीं हैं, लेकिन निकाह की तैयारी पूरी हो गई है. फ्रंट एक तरफ़ सत्ता का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ़ मुखिया के बारे में गोलमोल बातें. आधी-अधूरी तैयारी के साथ आनन-फानन में बना इत्तेहाद फ्रंट की कमान जिन हाथों में दी गई हैं, वह उसका कितना भला कर पाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी. जिस नदवा की चौखट पर तमाम सियासी दलों के दिग्गज मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए दस्तक देते हैं, उसी नदवा कॉलेज के प्रोफेसर ख़ुद ही सियासी मैदान में कूद पड़े. वह भी तब जबकि ख़ुद नदवा कभी सियासी गतिविधियों से नहीं जुड़ा. नदवा [illegible] प्रबंधक) मौलाना सै. राबे हसनी नदवी के भी रिश्तेदार होने के नाते भी मौलाना नदवी के इस क़दम पर सवाल उठने लगे हैं. नदवा के कई शिक्षक भी इससे खुश नहीं है. नदवा के प्रिंसीपल मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं कि नदवा के शिक्षकों की आचार संहिता किसी को राजनीतिक सक्रियता की छूट नहीं देता. हो सकता है कि उन्होंने मोहतमिम मौलाना राबे हसन नदवी साहब से इजाजत ले ली हो? वह नहीं चाहते हैं कि यह परंपरा आगे बढ़े इस लिए वह जल्द बैठक बुलाकर नदवा का नज़रिया स्पष्ट करने की बात कहते हैं.

इत्तेहाद फ्रंट में जुटे नेता (बांए से) मो. सुलेमान, अरशद खां, डॉ. अयूब, उदित राज, अनुप्रिया पटेल, मौलाना सलमान नदवी, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, ठाकुर भगवान सिंह.

चुनावी हलचल

नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी में शामिल

हरदोई ज़िले के प्रभारी नेता बसपा के राज्यसभा के सांसद नरेश अग्रवाल ने दो दिनों की कसमकस के बाद अपना पाला बदलते हुए सपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया. [illegible] अग्रवाल ने गूढ़ शब्दों में टिप्पणी की थी कि बेटे का टिकट काटना या देना बहनजी का काम है. मैं राज्य सभा में बसपा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. इस टिप्पणी के बाद सांसद के चुप्पी साधने से ज़िले के अन्य विधानसभा प्रत्याशियों के बीच खलबली मच गई. सभी कुछ न कुछ अनुमान लगा रहे हैं. जो प्रत्याशी विधानसभा पहुंचने के सपने संजोये हुए थे, उस पर तुशारापात होता दिखने लगा. बसपा में उनकी उम्मीदवारी से सभी सीटों पर सपा हारी थी. बहरहाल राजनीतिक गलियारों में नरेश के बेटे की उम्मीदवारी को लेकर ज़िले के राजनीतिक गलियारों में जो खलबली मची थी. यह चर्चा चल रही है कि अब नितिन अग्रवाल और राजेश्वरी को सपा से टिकट मिलना तय हो गया है. इस बार सपा और बसपा के बीच ज़िले में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है.

पर्दानशीनों के लिए महिला मतदान अधिकारी

विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने मतदाता की हर सुविधा का ख्याल रखा है, वह चाहे पुरुष हो या महिला. सामाजिक शिष्टाचार से पेश आ रहे चुनाव आयोग ने पर्दानशीन महिलाओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए ख़ास इंतजाम करने की योजना बनाई है. चुनाव आयोग ने 2002 और 2007 में महिला मतदाताओं के प्रतिशत में गिरावट पर गौर किया है. 2002 के चुनाव में महिला मतदान 50.25 प्रतिशत था, वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में प्रतिशत घटकर 41.92 पर पहुंच गया. इस बारे में आयोग का मानना है कि महिलाओं के लिए मतदेय स्थलों पर विशेष सुविधा मुहैया कराई जाएगी. जिससे महिला मतदान बढ़ेगा. आयोग ने साफ़ किया कि ऐसे क्षेत्र में जहां एक ही भवन अथवा परिसर में दो मतदान केंद्र हैं, वहां एक को महिला व दूसरे को पुरुष के लिए आरक्षित किया जाएगा. ख़ासतौर से इन मतदानस्थलों को ख़ास ध्यान रखा जाएगा, जहां पर्दानशीनों की संख्या ज़्यादा होगी. वहीं एक पुरुष मतदाता के बाद दो महिलाओं को मतदान केंद्र में जाने की इजाजत होगी. इससे समय की बचत होगी. महिलाओं की पहचान के लिए हर पोलिंग बूथ पर महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी.

आयोग की हाईटेक संचार सेवा

चुनाव आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अपनी तैयारियों में दूर संचार सेवाओं का जाल बिछाने का कार्य भी शुरू कर दिया हैं. उसने बीएसएनएल से टोल फ्री फोन सेवा के लिए छह अन्य फोन कनेक्शन लिए हैं. चाक चौबंद व्यवस्था के लिए कलेक्ट्रेट में छह फोन लाइनों के साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-1800--950 सेवा संचालित कर रखी है. जिससे शिकायतों का निस्तारण 24 घंटों में आयोग कर सकेगा. डीएम अनिल सागर ने राजकीय पॉलीटेक्निक के स्ट्रांग रूम, अभिकर्ताओं के बैठने के स्थान, मतमगणना कार्य में लगे वाहनों की पार्किंग का निरीक्षण किया. वहीं जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्यों के लिए प्रभारी व सह प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है. मतदान टोलियों के गठन एवं प्रशिक्षण व्यवस्था, ईवीएम प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर उपलब्ध कराने आदि कार्मिक कार्यों के प्रभारी अपर ज़िलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अब्दुल समद रहेंगे. ज़िला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी, ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह तथा ज़िला सूचना विज्ञान अधिकारी अबुबकर को सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

BSNL Connecting India

अवैध शराब पर शिकंजा

प्रदेश में गांव-गांव फैले शराब व्यवसाय पर इस बार चुनाव आयोग दख़ल दे रहा है. आयोग की अवैध शराब पर पूरी नज़र है. उसने अवैध शराब पर बिक्री करने वालों की धर पकड़ शुरू कर दी है. इसके पहले चुनाव आयोग ने बैंकों पर भी नज़र रखने का निर्णय लिया है. जहां से एक लाख से ऊपर राशि निकालने पर बैंक से पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है. वहीं अवैध शराब व्यवसायियों पर शिकंजा कस दिया है. चुनाव आयोग का मानना है कि राज्य में अवैध शराब कारोबारी अपना सिर न उठा सके इसके पहले ही उन्हें दबोच लिया जाए. इसके मद्देनज़र आयोग ने अवैध शराब की बिक्री को रोकने और इस धंधे में लगे लोगों की धरपकड़ के लिए राज्य में विशेष चुनाव अभियान चला रखा है. हाल ही दिल्ली से तस्करी कर लाई जा रही चार टाटा सूमो से 3 हज़ार बोतल शराब गाजियाबाद में बरामद हुई है. मेरठ, मुजफ्फरनगर, और महराजगंज में दो दर्जन से अधिक शराब बनाने वाली भट्ठियों पर छापा मारा गया है. जिसमें कई ड्रम देशी शराब बरामद हुई. मध्य प्रदेश से लाई जा रही क़रीब दस लाख रुपये की अंग्रेजी एवं देशी शराब बरामद की गई. नेपाल से शराब लाते हुए चार लोगों को पकड़ा गया. नेपाल के बड़े गिरोह चुनाव के दरम्यान सक्रिय रहते हैं. जो करोड़ों की शराब यूपी में खपाते हैं. हालांकि हर ज़िले में अवैध शराब के कारोबारी सक्रिय है. बहरहाल चुनाव आते ही अवैध शराब व्यवसायियों की पौबारह हो जाती है. चुनाव में मांग कई गुना बढ़ जाती है. अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है. प्रत्याशी वोट के लालच में पियक्कड़ों मदिरा पान कराने से गुरेज नहीं बरतते. बशर्ते उन्हें जीत हासिल हो.

दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो

मंत्रीपद के साथ हेडमास्टरी का वेतन भी लेते रहे

बसपा सरकार में लघु उद्योग मंत्री चंद्रदेव राम यादव एक साथ सरकार से दो-दो पदों का वेतन उठा रहे हैं. एक शिकायत के आधार पर जब मंत्रीजी की पेशी लोकायुक्त के दरबार में हुई तो उन्होंने सच सच बता दिया कि उन्होंने दो पदों का लाभ उठाया है. मंत्रिपद के साथ-साथ उन्होंने हेडमास्टरी का भी वेतन लिया है. इसके लिए उन्हें लोकायुक्त से क्षमा मांगनी पड़ी, वहीं मंत्री ने इस अवधि का हेडमास्टरी का वेतन सरकार को लौटाने की बात कही. इस बात का ख़ुलासा तब हुआ जब आजमगढ़ के इंद्रासन सिंह, जय प्रकाश सिंह व राधेश्याम सिंह ने मिलकर लघु उद्योगमंत्री चंद्रदेव के ख़िलाफ़ शिकायती पत्र लोकायुक्त को भेजा कि मंत्री चंद्रदेव राम यादव, मंत्री पद के साथ हेडमास्टरी का वेतन आहरण कर रहे हैं. लोकायुक्त ने फौरन मंत्रीजी को तलब कर लिया. 26 दिसंबर को मंत्री चंद्रदेव राम यादव लिखित रूप से अपनी सफ़ाई देने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे. लोकायुक्त के समक्ष प्रधानाध्यापक पद का वेतन लेने की बात कुबूल की. वहीं अनजाने में हुई इस भूल का सुधार करने कर प्रधानाध्यापक पद का इस अवधि का वेतन सरकार को वापस करने की बात कहते हुए क्षमा मांगी. उन्होंने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2006 से हेडमास्टर का वेतन ले रहे हैं. विधिक जानकारी न होने की वजह से उनसे यह चूक हुई है. परिवार में कई शस्त्रों की लाइसेंस होने के बारे में बताया कि मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है. सुरक्षा के लिए लाइसेंस आवश्यक था. रही बात संपत्ति की तो मुझे इसके लिए कुछ समय दिया जाए, जिससे अपनी संपत्ति के बारे में स्पष्ट कर सकूं. बहरहाल मंत्रीजी की इस भूल का समय रहते पता चल गया वरना चुनाव के बाद बात को कौन तवज्जो देता और कौन पैसा वापस करता. हैरत की बात यह है कि जिस व्यक्ति को जनता अपने हित के लिए चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजती है, वह लोग ऐसे कार्य कर बैठते हैं और पकड़े जाने पर भूल मान कर बच जाते हैं.

बसपा प्रत्याशी के गोदाम में हज़ारों कुंतल अवैध खाद्यान्न

बसपा अपनी बहुमतवाली पूरी पारी खेल चुकी है. उसके कई मंत्री और विधायक कुछ बर्ख़ास्त किए जा चुके हैं वहीं कई दर्जन मंत्री लोकायुक्त की जांच में फंसे हुए है. कई ऐसे मंत्री है, जिनकी कई बार शिकायतें आई हैं. जो बचे हैं उन्हें शंका की नज़रों से देखा जा रहा है. इससे पार्टी के अंदरूनी हालात अच्छे नज़र नहीं दिख रहे हैं. अब बची खुची साख़ अब बसपा प्रत्याशियों के कारण गवां रही है. चुनाव आयोग की निगाहें बसपा प्रत्याशियों पर भी टिकी हुई हैं. वहीं प्रशासन भी चुस्त दुरूस्त दिख रहा है. कुशीनगर ज़िले की फाजिलनगर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी कलीमुद्दीन के एक गोदाम में हज़ारों कुंतल अनाज बरामद हुआ. जिसे अवैध रूप से रखा गया था. कसया के उपजिलाधिकारी के अनुसार बसपा प्रत्याशी के गोदाम पर छापा मारकर खाद्य विभाग ने 36 हज़ार बोरा चावल, 7 सौ बोरा गेहूं बरामद किया. बसपा प्रत्याशी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. यह गोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित जंगल के बीच बना हुआ है.

–दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो

बीएसएफ चुनाव से दूर रहे

एक तरफ़ उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार को बीएसएफ पर बेहद भरोसा है, वहीं दूसरी तरफ़ विपक्ष बीएसएफ से सहमा हुआ है. वह लगातार चुनाव आयोग से मांग कर रहा है कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हों इसके लिए ज़रूरी है कि बीएसएफ को किनारे किया जाए. सत्ता के गलियारों में बीएसएफ को लेकर ख़ूब चुटकी ली जा रही है. दरअसल, विपक्ष ने डीजी बृजलाल, कैबिनेट सचिव शशांक शेखर और प्रमुख सचिव गृह की तिकड़ी को बीएसएफ (बी फॉर बृजलाल, एस फॉर शशांक शेखर और एफ फॉर फतेह बहादुर) का उपनाम दे रखा है. आचार संहिता लागू होते ही विपक्ष ने आयोग से उक्त तिकड़ी को हटाने की मांग की थी, जिस पर आयोग ने सरकार को आदेश भी दिया था कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े इन अधिकारियों को हटा दिया जाए जिन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव में हटाया गया था. सरकार ने इन अधिकारियों को हटाने की बजाए उनके नाम और वर्तमान तैनाती की स्थिति बताते हुए सूची निर्वाचन आयोग को भेज दी थी. इस सूची में मुख्य रूप से फतेह बहादुर सहित दर्जन भर से अधिक पुलिस डीआई/एसएसपी/एसपी अधिकारियों के भी नाम शामिल है. फतेह बहादुर का हटना तय माना जा रहा है, शशांक शेखर और डीआईजी बृजलाल पर आयोग की पैनी नज़र है. बृजलाल का विरोध सिर्फ़ समाजवादी पार्टी की तरफ़ से किया जा रहा है, लेकिन इस विरोध के पीछे कई बातें हैं.

–चौथी दुनिया, लखनऊ ब्यूरो

बसपा के अमर्यादित मंत्री

नेताओं को तो आपस में लड़ते-झगड़ते अक्सर देखा जा सकता है, लेकिन किसी सरकार का मंत्री अगर अपनी मर्यादा भूल कर लोकायुक्त जैसे पद पर बैठे न्यायमूर्ति पर सिर्फ़ इसलिए उंगली उठाए क्योंकि लोकायुक्त मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार को तेजी से उजागर कर रहा है तो आश्चर्य होता है. यह कारनामा करने वाले नेताजी हैं मायावती सरकार के क़रीबी ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय, जिन्होंने एक ही झटके में लोकायुक्त पर कई गंभीर आरोप लगा दिए. एक तरफ़ लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा की रिपोर्ट के आधार पर कई मंत्रियों की लालबत्ती छीनी जा चुकी हैं, वहीं उनके ही मंत्रीजी को लोकायुक्त में खोंट ही खोंट नज़र आ रहा है. रामवीर ने लोकायुक्त पर हाथरस की एक जनसभा के दौरान जमकर ज़हर उगला. मंत्रीजी खफा थे कि उनके ख़िलाफ़ लोकायुक्त जांच क्यों कर रहे हैं, जबकि वह लोकायुक्त के मित्र हैं. मंत्री उपाध्याय ने जनसभा में जो कुछ कहा वह काफ़ी शर्मसार करने वाला था. उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री किरीट सोमैय्या की शिकायत पर लोकायुक्त ने उनके ख़िलाफ़ जांच की लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि लोकायुक्त से उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं होते तो वह उच्चतम न्यायालय जाकर उन्हें हटवा देते.

रामवीर उपाध्याय

एनके मेहरोत्रा

मंत्रीजी का उक्त बयान चंद मिनटों में सुर्ख़ियों में आ गया. मंत्री जी को अपनी ग़लती समझ में भी आई, लेकिन तब तक पानी सिर के ऊपर निकल चुका था. उनकी बातें मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी थी. चुनाव आयोग ने भी मंत्रीजी के बयान को संज्ञान में ले लिया था.

बहरहाल, उत्तर प्रदेश के मंत्री की टिप्पणी न केवल उनकी हताशा बताती है, बल्कि राजनीति के गिरते स्तर की तरफ़ भी संकेत करती है, जिसमें जनप्रतिनिधि सिर्फ़ इसलिए अपने को बड़ा मानने की भूल करते हैं क्योंकि वह चुन कर आए हैं. यही वजह है कि लोकायुक्त का व्यवहार जनप्रतिनिधियों को रास नहीं आता है. केंद्र में कांग्रेस के नेता अन्ना हजारे को ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा बताते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ही काम रामवीर उपाध्याय जैसे नेता करते हैं. न अन्ना के ऊपर आरोप लगाने वालों के ख़िलाफ़ केंद्र सरकार या कांग्रेस कोई क़दम उठाती है, न ही मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्री से यह पूछने की ज़रूरत समझती हैं कि वह ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं. रामवीर उपाध्याय का यह कहना कि वह लोकायुक्त से ज़्यादा क़ानून की जानकारी रखते हैं, यह हास्यास्पद नहीं तो ओछापन ज़रूर है. उपाध्याय की बातों का निहितार्थ निकाला जाए तो ऐसा लगता है कि वह लोकायुक्त के सख्त रवैये से काफ़ी नाराज़ हैं. लोकायुक्त की गाज अधिकांश मामालों में मायावती सरकार के मंत्रियों पर ही गिर रही है. पहले तो उपाध्याय चुप रहे लेकिन जब जांच का केंद्र वह बने तो अपना आपा खो बैठे. बताते चलें कि लोकायुक्त उर्जामंत्री के ख़िलाफ़ दो शिकायतों की जांच कर रहे हैं, इसमें एक मामला बिजली वितरण के निजीकरण से जुड़ा हुआ है तो दूसरा सामान ख़रीद से संबंधित है. मंत्रीजी पर आरोप है कि बिजली वितरण का ठेका मनचाही कंपनियों को देने और सामान ख़रीद में काफ़ी अनियमितता बरती गई थी. उपाध्याय को समझना चाहिए कि अगर उनका दामन पाक-साफ़ होगा तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और अगर दोषी हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए. हो सकता है कि उपाध्याय को लग रहा हो कि लोकायुक्त के कारण क़रीब आधा दर्जन मंत्रियों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ चुकी है, कहीं उनको भी न छोड़नी पड़ जाए. वैसे ऐसा भी नहीं है कि मंत्रीजी को हक़ीक़त पता न हो, पहले भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे हैं. आय से अधिक संपत्ति, विधायक क्षेत्रीय निधि के दुरूपयोग, हाथरस में प्रखंड विकास समिति के एक सदस्य का अपहरण और एक आपराधिक मामले में जांच को प्रभावित करने के भी उनपर आरोप हैं. पहले इन आरोपों की जांच लोकायुक्त कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका लंबित होने के कारण उन्होंने इससे संबंधित जांच पिछले साल नवंबर में रोक दी.

मुख्यमंत्री मायावती के मंत्री ने लोकायुक्त के ख़िलाफ़ जैसे ही मोर्चा खोला, चुनाव आयोग ने तुरंत इसे संज्ञान में लिया, वहीं विपक्ष को बैठे-बिठाए बसपा पर हमला बोलने का मौक़ा मिल गया. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक कहते हैं कि जंगल राज जैसा माहौल हो गया है, जिस सरकार के मंत्री लोकायुक्त तक को धमकाते हों उसके रहते चुनाव निष्पक्ष कैसे संपन्न हो सकता है. यह बात चुनाव आयोग को गंभीरता से सोचना चाहिए. मुख्यमंत्री मायावती को अपने मंत्रियों को समझाना चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ मुंह खोलने से पहले सौ बार सोच लें. लोकायुक्त की सख्ती से कई राज्यों की सरकारें परेशान हैं, यही वजह है कई राज्य सरकारें अभी तक लोकायुक्त की तैनाती नहीं कर पाए हैं, लेकिन लोकायुक्त के बारे में एक मंत्री के सरेआम बेहद अपमानजनक बयान देने की यह घटना अपवाद है. उपाध्याय का लोकायुक्त के ऊपर हमला बताता है कि मायावती सरकार लोकायुक्त की तेजी से परेशान हैं. उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के ख़िलाफ़ जांच असर दिखाने लगी है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण नौकरशाहों से संबंधित अनेक शिकायतों की जांच अधूरी पड़ी है.

नौकरशाह इन मंत्रियों के ख़िलाफ़ तो लोकायुक्त को सामग्री उपलब्ध करा देते हैं जिनके अधीनस्थ वह काम करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट लॉबी अपने आप को बड़ी चतुराई से बचा ले जाती है. अब समय आ गया है कि लोकायुक्त से संबंधित ऐसा क़ानून लाया जाए जिसमें लोकायुक्त के पास जांच का अधिकार और पूरा तंत्र मौजूद हो. बहरहाल, लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने उपाध्याय के बयान पर अपनी मर्यादा नहीं खोई मंत्री के आरोपों के जवाब में लोकायुक्त ने इतना ही कहा कि यह टिप्पणी विधानसभा चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए की गई है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि क़ानून में ऐसा प्रावधान है जिसके तहत वह इस प्रकरण की शिकायत मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं लेकिन उपाध्याय इससे लाभान्वित होना चाहते होंगे इसलिए कार्रवाई करने का अभी कोई विचार नहीं है. लोकायुक्त ने कहा कि उपाध्याय का यह बयान व्यक्तिगत नहीं बल्कि पार्टी की कार्रवाई है और जनता चुनाव में उपाध्याय को सबक सिखाएगी.

अजय कुमार, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ANAND SOUTH CITY (JARAULI PHASE-2)
VIPIN DUBEY
Contact No. 9415041293, 9335959682

तेरह के फेर में मायावती

मुख्यमंत्री मायावती बौद्ध धर्म को मानती हैं. अन्य धर्मों का भी वह सम्मान करती हैं, लेकिन मंदिर-मस्जिद गुरुद्वारों में कभी नहीं जाती. [illegible]

बसपा सुप्रीमो मायावती स्वभाव से धाकड़ और निडर होकर चुनौतियों का सामना करने वाली महिला लगती हैं, लेकिन अंधविश्वास उनके भी भीतर घर किए हुए है. इसी अंधविश्वास ने उन्हें एक बार फिर पांच कालीदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास से आधा किलोमीटर की दूरी पर (उन्हें पूर्व मुख्यमंत्रियों कोटे से आवंटित सरकारी आवास) 13 माल एवेन्यू की तरफ़ जाने को मजबूर कर दिया है.

बसपा सुप्रीमो मायावती स्वभाव से धाकड़ और निडर होकर चुनौतियों का सामना करने वाली महिला लगती हैं, लेकिन अंधविश्वास उनके भी भीतर घर किए हुए है. इसी अंधविश्वास ने उन्हें एक बार फिर पांच कालीदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास से आधा किलोमीटर की दूरी पर (उन्हें पूर्व मुख्यमंत्रियों कोटे से आवंटित सरकारी आवास)13 माल एवेन्यू की जाने को मजबूर कर दिया हैं. मायावती का अधिकांश समय अब यहीं गुजरता है. वह चुनाव की सभी तैयारियों का संचालन यहीं से कर रही हैं. कारण 2007 के विधानसभा चुनाव में यहीं पर रहते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश की राजगद्दी मिली थी. 13 नंबर मायावती को इतना भाया की उन्होंने सिंहासन हासिल करने का दिन भी 13 मई 2007 चुना. इसे संयोग कहा जाए या कुछ और लेकिन हक़ीक़त यही है कि अबकी मायावती ने तमाम मुश्किलों का सामना किया हो लेकिन बहुमत को लेकर उन्हें कभी कोई आंख नहीं दिखा पाया. 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती के लिए उनका 13 नंबर बंगला कितना लकी रहेगा, यह देखने वाली बात होगी. वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मायावती अपने मंत्रिमंडल में जो सफ़ाई अभियान चलाए हुए हैं उसके पीछे भी उनका अंधविश्वास काम कर रहा है. उन्हें किसी ने बताया है कि कौन सा मंत्री उनके लिए शुभ है और किसे साथ लेकर चलने से उन्हें परेशानी हो सकती है. शुभ-अशुभ के चक्कर में फंसी मायावती सतीश मिश्र और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं को अपना बगलगीर बनाए हुए हैं. दावा किया जाता है कि इन दोनों की 2007 में बसपा को सत्तासीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी. ख़ासकर सतीश मिश्र का सोशल इंजीनियरिंग का फ़ार्मूला बसपा के लिए रामबाण जैसा रहा. उसे मायावती ने टोटके की तरह लिया और दोनों नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ती ही जा रही है, जबकि नसीमुद्दीन के ख़िलाफ़ भी वैसे ही आरोप लग रहे हैं जैसे आरोप में वह अपने कई मंत्रियों को हटा चुकी हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रभात के किडनी कारोबार में हरिशंकर भी बराबर का हिस्सेदार बन गया. प्रभात और हरिशंकर ने दो-तीन सालों में 40 से अधिक लोगों की किडनियां बेच दीं.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

राजनीतिक बिसात पर सज गए मोहरे

अवधेश प्रसाद | अभय सिंह | खब्बू तिवारी | जितेंद्र सिंह (बबलू) | मित्रसेन यादव | मुन्ना सिंह | लालू सिंह | पवन पांडे | किन्नर गुलशन बिंदू | रूश्दी मियान | रामचंद्र यादव

राकेश कुमार यादव

फ़ैज़ाबाद में अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता लल्लू सिंह विभिन्न दलों के लिए अजेय बने रहे. हर हाल में अपनी जीत पक्का करने लिए सभी दलों ने अधिकांशत: उन राजनीतिज्ञों को ही प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है जो या तो दल-बदलू है अथवा बाहुबली. अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी के रूप में किन्नर गुलशन बिंदु चुनाव में उतरा है. अयोध्या विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में आए व्यापारी नेता वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया है तो पीस पार्टी ने पूर्व में बसपाई रहे राजन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है. वहीं भाजपा ने अपने पुराने विधायक लल्लू सिंह पर ही जीत का विश्वास जताया है. इन सबके बीच समाजवादी पार्टी ने युवा तेजनरायन पांडे को उतारकर इस सीट को भारतीय जनता पार्टी से छीनने की कोशिश में है. केंद्रीय सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का दशकों से झंडा ढ़ो रहे राजेंद्र प्रताप सिंह भी इन सबके बीच नया इतिहास रचने को तैयार है.

अयोध्या के बाद गोसाईगंज विधानसभा जनपद की वह सीट है जिसपर कि दो जाने पहचाने बाहुबली आमने-सामने है, दोनों दल-बदल के माहिर हैं. इनमें से एक अभय सिंह अब समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं. वह अपना चुनाव प्रचार अभियान अभी जेल से ही संचालित कर रहे हैं, जबकि उन्हें टक्कर दे रहे बाहुबली इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतरे हैं. वहीं सीताराम निशाद ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मंत्रीपद का सुख भोगकर इस बार दल-बदल करके गोसाईगंज सीट को कांग्रेस की झोली में डालने की तैयारी में हैं. अभी तक भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य छोटे दलों के प्रत्याशियों के नाम पर इस क्षेत्र में कुछ ख़ास चर्चा में नहीं दिखता. सोहावल सुरक्षित सीट समाप्त करके नए परिसीमन में बनी बीकापुर विधानसभा सीट पर भी कांटे का मुक़ाबला होना तय माना जा रहा है. यहां से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर फुंकने के आरोपित जितेंद्र सिंह बब्लू जो बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित होने के बाद अब पीस पार्टी के टिकट से पुन: विधायक होने के दावेदार हैं, जेल से चुनाव प्रचार कर रहे हैं. दूसरी ओर जनपद में अपने 40 वर्षों की राजनीतिक यात्रा में दल-बदल का एक इतिहास साथ लिए पांच बार विधायक व दो बार सांसद रह चुके वयोवृद्ध मित्रसेन यादव भी साइकिल की सवारी पर विधानसभा तक पहुंचने का ख्वाब संजोए हैं, लेकिन दोनों के बीच कांग्रेस और लोकदल के समझौते से इस क्षेत्र के घोषित रालोद प्रत्याशी पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान भी इस बार विधानसभा पहुंचने की जुगत में लगे हैं. इन तीनों चर्चित प्रत्याशियों के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए युवा प्रत्याशी फ़िरोज़ खां उर्फ गब्बर को मैदान में उतारा है. भारतीय जनता पार्टी यहां एक उचित प्रत्याशी की तलाश में है, जो उसे यहां जीत दिला सके.

मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो पहले सामान्य हुआ करता था, अब नए परिसीमन में सुरक्षित कर दिया गया है. इस सीट से एक ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद अपनी जीत हासिल करने के लिए पूरी ताक़त झोंक रहे हैं तो उनके विरूद्ध बहुजन समाज पार्टी ने अपने सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए पवन कुमार को मैदान में उतारा है वहीं बहुजन समाज पार्टी से राजनीतिक शुरुआत करने वाले भोला भारती जो कि ज़िला पंचायत सदस्य भी हैं को कांग्रेस ने टिकट दिया है. भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में गए रामू प्रियदर्शी अपने पुराने घर में वापस आ गए हैं तो खुश करने के लिए भाजपा ने भी उन्हें टिकट दे दिया है.

रुदौली विधानसभा क्षेत्र भी नए परिसीमन और बाराबंकी जनपद से फ़ैज़ाबाद जनपद में शामिल होने के बाद सोहावल और मिल्कीपुर के आंशिक क्षेत्रों को अपने में समेटे इस बार चुनावी चर्चा में अहमियत पा रही है. यहां से समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने विधायक अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां को, बहुजन समाज पार्टी ने नए चेहरे शमशाद खां को मैदान में उतारा है. वहीं कई बार हार मुंह देख चुकी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रामचंद्र यादव जो कि अपने गुरु मित्रसेन यादव की तर्ज पर दल-बदल का नया इतिहास रच रहे हैं. अब वह टिकट के नाम पर ऐन चुनाव के वक्त बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. कुल मिलाकर जनपद की पांचों विधानसभा सीटों पर दल बदलुओं और बाहुबलियों के बीच ही रोचक चुनाव दिखने के आसार हैं, जबकि नए परिसीमन ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के चाबुक के नियंत्रण में चुनाव प्रचार करने में अभी से पसीने छूट रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

प्रमुख उम्मीदवार

गोशाईगंज- इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू (बसपा)
सीताराम निशाद (कांग्रेस).

बीकापुर - मित्रसेन यादव (सपा)
जितेंद्र सिंह बब्लू (पीस पार्टी)
फ़िरोज़ ख़ां गब्बर (बसपा)
मुन्ना सिंह चौहान (रालोद)
अयोध्या लल्लू सिंह (भाजपा)
तेजनरायन पांडेय पवन (सपा)
वेद प्रकाश गुप्ता (बसपा)
राजेंद्र प्रताप सिंह (कांग्रेस)
राजन मिश्रा (पीस पार्टी)

मिल्कीपुर (सु.)- अवधेश प्रसाद (सपा)
पवन कुमार (बसपा)
रामू प्रियदर्शी (भाजपा)
भोला भारती (कांग्रेस)

रुदौली - अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां (सपा)
शमशाद खां (बसपा)
रामचंद्र यादव (भाजपा)

2007 के चुनाव, कौन कितने पानी में

विधानसभा का नाम	प्रत्याशियों को प्राप्त मत
मिल्कीपुर आनंद सेन यादव (बसपा)	60,515 (विजेता)
राम चंद्र यादव (सपा)	51,136 (रनर)
मथुरा प्रसाद तिवारी (भाजपा)	14767 (तीसरा स्थान)
बीकापुर जितेंद्र सिंह बब्लू (बसपा)	52424 (विजेता)
सीताराम निशाद (सपा)	42201 (रनर)
सरिता सिंह (अपना दल)	39573 (तृतीय स्थान)
अयोध्या लल्लू सिंह (भाजपा)	58493 (विजेता)
इंद्र प्रताप तिवारी (सपा)	52752 (रनर)
अशोक कुमार तिवारी (बसपा)	29923 (तृतीय)
सोहावल अवधेश प्रसाद (सपा)	48624 (विजेता)
रामू प्रियदर्शी (बसपा)	38753 (रनर)
राम प्रसाद रसिक (रालोद)	34993 (तृतीय)
रुदौली अब्बास अली जैदी (सपा)	45388 (विजेता)
अशोक कुमार सिंह (बसपा)	41715 (रनर)
रामदेव आचार्य (भाजपा)	12169 (तृतीय)

किडनी गिरोह का काला कारनामा

पापी पेट क्या नहीं कराता. दो जून की रोटी जुटाने के चक्कर में इंसान कभी-कभी अपना ख़ून ही नहीं बल्कि अपने शरीर का अंग बेचकर अपनी जान जोखिम में डाल देता है. ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सरोजनी नगर पुलिस ने पकड़ा. जिसमें थोड़े से धन के लालच में 45 लोगों ने अपनी किडनिया बेंच डाली. पुलिस दलालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो एक बड़े किडनी गिरोह के काले कारनामों का ख़ुलासा हुआ. पांच साल पहले बस्ती ज़िले के लालगंज कस्बे के रहने वाले हरिशंकर की मुलाकात एक छुटभैये नेता से हो गई. अपनी चिकनी चुपड़ी बातें सुनाकर वह हरिशंकर को अपने साथ लखनऊ ले आया. चारबाग़ के नजदीक स्थित मवैया मोहल्ले में किराए के मकान में रखवाकर छुटभैये नेता ने उसे 1 हज़ार रुपए वेतन पर एक स्कूल में नौकरी दिला दी.

वह रायबरेली स्थित अस्पताल में किसी बिमार परिचित को अपना ख़ून देने गया. ख़ून कम पड़ा तो उसने ब्लडबैंक से 1500 रुपए प्रति यूनिट की दर से ख़ून ख़रीदा. उसका ब्लड बैंक वालों से अच्छा परिचय हो गया. फिर उसने ख़ून बेचने का धंधा शुरू कर दिया. वहीं उसकी मुलाकात प्रभात नाम के व्यक्ति से हुई. प्रभात किडनी के कारोबार से जुड़ा हुआ था. हरिशंकर को ख़ून की दलाली करते देख उसने समझ लिया कि यह व्यक्ति किडनी के कारोबार में इसका सहायक सिद्ध हो सकता है. प्रभात चंडीगढ़, मोहाली के अस्पतालों से जुड़ा था. प्रभात के किडनी कारोबार में हरिशंकर भी बराबर का हिस्सेदार बन गया. किडनी के धंधे में हरिशंकर ने प्रभात को भी मात दे दिया. प्रभात और हरिशंकर ने दो तीन-सालों में 40 से अधिक लोगों की किडनियां बेच दीं. हरिशंकर ने किडनी से मिले पैसे से ज़मीन ख़रीदा. पुलिस के मुताबिक अस्पताल ने किडनी देने वालों की वीडियाग्राफी कराई है. वीडियाग्राफी में डॉक्टर ने किडनी दानकर्ताओं से, आप किडनी क्यों देना चाहते है? आपका मरीज से क्या रिश्ता है? इत्यादि सवाल भी पूछे हैं. वीडियोग्राफी आशियाना पुलिस को मिल गई है. पुलिस ने इस तस्कर बिचौलिए वकील की भी तलाशी शुरू कर दी है.

कहते है कि वकील ही फर्ज़ी कागजात तैयार कराता था. इसके अलावा कमिश्नर के ऑफिस से अस्पताल का पत्र दबाकर अपर आयुक्त श्यामलाल के लेटर पैड पर जाली एनओसी फैक्स करता था. पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि जांच चल रही है. दोषी बच नहीं पाएंगे. जो ग़रीबों को फुसलाकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं. फिलहाल किडनी प्रत्यारोपण मामले में फर्जी रिश्तेदार बनकर घोटाला करने वाले इस संगीन मामले में मोहाली प्रशासन ने वहां के सीएमओ को सात दिन में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. सीएमओ ने मोहाली के सिल्वर ओक्स और शिवालिक अस्पताल की जांच अपने स्तर से शुरू कर रखी है. ख़ुद प्रशासन हैरत में कि सिल्वर ओक्स अस्पताल में सूर्या किडनी सेंटर किसकी शह पर चल रहा था, जबकि इसका बोर्ड अस्पताल के बाहर नहीं लगा है.

दर्शन शर्मा,लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

युवक कैसे बिके किडनी दलालों के हाथ

किडनी दलालों के हाथ फंसे लोगों में आलमबाग़ निवासी अभिषेक मुखर्जी, अनिल कुमार, तालकटोरा का पप्पू बाल्मीकि और कैंट का कल्लू भी है. उनका कहना है कि शराब के ठेकों पर किडनी गिरोह के सदस्य उनसे मिलते थे. रुपयों का लालच देकर किडनी निकाल लेते थे. भुक्त भोगी अनिल का कहना है कि किडनी निकलवाने के लिए उसे 45 हज़ार रुपये मिले लेकिन अब उसे काम करने में दिक्कत महसूस हो रहा है. ये चारों भुक्त भोगी 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के हैं.